Daily
THE PHOTON NEWS
सच के हक में...
द फोटोन न्यूज Published from Ranchi
Ranchi ●Saturday, 17January 2026 ●Year : 05 ●Issue : 05 ●Ranchi Edition ●Page : 12 ●Price : ₹3 ●www.thephotonnews.com E-Paper : epaper.thephotonnews.com

सुविचार

रूप-राशि पर गर्व न करना, जीवन ही नश्वर है। छवि के इसी शुभ्र उपवन में सर्वनाश का घर है।

-रामधारी सिंह 'दिनकर'

Suhana Khan Says She'd Rather Be Interesting Than...

SHARE

सेंसेक्स	:	83,570.35
निफ्टी	:	25,694.35

SARAFA

सोना	:	13,345.00
चांदी	:	310.00

(नोट : सोना 22 कैरेट प्रति ग्राम)

BRIEF NEWS

हजयात्रा के लिए पंजीकरण की बढ़ी अंतिम तिथि

NEW DELHI : हजयात्रा संबंधी प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 जनवरी कर दी गई है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने साफ किया है कि इसके बाद कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने हज यात्रियों से हज बुकिंग और अन्य कागजी प्रक्रिया 25 जनवरी 2026 तक पूरा कर लेने का अनुरोध किया है। हज यात्रियों को अपना वैध पासपोर्ट अपने चुने हुए एचजीओ (हज ग्रुप ऑर्गनाइजर) या संबंधित कार्यालय में जमा करने, नुसुक पोर्टल पर अपना पंजीकरण विवरण दर्ज करने को कहा गया है।

महिला ने बेटा-बेटी को जहर देकर खुद भी खाया, तीनों की मौत

SAHARANPUR : उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले के गागलहेड़ी थानाक्षेत्र में एक महिला मनीता ने कथित रूप से घरेलू विवाद के चलते अपनी छह वर्षीय बेटी नित्या और चार वर्षीय बेटे कार्तिकेय को जहर देने के बाद फिर खुद भी विष खा लिया, जिससे तीनों की मौत हो गई। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। मृत महिला के मायके वालों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि ससुराल में उनकी बेटी का सास-ससुर, जेठ और जेठानी उत्पीड़न करते थे। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

वेनेजुएला की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ने ट्रंप को भेंट किया पदक

WASHINGTON : वेनेजुएला में विपक्ष की नेता मारिया कोरिना मचाडो ने कहा कि उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक भेंट किया। मचाडो ने इससे पहले कई मौकों पर कहा था कि वह अपना नोबेल पुरस्कार ट्रंप को दे देंगी। उन्होंने 'व्हाइट हाउस' में अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात की। यह बैठक ऐसे समय में हुई, जब अमेरिका ने कुछ दिन पहले ही वेनेजुएला में सैन्य हमला कर उसके नेता निकोलस मादुरो को पकड़ने की कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर जारी एक तस्वीर में मचाडो 'ओवल ऑफिस' (राष्ट्रपति का कार्यालय) में ट्रंप के साथ खड़ी नजर आ रही हैं और ट्रंप के हाथ में नोबेल शांति पुरस्कार पदक है।

अब वैश्विक नेतृत्व पर ध्यान केंद्रित करें भारतीय स्टार्टअप : पीएम मोदी

NEW DELHI @ PTI : शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय स्टार्टअप से विनिर्माण, गहन प्रौद्योगिकी और वैश्विक नेतृत्व पर अधिक ध्यान देने का आह्वान करते हुए कहा कि 'स्टार्टअप इंडिया' का अगला दशक भारत को नवाचार के वैश्विक अग्रणी देशों की पंक्ति में खड़ा करने वाला होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने 'स्टार्टअप इंडिया' पहल की 10वीं वर्षगांठ पर भारत मंडपम' में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि स्टार्टअप भारत के आर्थिक और प्रौद्योगिकी भविष्य को आकार देने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप इंडिया पहल को एक क्रांति करार देते हुए कहा कि 2014 में जहां देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, वहीं आज यह संख्या दो लाख से अधिक हो चुकी है। इनमें से करीब 125 स्टार्टअप एक अरब डॉलर या उससे अधिक मूल्यांकन के साथ 'यूनिकॉर्न' दर्जा हासिल कर चुके हैं। मोदी ने कहा कि इसके साथ ही भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप परिवेश बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जोखिम लेने की प्रवृत्ति को पहले हतोत्साहित किया जाता था, लेकिन अब वह मुख्यधारा में आ गई है और स्टार्टअप रोजगार सृजन, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने स्टार्टअप संस्थापकों एवं उद्यमियों से कहा, सरकार आपके हर प्रयास में आपके साथ है। मुझे आपकी क्षमता पर पूरा भरोसा है। आपका साहस, आत्मविश्वास और नवाचार भारत के भविष्य को आकार दे रहे हैं। मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों ने भारत की उद्यमशील क्षमताओं को साबित किया है और अब लक्ष्य यह होना चाहिए कि अगले दशक में भारत नए स्टार्टअप रुझानों और प्रौद्योगिकियों में विश्व का नेतृत्व करे।

- नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम को प्रधानमंत्री ने किया संबोधित
- आर्थिक और प्रौद्योगिकी भविष्य को आकार देने में अहम भूमिका निभा रहे स्टार्टअप
- दो लाख में करीब 125 स्टार्टअप एक अरब डॉलर या उससे अधिक मूल्यांकन के साथ हासिल कर चुके यूनिकॉर्न का दर्जा

महिलाओं की भूमिका अहम

प्रधानमंत्री ने कहा कि 'स्टार्टअप इंडिया' की रफ्तार लगातार तेज हो रही है। कई यूनिकॉर्न कंपनियां अब अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लेकर आ रही हैं और बड़े पैमाने पर रोजगार भी सृजित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मझोले और छोटे शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के युवा भी स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, जो देश में उद्यमिता के विस्तार को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि आज 45 प्रतिशत से अधिक मान्यता-प्राप्त स्टार्टअप में महिला निदेशक या भागीदार हैं। इसके अलावा महिलाओं की अगुवाई वाले स्टार्टअप को मिलने वाले वित्तपोषण के मामले में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा परिवेश बन चुका है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने रक्षा विनिर्माण, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का भी उल्लेख किया, जहां नीतिगत सुधारों और नवाचार पर भरोसे ने स्टार्टअप के लिए नए अवसर खोले हैं।

साल 2016 में शुरू हुआ था मिशन : बता दें कि 'स्टार्टअप इंडिया' मिशन की शुरूआत 16 जनवरी, 2016 को हुई थी। इसका उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना, उद्यमिता को प्रोत्साहित करना और रोजगार देने वालों की नई पीढ़ी तैयार करना है। कृत्रिम मेधा (एआई) पर सरकार की पहल का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जो देश एआई क्रांति में आगे रहेगा, उसे उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इंडिया एआई मिशन के तहत एआई विकास से जुड़ी उच्च कंप्यूटिंग लागत की चुनौती से निपटने के लिए 38,000 से अधिक जीपीयू जोड़े गए हैं।

परिश्रम के साथ साहस और जोखिम उठाने की क्षमता

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय प्रतिभाओं द्वारा भारतीय सर्वरों पर स्वदेशी एआई के विकास पर भी जोर दिया जा रहा है। इसी तरह सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और हरित हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में भी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, बीते दशक में डिजिटल और सेवा क्षेत्र के स्टार्टअप में अच्छा काम हुआ है।

पेयजल घोटाला : झारखंड हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने का दिया आदेश

ईडी के अधिकारियों के खिलाफ जांच नहीं करेगी रांची पुलिस

15 जनवरी को ऑफिस पहुंची पुलिस, दो अधिकारियों से की थी पूछताछ

जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हुई मामले की सुनवाई

PHOTON NEWS RANCHI : शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने रांची पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय की याचिका (ईडी) पर सुनवाई की। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने पेयजल घोटाले में संतोष कुमार द्वारा एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई एफआईआर के आधार पर ईडी अधिकारियों के खिलाफ पुलिस जांच पर रोक लगा दी। प्राथमिति को रद्द करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी ने इस मामले में केंद्रीय गृह सचिव को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया। साथ ही ईडी कार्यालय की सुरक्षा सीआईएफ या बीएसएफ किसी अर्धसैनिक बल को सौंपने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) राकेश रंजन को भी ईडी कार्यालय की उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि यदि ईडी कार्यालय और उसके अधिकारियों की सुरक्षा में कोई चूक होती है, तो इसके लिए रांची के एसएसपी सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। मामले में अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी।

- संतोष कुमार ने एयरपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी मारपीट की प्राथमिकी
- केंद्रीय गृह सचिव को पक्षकार बनाने का दिया गया निर्देश
- ईडी कार्यालय की सुरक्षा सीआईएफ या बीएसएफ को सौंपने का मिला ऑर्डर
- एसएसपी को भी ईडी कार्यालय की सुनिश्चित करनी होगी उचित सुरक्षा, 9 फरवरी को अगली हियरिंग

घोटाले की जांच को प्रभावित करने का दबाव

आज की सुनवाई के दौरान ईडी ने अदालत को अवगत कराया कि पेयजल घोटाले की जांच के दौरान कई बड़े अधिकारियों की संलिप्तता से जुड़े अहम साक्ष्य सामने आए हैं। ईडी का आरोप है कि संतोष कुमार की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी का उद्देश्य घोटाले की जांच को प्रभावित करना और दबाव बनाना है।

12 जनवरी को दर्ज कराई गई थी एफआईआर

गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दो अधिकारियों पर मारपीट के आरोपों की जांच करने रांची पुलिस की टीम गुरुवार सुबह ईडी ऑफिस पहुंची थी। सदर और सिटी डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ईडी के सहायक निदेशक प्रतीक और सहायक शुभम से पूछताछ की थे। ई-साक्ष्य एकत्र किए थे। जांच एजेंसी के दोनों अधिकारियों के खिलाफ पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, हटिया योजना (डोरंडा) के क्लर्क संतोष कुमार ने 12 जनवरी को एयरपोर्ट थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले को लेकर ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है।

स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत मृदुल कुमार से मिले सीएम हेमंत

PHOTON NEWS RANCHI : स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत मृदुल कुमार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में मुलाकात की। मुख्यमंत्री को उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। बता दें कि झारखंड राज्य के 25 वर्ष पूरे होने के बाद यह पहला आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल है जो दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाग ले रहा है। दावोस में झारखंड की भागीदारी 'प्रकृति के साथ सामंजस्य में विकास' विषय पर आधारित है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सतत विकास, विश्वास और दीर्घकालिक आर्थिक परिवर्तन पर केंद्रित उद्देश्य से मेल खाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और यूके की यात्रा के क्रम में विश्व स्तर पर ऊर्जा क्षेत्र के अग्रणी निवेशकों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं और ऊर्जा के क्षेत्र में नीति-निर्माण करने वाले संस्थानों के साथ झारखंड राज्य का संवाद कायम होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल प्राकृतिक स्रोतों से बनाई जाने वाली ऊर्जा, ग्रिड आधुनिकीकरण, ऊर्जा भंडारण, स्वच्छ ईंधन और औद्योगिक डीकाबोर्नाइजेशन से जुड़े निवेश अवसरों को रेखांकित करेगा। दावोस और यूनाइटेड किंगडम में अपनी सहभागिता के माध्यम से झारखंड एक मॉडल प्रस्तुत कर रहा है जो विश्वसनीय, समावेशी और वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक है।

झारखंड में प्राकृतिक स्रोतों से उत्पादित की जाने वाली ऊर्जा की व्यापक संभावना है। यहां के प्रचुर प्राकृतिक संसाधन राज्य को एनर्जी ट्रांजिशन की दिशा में अग्रणी बनाएंगे। प्रतिनिधिमंडल बताएगा कि भारत ने जो नेट-जीरो टारगेट और ग्रीन इकोनॉमी की दिशा में दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाने का जो संकल्प लिया है उसे झारखंड दोहराएगा। झारखण्ड ह्लप्रकृति के साथ सामंजस्य में विकासह्व की बात को अपने इस पहल से पुख्ता भी करेगा। यह दृष्टिकोण न सिर्फ भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं में झारखंड की ऐतिहासिक भूमिका को रेखांकित करता है, बल्कि एक टिकाऊ वैश्विक भविष्य के प्रति राज्य की जिम्मेदारी को भी दर्शाता है।

- ग्रीन इकोनॉमी की दिशा में दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाने को झारखंड तैयार
- भविष्य के ऊर्जा स्रोतों को अपनाने के लिए अग्रसर है राज्य

विजन 2050 के अनुरूप आगे बढ़ रहा प्रदेश

युवा झारखंड विजन 2050 के लक्ष्य को साधने के लिए राज्य के समृद्ध विरासत के साथ तेजी से बदलते वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य के अनुरूप स्वयं को ढाल रहा है। जैसे-जैसे विश्व स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों की ओर अग्रसर हो रहा है, वैसे-वैसे झारखंड एक संतुलित मार्ग अपना रहा है। एक ऐसा मार्ग जो ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और रोजगार सृजन को सुनिश्चित करते हुए नवीकरणीय एवं कम-कार्बन ऊर्जा के विस्तार को बढ़ावा देता है। झारखंड सरकार का मानना है कि प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादित ऊर्जा न्यायसंगत और समावेशी होनी चाहिए।

झारखंड पुलिस के 26 डीएसपी की सेवा संपुष्ट, गृह विभाग का नोटिफिकेशन जारी

PHOTON NEWS RANCHI : राज्य सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, झारखंड राज्य पुलिस सेवा के 26 परीक्ष्यमान डीएसपी की सेवा को 25 जुलाई 2025 की तिथि से आधिकारिक रूप से संपुष्ट कर दिया गया है। यह निर्णय झारखंड राज्य पुलिस सेवा नियमावली, 2012 के प्रावधानों के तहत लिया गया है।

- राज्य पुलिस सेवा नियमावली 2012 के प्रावधानों के तहत लिया गया निर्णय
- 25 जुलाई 2025 की तिथि से आधिकारिक रूप से सेवा की मानी जाएगी संपुष्टि

लिस्ट में शामिल हैं ये अधिकारी दिवाकर कुमार, दूसरु बाण सिंह, विनीत कुमार किंडो, चिरंजीव मंडल, रोहित साव, अकरम रजा, प्रशांत कुमार-2, अमरेंद्र कुमार, अर्चना स्मृति खलखो, प्रदीप कुमार-3, सुनील कुमार सिंह, पूजा कुमारी, कैलाश प्रसाद महतो, नीलम कुजूर, प्रदीप साव, पूजा कुमारी (अन्य), राजीव रंजन, राजेश यादव, कुमार विनोद, प्रदीप कुमार-2, रामप्रवेश कुमार, प्रशांत कुमार-1, चंद्रशेखर, अजय आर्यन, आकाश भारद्वाज व अमित रविदास।

कोर्ट ने दिया था सरेंडर का ऑर्डर शराब घोटाले का आरोपी नवीन फरार

- 8 जनवरी को एसीबी ने गोवा के एक स्पा सेंटर से किया था गिरफ्तार
- 5 दिनों की ट्रांजिट बेल के बाद करना था सरेंडर

PHOTON NEWS RANCHI : झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा गिरफ्तार किए गए नवीन केडिया ने अपनी ट्रांजिट बेल की शर्तों को दरकिनार कर कोर्ट के आदेश को ना मानते हुए फरार हो गया। गौरतलब है कि नवीन केडिया को एसीबी ने 8 जनवरी 2026 को गोवा के एक स्पा सेंटर से पकड़ा था। गिरफ्तारी के बाद उसे पणजी (गोवा) की अदालत में पेश किया गया। जहां कोर्ट ने उसे 5 दिनों की ट्रांजिट बेल दी है, ताकि वह छत्तीसगढ़ वापस जा सके और उसके बाद रांची में एसीबी के समक्ष सरेंडर कर सके। लेकिन, वह तय तिथि बीत जाने के बाद भी एसीबी के सामने उपस्थित नहीं हुआ, जिसके बाद अब एसीबी ने नवीन केडिया की गिरफ्तारी के लिए प्रयास शुरू कर दिया है।

बड़ी मुहिम सैन्य कूटनीति का विस्तार करने में जुट चुकी हैं तीनों सेनाएं

दुनिया के कई देशों में भारतीय डिफेंस विंग खुलने का रास्ता साफ

PHOTON NEWS, RESEARCH DESK : आज की दुनिया में देशों के बीच में राजनयिक संबंधों के नए-नए आयाम उभर कर सामने आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में हर स्तर पर भारत नए सिरे से पहल करते हुए आगे बढ़ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बदलते भू-रणनीतिक हालात में सैन्य कूटनीति का बढ़ता महत्व कई अर्थों में और बढ़ गया है। इसे देखते हुए भारत ने दुनिया भर में अपने डिफेंस विंग की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। दुनिया के सामने आज की सच्चाई यह है कि भारत अब युद्ध उपकरणों के आयातक की सीमा पार कर निर्यातक की श्रेणी में पहुंच चुका है। दर्जनों देशों में भारत में निर्मित युद्ध उपकरणों का निर्यात पिछले कुछ वर्षों में शुरू हो चुका है। मार्च 2026 तक 30 हजार करोड़ का निर्यात करने का लक्ष्य रखा गया है। सेना की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, साल 2024 तक कुल 45 देशों में भारत के डिफेंस विंग थे। साल 2025 के अंत तक यह संख्या बढ़कर 52 हो गई है। अगले 7 सालों में यानी 2032 तक 90 से ज्यादा देशों में डिफेंस विंग खोलने का लक्ष्य रखा गया है। गौरतलब है कि विभिन्न देशों में भारतीय दूतावासों या उच्चायोगों में खुले डिफेंस विंग में डिफेंस अताशे तैनात होते हैं, जो तीनों में से किसी भी सेना के बड़े अफसर हो सकते हैं।

युद्ध उपकरणों के आयात की स्थिति को तेजी से पार कर निर्यातक बन रहा भारत

- मानवीय सहायता, आपदा राहत और आतंकरोधी सहयोग के क्षेत्र में भी बढ़ रहा आर्मी का महत्व
- बड़े स्तर पर 30 हजार करोड़ रुपये के रक्षा निर्यात का रखा गया है लक्ष्य
- साल 2024 में 45 देशों में बन चुके थे डिफेंस विंग, 2025 में 52 हो चुकी है तादाद
- अगले 7 वर्षों में 90 से अधिक देशों में डिफेंस विंग खोलने का तय किया गया है बड़ा मिशन

- भारतीय दूतावासों या उच्चायोगों में तैनात किए जाते हैं सेना के बड़े अधिकारी

विदेश नीति और रक्षा निर्णयों में मदद

इस मुहिम का उद्देश्य सैन्य गठबंधन करना नहीं है, बल्कि रक्षा सहयोग बढ़ाना है, क्योंकि युद्ध के अलावा मानवीय सहायता, आपदा राहत, शांति सेना, आतंकरोधी सहयोग जैसे क्षेत्रों में भी सेना का महत्व बढ़ रहा है। डिफेंस अताशे अपने देश की सैन्य नीतियां, दृष्टिकोण और प्राथमिकता साझा करते हैं। साझा सैन्य अभ्यासों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, रक्षा उपकरणों से जुड़े समझौतों में योगदान देते हैं। साथ ही सैन्य सुरक्षा से जुड़ी ऐसी रणनीतिक जानकारी भी जुटाते हैं, जो भारत की विदेश नीति और रक्षा निर्णयों में मदद करे।

राजनयिकों के समान विशेषाधिकार

किसी अन्य देश में तैनात ये सेना के अधिकारी राजनयिक स्तर पर अपने देश के सैन्य हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विएना कन्वेंशन के तहत उन्हें राजनयिकों के समान विशेषाधिकार और इम्युनिटी मिलती है। आमतौर पर ब्रिगेडियर, कर्नल या उससे उच्च रैंक वाले सैन्य अधिकारी इस पद के लिए चुने जाते हैं, ताकि वे सैन्य मामलों के साथ ही कूटनीतिक मामलों को भी समझ सकें। इस मामले में अधिकारियों को पहले से प्रशिक्षण और अनुभव भी प्राप्त होता है।

सुबह में छाया रहा कोहरा, कनकनी में आई कुछ कमी

RANCHI : झारखंड में मौसम का उतार-चढ़ाव जारी है। शुक्रवार को सुबह में कोहरा छाया रहा, लेकिन कनकनी में थोड़ी कमी आई। शुक्रवार को किसी भी जिले में शीतलहर चलने का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। पिछले 24 घंटे में 9 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। 2.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ खूंटी सबसे ठंडा जिला रहा। डाल्टनगंज न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे इलाके में हाड़ कंपाने वाली ठंड महसूस हुई। रांची मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि शनिवार से उच्चतम तापमान में तीन से चार डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है।

20 को भाजपा को मिलेगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, नोटिफिकेशन जारी

AGENCY NEW DELHI : 20 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। पार्टी ने इसके लिए शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसके मुताबिक 19 जनवरी को नामांकन भरा जाएगा। 20 जनवरी को नए पार्टी अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। गौरतलब है कि अभी नितिन नबीन पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। पार्टी उन्हें निर्विरोध अध्यक्ष चुन सकती है। भाजपा ने साल 2020 में जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। 2024 में उनका कार्यकाल खत्म हुआ था। तब से वे एक्सटेंशन पर थे। नड्डा अभी केंद्र में स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय रिटर्निंग ऑफिसर के. लक्ष्मण ने चुनाव का शेड्यूल जारी किया। इसके मुताबिक, पार्टी प्रमुख के चुनाव के लिए नॉमिनेशन 19 जनवरी को दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच भरे जाएंगे और उम्मीदवार उसी दिन शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच अपना नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं। लक्ष्मण ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो 20 जनवरी को वोटिंग होगी और उसी दिन नए चुने गए राष्ट्रीय अध्यक्ष की आधिकारिक घोषणा की जाएगी।

अभी नितिन नबीन हैं पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष

प्रेम-प्रसंग में किशोर की चाकू से गोदकर हत्या, दो घायल

मेला से लौटते समय युवकों ने घेरकर रोक दी थी बाइक

PHOTON NEWS DUMKA : दुमका जिले में प्रेम-प्रसंग से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां चाकू से किए गए हमले में एक किशोर की मौत हो गई, जबकि एक अन्य किशोर और एक किशोरी गंभीर रूप से घायल हो गए। यह वारदात रामगढ़ थाना क्षेत्र के पथरिया गांव के पास गुरुवार देर रात घटी, जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। जानकारी के अनुसार, जामा थाना क्षेत्र में आयोजित तातलोई मेला देखकर लौट रहे दो किशोर डेविड और लखींद्र एक किशोरी के साथ बाइक से घर जा रहे थे। जैसे ही वे रामगढ़ थाना क्षेत्र के पथरिया के पास पहुंचे, तभी बाइक सवार तीन युवकों ने उन्हें ओवरटेक कर रोका। आरोप है कि हमलावरों ने किशोरी को जबरन बाइक से उतारने का प्रयास किया। जब डेविड और लखींद्र ने इसका विरोध

अस्पताल में इलाजरत घायल

किया, तो आरोपियों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में किशोरी समेत दोनों किशोर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से तीनों घायलों को देर रात फूलो-झानो मेडिकल कॉलेज-अस्पताल, दुमका में भर्ती कराया गया। यहां चिकित्सकों ने लखींद्र को मृत घोषित कर दिया। वहीं, किशोरी और डेविड की हालत गंभीर बनी हुई है। उनका इलाज अस्पताल में जारी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर एसडीपीओ विजय कुमार महतो अस्पताल पहुंचे और घायलों से घटना की जानकारी ली। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। आशंका जताई जा रही है कि हमला किशोरी के परिजनों द्वारा किया गया हो सकता है, हालांकि पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। रामगढ़ थाना की पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

युवक की हत्या कर जलाया शव, जांच में जुटी पुलिस

PALAMU : जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के गुरहा गांव में एक 25 वर्षीय अज्ञात युवक की हत्या करने के बाद उसका शव जला दिया गया। शुक्रवार को उसका अधजला शव मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार गुरहा गांव के आसपास के लोगों ने कब्रिस्तान के पीछे सुनसान इलाके में एक युवक का अधजला शव देखा। इसे लेकर बड़ी संख्या में लोग शव को देखने के लिए मौके पर पहुंचे। इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पहचान कराने की कोशिश की। हालांकि शव की पहचान स्थानीय लोगों ने नहीं की, लेकिन चर्चा है कि युवक शाहपुर इलाके का रहने वाला है। युवक की हत्या किसने की और शव कैसे जलाया गया, इसके लिए पुलिस कई स्तरों पर जांच कर रही है। चैनपुर के थाना प्रभारी श्रीराम शर्मा ने बताया कि पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। युवक की पत्थर से कुचलकर कर हत्या करने के बाद उसके शव को जलाया गया है। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है।

मेदिनीनगर में युवक को पत्थर से कूचकर मार डाला, रेलवे लाइन के किनारे मिली लाश

AGENCY PALAMU : पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर शहर के दो नंबर टाउन थाना क्षेत्र अंतर्गत कांदू मुहल्ला में रेलवे लाइन किनारे शुक्रवार सुबह एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक की पत्थर से कूचकर हत्या कर शव को झाड़ी में फेंक दिया गया था। घटना की सूचना मिलने पर टीओपी-02 की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (एमएमसीएच) में पोस्टमार्टम कराया। मृतक की पहचान लेस्लीगंज निवासी सुनील यादव के रूप में हुई है, जो कांदू मुहल्ला में रह रहा था। पुलिस के अनुसार, सुबह कांदू

मुहल्ला की कुछ महिलाएं रेलवे लाइन किनारे शौच के लिए गई थीं। इसी दौरान उन्होंने झाड़ी में शव देखा और आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव की पहचान का प्रयास किया गया, लेकिन प्रारंभ में पहचान नहीं हो सकी। पुलिस ने बताया कि शव मिलने वाले स्थान से कुछ दूरी पर गुरुवार सुबह गोली चलने की घटना हुई थी। इसके चलते स्थानीय लोगों को पहले आशंका हुई कि शव गोली चलाने वाले गोलू पासवान का हो सकता है, लेकिन बाद में यह स्पष्ट हुआ कि मृतक कोई अन्य युवक है। कुछ घंटे बाद शव की पहचान सुनील यादव के रूप में हुई। स्थानीय लोगों के अनुसार, मृतक स्टेशन परिसर के आसपास घूमता था और उस पर छोटी-मोटी चोरी में संलिप्त रहने की चर्चा थी। शहर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि हत्या के कारणों और आरोपितों की पहचान के लिए पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है।

BRIEF NEWS

स्लीपर बसों से ड्राइवर पार्टिशन डोर हटाने का आदेश

SERAIKELA : सरायकेला-खरसावां के जिला परिवहन पदाधिकारी गिरजा शंकर महतो ने बस संचालकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। इसके तहत सभी स्लीपर बस से ड्राइवर पार्टिशन डोर तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, स्लीपर बर्थ में लगाए गए सभी प्रकार के स्लाइडर को भी अविलंब हटाने को कहा गया है। सभी स्लीपर बसों में फायर डिटेक्शन एंड सप्रेसन सिस्टम एक माह की अवधि के भीतर अनिवार्य रूप से स्थापित करना होगा। इसके साथ ही, प्रत्येक बस में न्यूनतम 10 किलोग्राम क्षमता का अग्निशामक यंत्र निर्धारित ग्रीन जोन में उपलब्ध रखना अनिवार्य होगा। चेसिस के अनधिकृत विस्तार के आधार पर निर्मित बस बॉडी को तत्काल प्रभाव से परिचालन से बाहर किया जाएगा। किसी भी बस का पंजीकरण केवल फॉर्म 22/22अ एवं अनुमोदित परीक्षण एजेंसी की वैध स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही किया जाएगा। प्रत्येक बस के पंजीकरण के लिए ले-आउट ड्राइंग संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसमें बस के आयाम, दरवाजों की स्थिति, आपातकालीन निकास तथा रूफ हैच का स्पष्ट विवरण अंकित हो। इसके साथ ही बस बॉडी बिल्डर की वैध मान्यता की जांच पंजीकरण के समय अनिवार्य रूप से की जाएगी। जिला परिवहन पदाधिकारी ने निर्देश दिया है कि बसों का परिचालन प्रावधानों के अनुरूप ही किया जाएगा। इन निदेर्शों का उल्लंघन करने वाले बस संचालकों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

दो बच्चों की बलि चढ़ाने वाले को उम्रकैद

LATEHAR : छह वर्ष पूर्व मनिका थाना क्षेत्र के सेमरहट में दो मासूम बच्चों की बलि दे दी गई थी। इस मामले में जिला कोर्ट ने शुक्रवार को सुनील उरांव को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 9 लाख रुपये का जुमार्ना भी लगाया गया है। वर्ष 2019 में हुई नरबलि की घटना काफी चर्चा में थी। दोनों बच्चों का सिर कटा हुआ मिला था। दोषी सुनील उरांव ने घर के आंगन में ही दोनों बच्चों का शव बालू में दबा दिया था। लगभग 10 लोगों की गवाही के बाद न्यायालय ने इस मामले में फैसला सुनाया।

रामगढ में दो ज्वेलरी दुकानों से लाखों की चोरी

RAMGARH : जिले के भुरकुंडा ओपी क्षेत्र अंतर्गत सौंदा डी पंचायत में एक ही परिवार की दो ज्वेलरी दुकानों में चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने दोनों दुकानों का शटर तोड़कर लाखों रुपए के गहने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। सूचना पर पहुंची भुरकुंडा पुलिस घटनास्थल पर पहुंच कर टेक्निकल टीम के सहयोग से जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार सौंदा डी स्थित देवरतन ज्वेलर्स में शटर तोड़कर चोरों ने करीब 15 लाख रुपये से अधिक मूल्य के सोने-चांदी के गहने और 35 हजार रुपये नकद चोरी कर ले गए। वहीं जीपी कैंप स्थित राजरतन ज्वेलर्स में भी शटर तोड़कर लगभग ढाई लाख रुपये के गहने चोरी होने की बात सामने आई है। शुक्रवार को लोगों ने दोनों दुकानों के शटर टूटे होने की जानकारी दुकानदारों को दी। सूचना के बाद संचालक रतनलाल प्रसाद और मनोज कुमार स्वर्णकार दुकान पहुंचे तो देखा कि दुकान के अंदर सामान बिखरा पड़ा है। इसके बाद भुरकुंडा पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाना शुरू किया।

मोस्ट वांटेड हैदर अली उर्फ प्रिंस खान का वीडियो वायरल, फहीम को दी जान से मारने की धमकी

AGENCY DHANBAD : मोस्ट वांटेड अपराधी हैदर अली उर्फ प्रिंस खान का एक ताजा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कोयलांचल में हड़कंप मच गया है। वायरल वीडियो में प्रिंस खान सामान्य टी-शर्ट में नजर आ रहा है, जबकि वीडियो में कई अत्याधुनिक हथियार भी दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में वह गैंग्स ऑफ वासेपुर के सरगना फहीम खान और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। यह पहली बार नहीं है जब प्रिंस खान का ऐसा वीडियो सामने आया हो। इससे पहले भी उसके द्वारा धमकी भरे वीडियो वायरल होते रहे हैं। ताजा वीडियो में वह खुले तौर पर कहता नजर आ रहा है कि उसके पास हथियार मौजूद हैं और वह फहीम खान

अपराधी हैदर अली उर्फ प्रिंस खान

तथा उसके परिवार को गोली से उड़ा देने की बात कर रहा है। वीडियो में वह अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए पुलिस को भी चुनौती देता दिख रहा है।
वीडियो में प्रिंस खान यह दावा करता नजर आ रहा है कि पुलिस उसे पकड़ नहीं सकती और यदि कभी पुलिस उसे गिरफ्तार करती है तो वह खुद को गोली मार लेगा। साथ ही वह खुद को दुबई में होने का दावा करते हुए पुलिस को चुनौती देता हुआ दिखाई देता है। वायरल वीडियो को लेकर फैली चचाओं के बीच धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) प्रभात कुमार ने स्थिति को स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले में पूरी गंभीरता से काम कर रही है। किसी भी तरह की अफवाह या धमकी से निपटने के लिए पुलिस 24 घंटे तत्पर है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पुलिस और जिला प्रशासन जनता की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर आती रहती है, इसपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नही है, कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है।

फर्जी बेलर पर कार्रवाई शुरू, 3400 अपराधी रडार पर

DHANBAD : फर्जी बेलर प्रस्तुत कर जमानत पर जेल से बाहर आने वाले अपराधियों की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पहले चरण में ऐसे 3400 अपराधी रडार पर आ गए हैं। एसएसपी प्रभात कुमार ने शुक्रवार को पत्रकारों को बताया कि कई अपराधी फर्जी या भाड़े के बेलर बनाकर बेल बॉन्ड भरवाते हैं और जेल से बाहर आ जाते हैं। ऐसे बेलर पैसा लेकर अपराधियों के लिए जमानतदार बनते हैं, जो कानूनन अपराध है। इस पूरे नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वर्ष 2025 तक बेल पर बाहर आए अपराधियों के मामलों की जांच की जा रही है। इसमें यह देखा जाएगा कि किन-किन लोगों ने बेलर की भूमिका निभाई। बेल किस आधार पर कराई गई और बेल बॉन्ड में कोई फजीर्वाड़ा तो नहीं हुआ।
एसएसपी ने बताया कि बैठक में पिछले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न मामलों में शामिल अपराधियों की सूची तैयार की गई है, जिनकी संख्या करीब 3400 है। इन सभी अपराधियों के वेरिफिकेशन के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है।

शराब पार्टी के बाद युवक पर चलाई गोली, अफरा-तफरी

DHANBAD : सदर थाना क्षेत्र के झाड़ूडीह में गुरुवार की रात शराब पार्टी के बाद गोली चलने की घटना हुई। राजेश झा ने बताया कि अपार्टमेंट के फर्स्ट फ्लोर पर देवेंद्र सिंह का फ्लैट है। उसने अपार्टमेंट के पास अपने दोस्तों के साथ शराब पार्टी की थी। शराब पीने के बाद देवेंद्र सिंह उत्पात मचाते हुए तोड़फोड़ भी कर रहा था। जब उन्होंने आवाज सुनी और फ्लैट से नीचे आए तो उन्होंने देखा कि देवेंद्र सिंह उनके ड्राइवर को बंदूक की बट से पीट रहा था। जब मैंने देवेंद्र सिंह को ऐसा करने से मना किया तो उसने मेरे ऊपर ही गोली चला दी। संयोगवश गोली मेरी बायीं आंख के बगल से निकल गई। आंख के बगल में जख्म हो गया है। दूसरी ओर, इस घटना के बाद देवेंद्र सिंह फरार हो गया। राजेश झा की पत्नी कंचन झा ने

बताया कि देवेंद्र सिंह हमेशा शराब पीकर अपार्टमेंट में उपद्रव करता है। गुरुवार को रात में भी दोस्तों के साथ शराब पी और हंगामा मचाया। एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि पुलिस को फायरिंग मामले की लिखित शिकायत मिली है। आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटनास्थल पर पुलिस रात में ही पहुंची थी। वहां से कारतूस और खोखा बरामद किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

खुले में मांस बेचने वालों पर लगाया गया भारी जुर्माना

RAMGARH : रामगढ़ में खुले में मांस बेचने वालों के खिलाफ एक बार फिर कार्रवाई की गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से शुक्रवार को शहर में व्यापक जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान बाजार टांड़ स्थित मीट और चिकन दुकानों की जांच की गई और उनपर जुर्माना लगाया गया। जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अदिति सिंह ने बताया कि जांच के दौरान सभी दुकानें बिना भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के लाइसेंस और पंजीकरण के संचालित पाई गईं। नियमानुसार मीट और चिकन दुकानों में न तो पर्याप्त साफ-सफाई थी और न ही मांस को पर्दे से ढककर रखा गया था। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के शेड्यूल-4 के अनुरूप कोई भी मानक पूरा नहीं किया गया था। दुकानों में अत्यधिक गंदगी भी पाई गई। उन्होंने बताया कि सभी संबंधित दुकानों पर जुर्माना लगाया गया है तथा सुधार के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। तेजू चिकन शॉप पर 5,000 रुपये, उपेंद्र झटका मीट दुकान पर 10,000 रुपये, मुन्नीलाल झटका मीट दुकान पर 10,000 रुपये, महतो झटका मीट दुकान पर 10,000 रुपये, अभय चिकन शॉप पर 5,000 रुपये, रघु चिकन शॉप पर 10,000 रुपये तथा रवि कुशवाहा झटका मीट दुकान पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। औचक निरीक्षण और कार्रवाई के बाद जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने दुकानदारों को खुले में मांस की बिक्री नहीं करने का निर्देश दिया। उन्होंने फल और सब्जी की दुकानों के समीप मांस की बिक्री न करने, दुकान के आसपास स्वच्छता बनाए रखने तथा मांस दुकानों में स्वतः बंद होने वाले दरवाजे लगाने के निर्देश दिए। साथ ही बिना पंजीकरण के दुकान संचालित नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई।

पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा

CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिला में न्यायालय ने पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार, कुमारडुंगी दिकुबालकाड़ गांव के रंगामाटी गांव निवासी उपेंद्र उर्फ फूलचंद गोप ने अपनी पत्नी गांगी गोप की 26 फरवरी 2022 को हत्या कर दी थी। किस बात को लेकर हुए झगड़े में फूलचंद गोप ने तेज धारदार हथियार से पत्नी की बायीं कान के पास मारकर जख्मी कर दिया था, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। फूलचंद गोप पर कोर्ट ने 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

तस्करी के लिए ले जा रहे 48.1 किलो गांजा के साथ एक धराया

AGENCY HAZARIBAG : जिले में नशीले पदार्थों की खरीद-बिक्री करने वालों के विरुद्ध पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को 48.1 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। इस दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि एनएच-522 स्थित सिवाने पुल के पास एक सफेद रंग की डस्टर कार में गांजा की तस्करी की जा रही है। सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, विष्णुगढ़ के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया। छापेमारी दल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सिवाने पुल के पास सड़क किनारे खड़ी डस्टर वाहन को चिन्हित किया गया। पुलिस बल को देखकर एक व्यक्ति

पुलिस गिरफ्त में आरोपी व बरामद गांजा

वाहन छोड़कर भागने लगा, जिसे दौड़ाकर पकड़ लिया गया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान चंदन कुमार, ग्राम नामकुम देवी मंडप रोड, थाना नामकुम, जिला रांची के रूप में हुई है। वाहन की तलाशी के दौरान डिक्की में पारदर्शी प्लास्टिक में लिपटे 13 पैकेट गांजा, कुल वजन 48.1 किलोग्राम बरामद किया गया। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि वह अपने सहयोगियों के साथ मिलकर वाहन से गांजा तस्करी का कार्य करता था। इस मामले में अन्य संलिप्त व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं पुलिस ने बताया कि जिले में अवैध अफीम, डोडा और गांजा की तस्करी के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा और इस तरह के अपराधों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

भागवत कथा में रसिया बाबा ने कथाओं के माध्यम से बताया जीवन का सार

PHOTON NEWS JSR: बिष्टुपुर स्थित तुलसी भवन में चल रही भागवत कथा के दूसरे दिन शुक्रवार को वृंदावन से पधारे प्रसिद्ध कथावाचक रसिया बाबा ने व्यासपीठ से भागवत कथा के मंगल मय प्रसंग, महाभारत कथा, श्रृष्टि की उत्पति, कपिल देवहूति जी की कथा, सती चरित्र, शिव विवाह महोत्सव आदि का प्रसंग विस्तार से सुनाया। शरणागति परिवार, जमशेदपुर द्धारा आयोजित कथा में कथावाचक ने कहा कि भागवत कथा के ये सभी प्रसंग (सृष्टि, कपिल-देवहूति, सती चरित्र, शिव विवाह, महाभारत) श्रीमद्भागवत महापुराण और अन्य शास्त्रों के अत्यंत महत्वपूर्ण और मनमोहक अंश हैं, जो जीवन, भक्ति, वैराग्य, और ईश्वर-लीला के गूढ़ रहस्यों को समझाते हैं। भागवत कथा इन सभी प्रसंगों को एक साथ जोड़कर एक मंगलमय यात्रा कराती है, जिसमें सृष्टि की

कथावाचक रसिया बाबा

उत्पत्ति (ब्रह्मा से लेकर प्रलय तक), कपिल मुनि द्वारा माता देवहूति को ज्ञान, देवी सती का आत्मदाह और शिव-विवाह का विस्तार से वर्णन होता है, जो अंततः महाभारत की ओर ले जाता है। इन कथाओं के माध्यम से उन्होंने जीवन का सार समझाया। कथावाचक ने कहा कि सती चरित्र और शिव विवाह का प्रसंग हिंदू पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें माता सती का अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर आत्मदाह करना और फिर पुनर्जन्म लेकर देवी पार्वती के रूप में शिव से विवाह करना वर्णित है, जो शिव-पार्वती विवाह के रूप में मनाया जाता है, जिसे महाशिवरात्रि के पर्व से भी जोड़ा जाता है। कथा में मुख्य यजमान उषा-ब्रिज मोहन बागड़ी, गरिमा-तनय झवर, सुनीता-बिमल रिंगसिया, निर्मला-अरुण धूत थे। शनिवार को तीसरे दिन ध्रुव चरित्र, पुरंजन उपाख्यान, जड़भरत चरित्र, अजामिल कथा, श्री प्रह्लाद चरित्र आदि प्रसंगों की व्याख्या सुमधुर भजनों के साथ की जाएगी।

ब्रज चौरासी कोस यात्रा : ब्रज चौरासी कोस यात्रा 22 फरवरी से 1 मार्च तक निकलेगी। पावन सानिध्य रसिया बाबा महाराज और शरणागति परिवार, वृंदावन के तत्वावधान में निकलने वाली इस कोस यात्रा से जो भक्त जुड़ना चाहते हैं, उन्हें शरणागति परिवार से इस नंबर 9837036490, 8477050001 पर संपर्क करना होगा।

आक्रोश विभिन्न संगठनों ने किया बंद का समर्थन, शाम को निकाला गया मशाल जुलूस

सोमा मुंडा की हत्या को लेकर आज झारखंड बंद का आह्वान

PHOTON NEWS KHUNTI : खूंटी के पड़हा राजा सोमा मुंडा की 7 जनवरी की शाम को हत्या कर दी गई थी। इसे लेकर 17 जनवरी को झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। आदिवासी समन्वय समिति (खूंटी) की अगुवाई में होने वाले बंद का 30 से अधिक राजनीतिक-सामाजिक संगठनों ने समर्थन किया है। बंद समर्थकों का कहना है कि हत्याकांड के इतने दिनों बाद भी मुख्य साजिशकर्ता और शूटरों की गिरफ्तारी नहीं होने से सामाजिक संगठनों में आक्रोश बढ़ रहा है।
बंद समर्थक मांग कर रहे हैं कि हत्या में शामिल मुख्य अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए, अनावश्यक रूप से किसी निर्दोष को नहीं पकड़ा जाए, दिवंगत सोमा मुंडा के परिवार को जल्द समुचित मुआवजा दिया जाए और सोमा मुंडा द्वारा संचालित स्कूल के बच्चों को गोद लेकर सरकार

चाईबासा में मशाल जुलूस निकालकर बंद का किया आह्वान

CHAIBASA : पड़हा राजा सोमा मुंडा हत्याकांड को लेकर शुक्रवार को चाईबासा में पोस्ट ऑफिस चौक पर मशाल जुलूस निकाला गया। इसमें आदिवासी मुंडा समाज, आदिवासी एकता मंच, आदिवासी स्वशासन एकता मंच, आदिवासी हो महासभा के सदस्य व समर्थक शामिल थे। इस मौके पर मानकी मुंडा समिति के महासचिव चंदन होनहागा ने कहा कि कहा कि पुलिस निर्दोष ग्रामीणों को परेशान करने के बजाय असली दोषियों को गिरफ्तार करे। उन्होंने दावा किया कि झारखंड बंद को एक दर्जन से अधिक आदिवासी संगठनों का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने बताया कि 7 जनवरी को पड़हा राजा सोमा मुंडा को भू माफिया ने एक साजिश के

मशाल जलाकर बंद का आह्वान करते आदिवासी

तहत उनकी हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि सरकार पारंपरिक व्यवस्था को जोड़े रखने वाले को पूरा सुरक्षा प्रदान करे, ताकि क्षेत्र में व्यवस्था बनी रहे। हत्या के बाद समाज के लोगों ने प्रशासन को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन अब तक की गई पुलिस की कार्रवाई से कोई भी संतुष्ट नहीं है। जब तक मुख्य आरोपी सहित अन्य अपराधियों को पकड़कर फांसी नहीं दी जाती, तब तक विरोध जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इसी वजह से 17 जनवरी को झारखंड बंद का आह्वान किया गया है।

उनकी शिक्षा जारी रखे। इसे लेकर शुक्रवार शाम को खूंटी में मशाल जुलूस निकाला गया, जो भगत सिंह चौक से नेताजी चौक तक गया। इसमें आदिवासी समन्वय समिति के अध्यक्ष चंद्र प्रभात मुंडा, संयोजक महादेव मुंडा, दुर्गावती ओड़ेया, जॉनसन होरो, चार्ल्स पाहन, बाहा लिंडा समेत आदिवासी संगठनों के लोग शामिल थे।

झापीपा ने रखी सीबीआई जांच की मांग : आजसू के संस्थापक व झारखंड पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष-सहः घाटशिला के पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि पाड़हा राजा शहीद सोमा मुंडा की हत्याकांड के खिलाफ 17 जनवरी को संपूर्ण झारखंड बंद उचित है। बेसरा ने कहा कि सोमा मुंडा की हत्या एक सुनियोजित राजनीतिक साज़िश के तहत हुई है, इसलिए इसकी जांच सीबीआई से करानी चाहिए। सोमा मुंडा साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे पड़हा राजा थे। जल, जंगल और जमीन के प्रहरी ही नहीं, बल्कि रक्षक थे। वे झारखंड आंदोलनकारी के साथ साथ धरतीआबा बिरसा मुंडा के अनुयायी भी थे। वे भूमि माफियाओं के खिलाफ निरंतर संघर्ष कर रहे थे। पड़हा राजा शहीद सोमा मुंडा वर्तमान झारखंड राज्य पंचायत अधिनियम 2001 एवं हेमंत सरकार द्वारा अधिसूचित पेसा कानून-1996 की मूल आत्मा के विपरीत नियमावली के खिलाफ थे।

BRIEF NEWS

तीरंदाजी में झारखंड की प्रिया बनी चैंपियन

RANCHI : मणिपुर के खुमान लम्पक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 14 जनवरी से 18 जनवरी 2026 तक आयोजित 69 वीं राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता (एसजीएफआई) में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रौशन किया है। इस प्रतियोगिता में झारखंड की तीरंदाजी और वुशु टीम स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की अगुवाई में भाग लेने गई है। वहीं शुक्रवार को आयोजित तीसरे दिन की तीरंदाजी प्रतियोगिता में इंडियन इंडिविजुअल राउंड (ओलंपिक राउंड) 40 मीटर, अंडर-19 बालिका वर्ग में झारखंड की प्रिया माहाली ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया।

हटिया स्टेशन से 16 किलो गांजा बरामद दो गिरफ्तार

RANCHI : रेल सुरक्षा बल पोस्ट हटिया और फ्लाइंग टीम रांची ने ऑपरेशन नार्कोस के तहत मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। कमांडेंट आरपीएफ रांची मंडल पवन कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान के दौरान हटिया रेलवे स्टेशन से 16 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। जिसकी अनुमानित कीमत करीब 8 लाख रुपये बताई जा रही है। यह कार्रवाई 15 जनवरी को की गई थी। ट्रेन संख्या 18452 पुरी हटिया एक्सप्रेस के आने के बाद प्लेटफॉर्म संख्या-1 स्थित पार्सल कार्यालय के पास दो युवक पिट्ठू बैग के साथ संदिग्ध स्थिति में बैठे पाए गए। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम मंटू मलिक उर्फ मनोरंजन मलिक संबलपुर ओडिशा और आलोक डिगल कंधमाल ओडिशा बताया। पूछताछ के दौरान दोनों ने बैग में गांजा होने की बात स्वीकार की।

6 फरवरी से शुरू होगी मदरा मुंडा फुटबॉल चैंपियन ट्रॉफी

KANKE : शुक्रवार को कांके प्रखंड प्रमुख सोमनाथ मुंडा की अध्यक्षता में महाराजा मदरा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम रेंडो पतरातू कांके में छठा महाराजा मदरा मुंडा फुटबॉल चैंपियन ट्रॉफी को लेकर बैठक हुई। मुंडा ने बताया कि पिछले पांच वर्षों से महाराजा मदरा मुंडा फुटबॉल चैंपियन ट्रॉफी का भव्य आयोजन होते आ रहा है। इस वर्ष भी टूनार्मेंट का आयोजन 6 फरवरी को उद्घाटन एवं 14 फरवरी को फाइनल मैच खेला जाएगा। टूनार्मेंट मे भाग लेने के लिए प्रवेश शुल्क एक्कीस हजार रुपये रखा गया है। प्रथम पुरस्कार के रूप मे तीन लाख रुपये एवं बड़ा ट्रॉफी, द्वितीय पुरस्कार दो लाख रुपये एवं छोटा ट्रॉफी, तृतीय पुरस्कार पचास हजार रुपये, एवं चतुर्थ पुरस्कार भी पचास हजार रुपये रखा गया है।

आरपीएफ ने लोगों की अमानत लौटने में लगातार दिखाई तत्परता

VIVEK SHARMA, RANCHI : रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (आरपीएफ) यात्रियों की सुरक्षा तो कर ही रहा है। वहीं ट्रेन में छूटे हुए सामान भी उसके असली मालिक तक पहुंचाने में पीछे नहीं है। यहीं वजह है कि अब ट्रेन में सामान छूट जाने के बाद भी लोगों को सही सलामत लौटाया जा रहा है,ताकि लोगों का भरोसा और मजबूत हुआ है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते एक साल के दौरान आरपीएफ ने ट्रेन और रेलवे परिसरों में छूटे हुए 273 यात्रियों का खोया हुआ सामान सुरक्षित लौटाया। जिसकी अनुमानित कीमत 51,47,057 रुपये थी।

आरपीएफ अधिकारियों के अनुसार, यात्रियों की बढ़ती आवाजाही के कारण ट्रेन में जल्दबाजी, स्टेशन पर भीड़ या असावधानी के चलते सामान छूटने की घटनाएं आम हैं। ऐसे मामलों में आरपीएफ ऑपरेशन अमानत के तहत त्वरित कार्रवाई करते हुए खोए हुए बैग, नकद राशि, मोबाइल, आभूषण, कपड़े और अन्य कीमती सामान को सुरक्षित बरामद करता है। इसके बाद पूरी जांच-पड़ताल और वेरीफिकेशन के बाद सामान उसके वास्तविक मालिक को सौंप दिया जाता है।

नकद राशि के साथ कीमती दस्तावेज : आरपीएफ द्वारा लौटाए गए सामान में नकद राशि के साथ-साथ पैसेंजर्स के कीमती दस्तावेज, पहचान पत्र, मेडिकल कागजात और घरेलू सामान भी शामिल हैं। इसके अलावा लोगों को कैश भी सही सलामत लौटाए गए है। जिसकी लोगों को मिलने की उम्मीद ही नहीं थी। कई मामलों में पैसेंजर्स ने आरपीएफ की सक्रियता और ईमानदारी की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका खोया हुआ सामान इतनी जल्दी और सुरक्षित वापस मिल जाएगा।

- एक साल में 273 छूटे हुए सामान को असली मालिक तक पहुंचाया
- ट्रेनों में छूटने के बाद 51,47,057 रुपये के सामान किए गए वापस
- पूरी जांच-पड़ताल और वेरिफिकेशन के बाद सौंपी जाती है छूटी हुई वस्तु

सामान छूट जाए तो करें कंप्लेन

आरपीएफ कमांडेंट पवन कुमार ने बताया कि यदि किसी यात्री का सामान ट्रेन में या रेलवे स्टेशन पर छूट जाए तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे मामलों में यात्री तुरंत रेल मदद हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। 139 डायल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है। शिकायत मिलते ही संबंधित आरपीएफ पोस्ट और एस्कॉर्ट टीम को सूचना दी जाती है, जिसके बाद त्वरित खोजबीन शुरू की जाती है। समय पर सूचना मिलने से सामान बरामद होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इसलिए यात्रा के दौरान अपने सामान पर ध्यान रखें और ट्रेन से उतरते समय एक बार अपने आसपास जरूर जांच कर लें। इसके साथ ही किसी भी प्रकार की परेशानी या सामान छूटने की स्थिति में बिना देरी किए रेल मदद का सहारा लें।

केस-1 आरपीएफ लोहरदगा ने 15 जनवरी को राजधानी एक्सप्रेस के यात्री का खोया हुआ सामान सुरक्षित रूप से लौटाया। रेल मदद के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि ट्रेन संख्या 20408 राजधानी एक्सप्रेस के कोच बी-1 के बर्थ संख्या 30 पर एक यात्री का बैग छूट गया है। सूचना मिलते ही आरपीएफ एस्कॉर्ट पार्टी ने जांच की और बैग सुरक्षित बरामद किया। बैग में साड़ियां, निमंत्रण पत्र, मेडिकल कार्ड तथा अन्य घरेलू सामान जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 10,000 रुपये बताई गई। वेरीफिकेशन के बाद पश्चात बैग को यात्री के अधिकृत प्रतिनिधि को सौंप दिया गया।

केस-2 12 जनवरी को एक यात्री बिहार के भोजपुर चिटनी के रहने वाले टुनटुन कुमार रांची से आरा जाने के लिए ट्रेन संख्या 18640 एक्सप्रेस से जाने के लिए रांची स्टेशन आया था। लेकिन, वह ट्रेन संख्या 18624 एक्सप्रेस के सामान्य कोच में चढ़ गया। गलती का एहसास होते ही वह तुरंत रांची रेलवे स्टेशन पर उतर गया। हड़बड़ी में उसका बैग ट्रेन में ही छूट गया। सूचना मिलते ही ऑन ड्यूटी शिफ्ट अधिकारी ने ट्रेन संख्या 18624 एक्सप्रेस में तैनात एस्कॉर्ट पार्टी प्रभारी को अवगत कराया गया। जिन्होंने बैग सुरक्षित रूप से बरामद किया गया। बैग में नकद और कपड़े मिले। वेरीफिकेशन के बाद बैग और नकद राशि 44,970 रुपये बोकारो रेलवे स्टेशन पर संबंधित यात्री को सुपुर्द किया गया।

तीन दिवसीय मारवाड़ महोत्सव का आगाज, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार बोले-

मारवाड़ी समाज की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जीवंत करता है यह महोत्सव

PHOTON NEWS RANCHI : शुक्रवार को रांची में तीन दिवसीय 'मारवाड़ महोत्सव- 2026' का आगाज हो गया। जिसका उद्घाटन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया। उन्होंने कहा कि ये राजस्थान और मारवाड़ी समाज की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जीवंत रूप में प्रस्तुत करने का सराहनीय प्रयास है। साथ ही कहा कि ऐसे आयोजन देश की विविधतापूर्ण सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्यपाल ने कहा कि मारवाड़ महोत्सव केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने वाला मंच है। राज्यपाल ने कहा कि झारखंड की पावन धरती पर राजस्थान और मारवाड़ी समाज की सांस्कृतिक, सामाजिक और पारंपरिक विरासत का जीवंत प्रदर्शन यह दशार्ता है कि भारत की विविध संस्कृतियां एक-दूसरे के साथ कितनी सहजता से जुड़ती हैं। उन्होंने कहा कि महोत्सव के दौरान आयोजित पारंपरिक लोकनृत्य, लोकसंगीत, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, पारंपरिक व्यंजन, हस्तशिल्प प्रदर्शनी और विभिन्न प्रतियोगिताएं सामाजिक सौहार्द और सांस्कृतिक विविधता का सुंदर उदाहरण हैं।

ऐसे कार्यक्रम से एक-दूसरे के साथ सहजता से जुड़ती हैं भारत की विविध संस्कृतियां

कार्यक्रम को संबोधित करते राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार

विरासत का महत्व

राज्यपाल ने कहा कि इस तरह के आयोजन प्रधानमंत्री के 'विकास के साथ विरासत' और 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की अवधारणा को साकार करते हैं। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता में एकता है और सांस्कृतिक महोत्सव इस भावना को और अधिक मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों और समाजों की सांस्कृतिक पहचान को सम्मान देने से राष्ट्रीय एकता को नई ऊर्जा मिलती है।

समाज के योगदान की सराहना

मारवाड़ी समाज के योगदान की सराहना करते हुए राज्यपाल ने कहा कि परोपकार, सेवा-भावना, अनुशासन, श्रम, ईमानदारी और उद्यमशीलता इस समाज की विशिष्ट पहचान रही है। व्यापार, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा के क्षेत्रों में मारवाड़ी समाज ने देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि जहां-जहां मारवाड़ी समाज ने निवास किया है, वहां उसने स्थानीय संस्कृति के साथ आत्मीय समन्वय स्थापित कर सामाजिक सौहार्द को सुदृढ़ किया है।

सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में आगे

अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए राज्यपाल ने बताया कि वे उत्तर प्रदेश के बरेली से आते हैं और वहां उन्होंने मारवाड़ी समाज द्वारा किए जा रहे सामाजिक, शैक्षणिक और परोपकारी कार्यों को नजदीक से देखा है। यह समाज न केवल आर्थिक गतिविधियों में अग्रणी रहा है, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में भी हमेशा आगे रहा है। राज्यपाल ने विश्वास जताया कि झारखंड राज्य विकास के क्षेत्र में अग्रणी बनेगा और इस यात्रा में मारवाड़ी समाज की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए सभी वर्गों और समुदायों का सहयोग आवश्यक है। उद्घाटन समारोह के बाद राज्यपाल ने महोत्सव परिसर में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया।

कानून के शिकंजे से कोई नहीं बच पाएगा, तय है सबका जेल जाना : बाबूलाल मरांडी

PHOTON NEWS RANCHI : झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विरुद्ध रांची पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगाने और ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय की सुरक्षा केंद्रीय सुरक्षा बलों को सौंपने के आदेश को लेकर राज्य के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इस आदेश को जांच एजेंसियों की कार्रवाई को प्रभावित करने की कोशिश करने वालों के लिए ह्लकरारा तमाचाह्व बताया है। बाबूलाल मरांडी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ह्यएक्सह्व पर पोस्ट करते हुए कहा कि पुलिस के सहारे जांच एजेंसियों को डराने-धमकाने की चाहे जितनी भी कोशिश कर ली जाए, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि घोटालों और षड्यंत्रों में शामिल पूरा कुनबा कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएगा और सभी का जेल जाना तय है। मरांडी ने लोगों से धैर्य रखने की अपील करते हुए कहा कि समय आने पर सच्चाई सबके सामने होगी। नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार की ओर से पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति को लेकर नियमावली में किए गए संशोधन पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए यह तर्क दिया कि कई वरिष्ठ आईपीएस (भारतीय पुलिस सेवा) के अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर होने के कारण उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए नियमावली में संशोधन जरूरी था। मरांडी ने इस तर्क को पूरी तरह भ्रामक बताया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठता क्रम में शामिल आईपीएस अधिकारी अनिल पालटा, प्रशांत सिंह और एम.एस. भाटिया में से कोई भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नहीं है। इन अधिकारियों की सेवा अवधि भी क्रमशः एक वर्ष, दो वर्ष और तीन वर्ष शेष है। इसके बावजूद सेवानिवृत्ति से ठीक एक दिन पहले वरीयता क्रम में कनिष्ठ अधिकारी को डीजीपी नियुक्त कर दिया गया।

नगर निकाय को लेकर सीईसी ने दिए निर्देश, शांतिपूर्ण व निष्पक्ष हो चुनाव

PHOTON NEWS RANCHI : नगर निकाय चुनाव की तैयारी को अंतिम रूप देने में राज्य निर्वाचन आयोग जुटा हुआ है। शुक्रवार को राज्यभर के सभी 48 नगर निकायों के निवार्ची पदाधिकारी और सह निवार्ची पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। आयोग कार्यालय में आयोजित बैठक सह प्रशिक्षण कार्यक्रम में चुनाव के हर विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने कहा कि चुनाव की घोषणा होते ही निवार्ची पदाधिकारी और सह निर्वाचन प्रभारी की भूमिका अहम हो जाती है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि नामांकन के वक्त प्रत्याशियों के द्वारा भरे जाने वाले फॉर्म और चुनाव चिन्ह आवंटन के समय निर्वाचन पदाधिकारी की अहम भूमिका होती है। जिसे बड़े ही सतर्कता के साथ निभानी चाहिए। उन्होंने निर्वाचन से जुड़े पदाधिकारियों को सलाह दी। साथ ही कहा कि आयोग के द्वारा जारी निर्वाचन पुस्तिका का अध्ययन जरूर कर लें। क्योंकि उसी के अनुरूप निकाय चुनाव संपन्न कराने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया जाएगा। छोटी-छोटी बातों से कई बार विवाद बढ़ जाता है, इसलिए नियम संगत चुनाव के दौरान कार्य करें।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसकी जिम्मेदारी सभी पदाधिकारियों पर होगी। इसके लिए पूरी सतर्कता के साथ निर्वाचन के दौरान काम करने की आवश्यकता है।

श्री महावीर मंडल ने की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक, कई मुद्दों पर चर्चा

RANCHI : शुक्रवार को राजधानी रांची में श्री महावीर मंडल, केंद्रीय समिति की कार्यकारिणी की बैठक मंडल के अध्यक्ष जय सिंह यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में वर्ष 2025-26 में आयोजित श्री रामनवमी महोत्सव की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष जय सिंह यादव ने कहा कि सभी के सहयोग से वर्ष 2025 में श्री रामनवमी महोत्सव पूरे राज्य में भव्य, अनुशासित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। आयोजन को सफल बनाने में राज्यभर के अखाड़ाधारियों की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही। उन्होंने इस सफलता का श्रेय देते हुए सभी के प्रति आभार व्यक्त किया।

होटल स्टाफ की लापरवाही पर टोकना पड़ा भारी, थाने में दर्ज हुई शिकायत

PHOTON NEWS RANCHI : अरगोड़ा चौक स्थित एक मिठाई की दुकान में होटल स्टाफ की लापरवाही पर टोकना दो महिलाओं को भारी पड़ गया। मामूली कहासुनी देखते ही देखते मारपीट और अभद्रता में बदल गई। इस घटना में सपना चटर्जी और नेहा प्रसाद नामक दो महिलाओं ने अज्ञात लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं मामले को लेकर अरगोड़ा थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पीड़ित महिलाओं की शिकायत के अनुसार, यह घटना 11 जनवरी 2026 की शाम लगभग 7:30 बजे की है। दोनों महिलाएं अरगोड़ा चौक स्थित स्वीट कॉर्नर होटल में मिठाई खा रही थीं। इसी दौरान होटल स्टाफ की लापरवाही के कारण रस कपड़े पर गिर गया। महिलाओं ने स्टाफ को केवल सावधानी बरतने की सलाह दी, ताकि आगे ऐसा न हो। इसी बात से नाराज होकर वहां मौजूद एक अज्ञात महिला ने दोनों से अपमानजनक भाषा में बात करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उक्त महिला ने अन्य लोगों को मौके पर बुला लिया। इन लोगों ने खुद को प्रशासन से जुड़ा बताते हुए डराने का प्रयास किया। आरोपियों ने हमारे साथ गाली-गलौज की, साड़ी खींची, पैर से हमला किया और बीच बाजार घसीटने की धमकी दी। इसके साथ ही थाने में बंद करवा कर पिटाई कराने की भी धमकी दी गई।

कार्रवाई शहर का जायजा लेने निकले नगर निगम के प्रशासक

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगी 11 हजार की फाइन

PHOTON NEWS RANCHI : रांची नगर निगम शहर को स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के अपने संकल्प को धरातल पर उतारने में तेजी से जुटा है। इसी क्रम में शुक्रवार को नगर निगम के प्रशासक सुशांत गौरव के नेतृत्व में निगम की टीम ने शहर के प्रमुख इलाकों कडरू और अपर बाजार का निरीक्षण किया। निरीक्षण का उद्देश्य यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करना, स्वच्छता सुनिश्चित करना, सड़क चौड़ीकरण को गति देने के साथ अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई करना था।

कडरू में स्मार्ट बाजार से रेडिशन ब्लू होते हुए कडरू फ्लाईओवर तक पूरे मार्ग का बारीकी से निरीक्षण किया गया। प्रशासक ने

रोड का निरीक्षण करते नगर प्रशासक सुशांत गौरव व अन्य

गिफ्ट डीड की जमीन की जांच कर अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने और सुव्यवस्थित पाथवे निर्माण के निर्देश दिए। अतिक्रमण मुक्त अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने, टर्निंग प्वाइंट्स पर यातायात अव्यवस्था दूर करने तथा हरमू नदी की सफाई के साथ संरक्षण अभियान को और तेज करने के निर्देश भी दिए गए। अधिकारियों को स्पष्ट कहा गया कि सड़कें केवल आवागमन का माध्यम नहीं, बल्कि शहर की पहचान होती हैं। इसके बाद नगर निगम टीम ने शहर के सबसे व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्र अपर बाजार का निरीक्षण किया। शहीद चौक से रंगरेज गली और पुस्तक पथ होते हुए रांची विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार तक निरीक्षण के दौरान जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त निर्देश जारी किए गए। सड़कों और नालियों पर कूड़ा फेंकने, अवैध अतिक्रमण, दुकानों के अनधिकृत विस्तार और यातायात बाधित करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए। पीक आवर्स में मालवाहक वाहनों की नो-एंट्री के सख्त पालन और अवैध संरचनाओं की गहन जांच पर भी जोर दिया गया।

निरीक्षण के दौरान मौके पर ही नियमों के उल्लंघन पर 11,000 का जुर्माना लगाया गया। नगर निगम ने डेडिकेटेड रोड मैनेजमेंट टीम के माध्यम से प्रमुख सड़कों पर निरंतर निगरानी और त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। निगम ने लोगों से स्वच्छता और यातायात अनुशासन में सहयोग की अपील की है।

बजट 2026-27: स्वास्थ्य व पोषण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की मांग

RANCHI : झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने अबुआ दिशोम बजट 2026-27 को लेकर आयोजित बजट पूर्व गोष्ठी में राज्य की जनता के स्वास्थ्य और पोषण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह बजट मजबूत, दूरदर्शी और जनहितकारी होना चाहिए, ताकि इसका सीधा लाभ आम लोगों तक पहुंचे। गोष्ठी में अपने सुझाव रखते हुए डॉ. अंसारी ने स्वास्थ्य विभाग के बजट को वर्तमान 5500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 11000 करोड़ रुपये किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि बजट में पर्याप्त वृद्धि होने से राज्य में बेहतर अस्पतालों की स्थापना, नए मेडिकल कॉलेज, हाईटेक लैब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक तकनीक का उपयोग व सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का विकास संभव हो सकेगा।

जेएमएम को पिछड़े समाज से आने वाले का नेतृत्व स्वीकार नहीं : अमरदीप यादव

PHOTON NEWS RANCHI : भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अमरदीप यादव ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य द्वारा भाजपा के नव-निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू पर दिए गए बयान की कड़ी निंदा की।

उन्होंने कहा कि झामुमो को पिछड़े समाज से आने वाले समर्पित कार्यकर्ता का नेतृत्व स्वीकार नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि वह राजनीतिक मयार्दा को ताक पर रखकर नकारात्मक बयानबाजी कर रही है। भाजपा ने एक पिछड़ा वर्ग के मूलवासी किसान के बेटे, जो चार दशकों से अधिक समय से बूथ स्तर से संगठन की सेवा कर रहे हैं, को

प्रदेश अध्यक्ष बनाकर यह सिद्ध कर दिया है कि भाजपा सामाजिक न्याय, संगठनात्मक लोकतंत्र और कार्यकर्ता सम्मान की सच्ची पक्षधर है। उन्होंने आरोप लगाया कि झामुमो का इतिहास पिछड़ा, आदिवासी और किसान विरोधी नीतियों से भरा रहा है। अमरदीप ने कहा कि झामुमो और कांग्रेस गठबंधन को राज्य में पिछड़े वर्ग की बढ़ती राजनीतिक मजबूती बर्दाश्त नहीं हो रही है। झामुमो-कांग्रेस सरकार ने पिछड़ों को आरक्षण से वंचित कर धोखा दिया।

समाचार सार

25 फरवरी से खुल जाएगी डीएम लाइब्रेरी

JAMSHEDPUR : साकची के स्ट्रेटमाइल रोड स्थित डीएम (दिनशॉ मेमोरियल) लाइब्रेरी 25 फरवरी से दोबारा खुल जाएगी। 1936 में बनी

लाइब्रेरी का 13 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार किया गया है। इसे शुरू करने को लेकर डीसी कर्ण सत्यार्थी ने शुक्रवार को लाइब्रेरी का निरीक्षण किया। उन्होंने जेएनएसी के उपनगर आयुक्त कृष्ण कुमार को निर्देश दिया कि डीएम लाइब्रेरी में बेंच और डेस्क के अलावा अन्य जरूरी संसाधनों का इंतजाम किया जाए, ताकि यहां आने वालों को सुविधाजनक माहौल मिले। डीएम लाइब्रेरी में पठन सामग्री, प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता, पेयजल, शौचालय और अन्य आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने को कहा गया है। डीसी ने कहा कि डीएम लाइब्रेरी स्टूडेंट के लिए काफी फायदेमंद है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा भी इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा, आम पाठक भी अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए आ सकते हैं। इस पांचमंजिला बनाया गया है, जिसमें पार्किंग के अलावा दुकान व ई-लाइब्रेरी की व्यवस्था भी है। ज्ञात हो कि यह लाइब्रेरी करीब 6 वर्ष से बंद थी।

तारापदो महतो का अब तक नहीं हुआ अंतिम संस्कार

GHATSILA : गालूडीह थाना क्षेत्र के पुतरु गांव निवासी तारापदो महतो

की 12 जनवरी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, लेकिन परिजनों ने अभी तक उसका अंतिम संस्कार नहीं किया है। इसे लेकर झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता सह पूर्व विधायक कुणाल षाड़ंगी शुक्रवार को शोकाकुल परिवार से मिले। उन्होंने परिजनों को आश्वस्त किया कि इस हत्या में जो भी दोषी पाए होंगे, उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने परिजनों से आग्रह किया कि वे जल्द से जल्द अंतिम संस्कार संपन्न कराएं, ताकि प्रशासन को आगे की कानूनी कार्रवाई में सहयोग मिल सके। षाड़ंगी ने मृतक के बड़े भाई षष्ठी महतो की ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग से बात भी कराई। षाड़ंगी ने राज्य की पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा से भी बात कर इस गंभीर घटना पर संज्ञान लेने एवं दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग रखी। कुणाल ने कहा कि हेमंत सरकार में अपराधियों को न तो संरक्षण मिलेगा, न ही किसी दोषी को बख्शा जाएगा। झामुमो पीड़ित परिवार को हर हाल में न्याय दिलाने के लिए पूरी मजबूती से खड़ा है।

तारापदो हत्याकांड : आज एनएच जाम की चेतावनी

JAMSHEDPUR : गालूडीह स्थित पुतरू गांव में 12 जनवरी को

सीएससी संचालक तारापदो महतो की दुकान में घुसकर हत्या कर दी गई थी। इसे लेकर ग्रामीणों ने शुक्रवार को डीसी-एसएसपी सहित गालूडीह के थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें प्रशासनिक लापरवाही का आरोप लगाते हुए 17 को एनएच-33 व एनएच-18 को जाम करने की चेतावनी दी है। ज्ञापन में कहा गया है कि इस घटना से पूरे क्षेत्र में भय, आक्रोश और असंतोष का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि यह हत्या केवल एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि कानून-व्यवस्था की विफलता और अंचल कार्यालय की घोर लापरवाही का परिणाम है। प्रशासनिक नियमों के अनुसार सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त रखना, अवैध कब्जे पर रोक लगाना तथा भूमि से जुड़े विवादों का समय रहते समाधान करना अंचल कार्यालय की जिम्मेदारी होती है। लेकिन, संबंधित अधिकारियों की निष्क्रियता और मिलीभगत के कारण जमीन कारोबारियों को खुला संरक्षण मिला, अवैध कब्जों को बढ़ावा मिला और विवाद लगातार गहराता चला गया। इसी का परिणाम है कि भूमि विवाद ने हिंसक रूप लिया और अंततः तारापदो महतो की हत्या हुई।

एनसीसी कैडेट 21 को करेंगे पदयात्रा

GHATSILA : घाटशिला कॉलेज की एनसीसी इकाई द्वारा 21 जनवरी को भगवान बिरसा मुंडा पदयात्रा की जाएगी। प्राचार्य डॉ. आरके चौधरी

ने बताया कि भारत सरकार के माई भारत पोर्टल की पहल तथा एनसीसी निदेशालय के आह्वान पर यह पदयात्रा वृहद स्तर पर होगी। पदयात्रा के माध्यम से बिरसा मुंडा की विरासत और आदिवासी समुदायों के योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाएगा। इससे एक भारत- श्रेष्ठ भारत की भावना को भी बढ़ावा मिलेगा। प्राचार्य ने बताया कि पदयात्रा में स्थानीय जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, नागरिक व समाजसेवी भी शामिल होंगे।

नक्सल प्रभावित गांवों में सीआरपीएफ ने बांटी सामग्री

CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिले में पदस्थापित सीआरपीएफ की 193 बटालियन ने शुक्रवार को नक्सल प्रभावित गांवों में सामग्री का

वितरण किया। सिविक एक्शन प्रोग्राम 2025-26 के तहत ग्राम बोरोई में कमांडेंट ओमजी शुक्ला के मार्गदर्शन में बोरोई, बाईहातु, सांगाजटा, पाटुंग, सोंगा, किमसुआ, रुटागुटू आदि के ग्रामीणों में कंबल, मच्छरदानी, प्रेशर कुकर, छाता, बाल्टी, सिलाई मशीन, खाद्य सामग्री, पोशाक आदि के अलावा बच्चों में कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल, खेल सामग्री व पोशाक का वितरण किया गया। इस दौरान सीआरपीएफ के जीडी बिभूतोश दास ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य युवक-युवतियों को खेल व शिक्षा के प्रति जागरूक करना और प्रेम, सहयोग और भाईचारा को बढ़ावा देना है। जवानों का स्वागत ग्रामीणों ने पारंपरिक नृत्य व संगीत के साथ किया।

अर्जुन मुंडा ने किया गोल्फ टूर्नामेंट का उद्घाटन

JAMSHEDPUR : गोलमुरी स्थित गोल्फ कोर्स में शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने 75वें स्टील सिटी गोल्फ टूर्नामेंट का उद्घाटन

किया। यह टूर्नामेंट 18-होल की बेल्डीह और गोलमुरी गोल्फ कोर्स में रविवार तक होगा। इसमें पटना, भुवनेश्वर, पारादीप, रांची, दिल्ली और जमशेदपुर समेत कई प्रमुख शहरों के 250 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इस अवसर पर जमशेदपुर गोल्फ सचिव और टाटा स्टील लिमिटेड के चीफ-सेफ्टी नीरज कुमार सिन्हा, जेकेपीएसीपीएल के एमडी अभिजीत अविनाश ननोती, टाटा स्टील के चीफ- कॉरपोरेट सर्विसेज, वरुण बजाज, डीबीएमएस के चेयरपर्सन बी. चंद्रशेखर और एक्सएलआरआई एलुमनी कमेटी के ग्लोबल प्रेसिडेंट रणवीर सिन्हा भी उपस्थित थे।

गोविंदपुर के मुर्गा दुकानदार अजय श्रीवास्तव की हत्या का खुलासा

ब्राउन शुगर के धंधे को लेकर हुआ था मर्डर, दो आरोपी हुए गिरफ्तार

PHOTON NEWS JSR : छोटागोविंदपुर की सेरेंगबेड़ा बस्ती के रहने वाले अजय श्रीवास्तव हत्याकांड का टेल्को थाना की पुलिस ने शुक्रवार को खुलासा कर दिया है। गोविंदपुर के चांदनी चौक में मुर्गा दुकान चलाने वाले अजय श्रीवास्तव की हत्या 13 जनवरी की रात में कर दी गई थी और उसका शव टेल्को स्थित रामकृष्ण मिशन स्कूल के पीछे फेंक दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में दो हत्यारोपियों सिद्धार्थ कुमार और राहुल कुमार सिंह उर्फ चीकू को गिरफ्तार किया है। सिद्धार्थ कुमार छोटा गोविंदपुर के ही शेषनगर का रहने वाला है, जबकि राहुल कुमार सिंह छोटागोविंदपुर के डबल स्टोरी इलाके का रहने वाला है। पुलिस ने इनके पास से घटना में

एक मां के ताने से, दूसरा अजय श्रीवास्तव के अपमान से था दुखी

पत्रकारों को जानकारी देते पुलिस पदाधिकारी ● फोटोन न्यूज

प्रयुक्त चाकू के अलावा अजय श्रीवास्तव से लूटे गए 11 हजार 500 रुपये भी बरामद किए हैं। इसके अलावा, अजय श्रीवास्तव का मोबाइल, घटना को अंजाम देते समय आरोपी का जैकेट, बाइक और मोबाइल फोन भी बरामद किया है। पुलिस ने शुक्रवार को दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने बताया कि अजय श्रीवास्तव ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री भी करता था। हत्यारोपी सिद्धार्थ कुमार इस काम में उसकी मदद करता था। दोनों के बीच पैसे को लेकर कुछ दिन पहले विवाद हुआ था। इसके बाद अजय श्रीवास्तव ने सिद्धार्थ कुमार की चांदी की चेन छीन ली थी। सिद्धार्थ ने पुलिस को बताया कि जब वह अपने घर गया तो उसकी मां ने पूछा कि चेन कहां है। तब उसने सारी घटना बताई। इस पर उसकी मां ने कहा कि थू है तेरे ऊपर। ऐसी नशेड़ी औलाद। यह कह कर उसे घर से निकाल दिया था। इसके बाद सिद्धार्थ अजय श्रीवास्तव से बदला लेने के चक्कर में घूम रहा था। कुछ दिन पहले अजय श्रीवास्तव, सिद्धार्थ और एक अन्य हत्यारोपी राहुल कुमार सिंह बैठकर नशा कर रहे थे। तभी अजय श्रीवास्तव ने राहुल कुमार सिंह से कहा कि जब तेरे पास खर्च करने की औकात नहीं है तो पीने खाने क्यों आ जाता है। राहुल कुमार सिंह को यह बात बेहद बुरी लगी। उसने अपने आप को अपमानित महसूस किया और अजय श्रीवास्तव से बदला लेने की फिराक में था। तभी सिद्धार्थ कुमार और राहुल कुमार सिंह ने मिलकर अजय श्रीवास्तव को मौत के घाट उतारने का प्लान बनाया और उसकी हत्या कर लाश टेल्को थाना क्षेत्र के रामकृष्ण मिशन स्कूल के पीछे फेंक दी थी।

उलीडीह में चल रहा था सेक्स रैकेट, धरी गई चार युवतियां

JAMSHEDPUR : मानगो के उलीडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत सुभाष कॉलोनी स्थित ग्रीनफील्ड अपार्टमेंट में शुक्रवार की शाम पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस को सूचना मिली थी कि यहां जिस्मफरोशी का धंधा किया जा रहा है। इसी को लेकर पुलिस ने रेड कर चार युवतियों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। यह रेड ग्रीन फील्ड अपार्टमेंट के सरस्वती ब्लॉक नंबर 5 में हुई है। बताया जा रहा है कि अपार्टमेंट में दो युवक भी थे, जो पुलिस के आने की भनक लगते ही वहां से फरार हो गए। अपार्टमेंट में चार युवतियां मिलीं, जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। इन सभी को थाने ले जाया गया है। वहां उनसे पूछताछ चल रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर मामला क्या है। क्या पकड़ी गई युवतियां जिस्मफरोशी के धंधे में ही लिप्त हैं या नहीं। बताया जा रहा है कि देव विला अपार्टमेंट के लोगों ने मामले की शिकायत पुलिस से की थी और बताया था कि ग्रीन फील्ड अपार्टमेंट में देह व्यापार का धंधा होता है। इस आधार पर पटमदा डीएसपी और उलीडीह थाना प्रभारी अन्य पुलिस कर्मियों को लेकर सिविल ड्रेस में वहां पहुंचे। वहां जो युवतियां मौजूद थीं, उनसे सौदा तय किया और जब यह निश्चित हो गया कि यहां देह व्यापार होता है तो छापामारी कर चार युवतियों को पकड़ लिया गया।

लापता कैरव गांधी के परिजनों से मिले रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, सकुशल बरामदगी के दिए निर्देश

PHOTON NEWS JSR : केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ शुक्रवार को शहर पहुंचे। यहां उन्होंने 13 जनवरी से लापता सीएच एरिया (बिष्टुपुर) निवासी कैरव गांधी के परिजनों से मिले। आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (एसिया) के उपाध्यक्ष देवांग गांधी के बेटे कैरव गांधी के अपहरण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस अब तक न तो अपहरणकताओं को गिरफ्तार कर सकी है, ना कैरव गांधी का पता लगा सकी है। संजय सेठ ने परिजनों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही कैरव गांधी का पता लगा लिया जाएगा। उन्होंने परिजनों को बताया कि केंद्र सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और हर हाल में कैरव गांधी को सुरक्षित बरामद किया

कैरव गांधी के परिजन से मिलने पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ

जाएगा। पत्रकारों से बात करते हुए संजय सेठ ने कहा कि झारखंड की कानून व्यवस्था निरंतर खराब होती जा रही है। नागरिक, उद्योगपति और कारोबारी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। झारखंड के हालात ऐसे हैं और मुख्यमंत्री विदेश जाकर झारखंड में निवेश और उद्योग लगाने का निमंत्रण दे रहे हैं। संजय सेठ ने जिला पुलिस और प्रशासन को साफ निर्देश दिया कि कैरव गांधी को अविलंब खोजा जाए और उनकी सकुशल बरामदगी की जाए। इस मामले में किसी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गौरतलब है कि कैरव गांधी की कार 13 जनवरी को रात में सरायकेला-खरसावां जिले के कांदरबेड़ा से बरामद हुई थी।

लापता युवक के लिए हुआ हनुमान चालीसा का पाठ

सीएच एरिया निवासी उद्यमी देवांग गांधी के पुत्र कैरव गांधी की कुशलता के लिए शुक्रवार को बिष्टुपुर स्थित गुजराती सनातन समाज में हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करने वालों में समीर मकानी, गुनुभाई, रश्मिन रानपरा, हितेश रानपरा, मुनीभाई वसानी, प्रह्लादभाई आदि भी शामिल थे। ज्ञात हो कि कैरव गांधी 12 जनवरी से ही लापता हैं। उनके अपहरण की आशंका जताई जा रही है।

टाटानगर रेलवे स्टेशन पर ध्वस्त की गईं 32 दुकानें व मकान

टाटानगर स्टेशन पर अतिक्रमण हटाता बुलडोजर ● फोटोन न्यूज

JAMSHEDPUR : टाटानगर रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। इसे लेकर बनाए गए रि-डेवलपमेंट प्लान के तहत शुक्रवार को टाटानगर रेलवे ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस अभियान के तहत बागबेड़ा और कीताडीह की ओर जाने वाली सड़क पर बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान लगभग 32 दुकानें और मकान हटा दिए गए। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में आरपीएफ के जवान तैनात रहे। इसके अलावा, मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई थी। अभियान का कहीं विरोध नहीं हुआ। प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट जमशेदपुर अंचल के सीओ मनोज कुमार ने बताया कि 27 मकानों और पांच दुकानों को तोड़ा गया है। इसके पहले गुरुवार को इलाके में माइक से एलान कर लोगों को बता दिया गया था कि इस क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। सभी लोग अपना सामान हटा लें। ज्यादातर लोगों ने सामान हटा लिया था।

ओवरलोडिंग के खिलाफ चला अभियान, वसूले 83,650 रुपये

JAMSHEDPUR : पूर्वी सिंहभूम जिले में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के निर्देशानुसार जिला परिवहन विभाग ने शुक्रवार को परसुडीह में सघन वाहन जांच अभियान चलाया। एमवीआई सूरज हेंब्रम के नेतृत्व में विभाग की सड़क सुरक्षा टीम ने मुख्य रूप से पैसेंजर वाहनों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने (ओवरलोडिंग) पर ध्यान केंद्रित किया। इसमें 83,650 रुपये जुर्माना वसूला गया। जिला मोटरयान निरीक्षक ने बताया कि 40 से अधिक बसों, पिकअप वैन और अन्य व्यावसायिक वाहनों को रोककर उनके दस्तावेजों एवं सुरक्षा मानकों की जांच की गई। जांच के दौरान ओवरलोडिंग के दोषी पाए गए पांच वाहनों पर सख्ती बरतते हुए 83 हजार 650

रुपये का जुर्माना लगाया गया। उन्होंने वाहन चालकों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि ओवरलोडिंग न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह सड़क दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण भी है। उन्होंने चालकों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन का उद्देश्य केवल जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि लोगों को सुरक्षित सफर के प्रति सचेत करना है।

पोटका में आम के बाग को अराजक तत्वों ने लगाई आग, सारे पेड़-पौधे जले

JAMSHEDPUR : पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत पोटका प्रखंड के कोवाली थाना क्षेत्र में मझगांव में बड़ी घटना हुई है। अराजक तत्वों ने मझगांव में आम के बगीचे में आग लगा दी, जिससे बगीचे के सारे पेड़-पौधे जलकर खाक हो गए। बाग के मालिक पोलटू मंडल ने इस मामले में कोवाली थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पोलटू का कहना है कि पुरानी रंजिश के चलते उनके बाग में आग लगाई गई है। घटना 10 जनवरी की बताई जा रही है। एफआईआर दर्ज होने के बाद थाना से पुलिसकर्मी शुक्रवार को बगीचे में पहुंचे और बाग के मालिक सहित स्थानीय ग्रामीणों से पूछताछ की। पुलिस ने पोलटू मंडल के आवेदन पर अनूप कुमार मंडल, महितोस मंडल और जयंत मंडल के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है।

आदित्यपुर में डिफेंस कॉन्क्लेव शुरू, उद्यमियों ने दिखाई रुचि

कॉन्क्लेव में संजय सेठ को स्मृति चिह्न भेंट करते उद्यमी ● फोटोन न्यूज

SERAIKELA : आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर परिसर में दो दिवसीय एमएसएमई डिफेंस कॉन्क्लेव-2026 लगा है, जिसका उद्घाटन शुक्रवार को केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने किया। समारोह को संबोधित करते हुए संजय सेठ ने कहा कि आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में भारत का इंडस्ट्रियल कैपिटल बनने की पूरी क्षमता है। जमशेदपुर अब केवल टाटा मोटर्स या ऑटोमोबाइल हब तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे रक्षा उपकरणों का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना हमारा लक्ष्य है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि अभी इंडिया, दुनिया के 92 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है और पिछले 8 सालों में स्टार्टअप की संख्या 800 से बढ़कर हो गई है। इसमें भारत तीसरे स्थान पर है। जियाडा के क्षेत्रीय निदेशक प्रेम रंजन ने बताया कि 5000 एकड़ में फैले इस औद्योगिक क्षेत्र की 1500 इकाइयां और 50 हजार से अधिक श्रमिक, देश की रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं।

टाटा स्टील जूलॉजिकल सोसाइटी ने मनाया 36वां स्थापना दिवस

JAMSHEDPUR : टाटा स्टील जूलॉजिकल सोसाइटी (टीएसजेडएस) ने शुक्रवार को टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क (टीएसजेडपी) में 36वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस सोसाइटी की स्थापना 16 जनवरी 1990 को टाटा स्टील के पूर्व सीएमडी स्व. रूसी मोदी द्वारा की गई थी, जो वन्यजीव संरक्षण, शिक्षा और जन सहभागिता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कार्यक्रम की शुरूआत केक कटिंग समारोह के साथ हुई, जिसमें टीएसजेडएस वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष रघुनाथ पांडेय, टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क के निदेशक डॉ. नईम अख्तर तथा टीएसजेडएस के एचआर सदस्य विकास कुमार शामिल थे। इस अवसर पर क्यूरेटर डॉ. संजय कुमार महतो सहित चिड़ियाघर के अन्य कर्मचारी भी उपस्थित रहे। समारोह के दौरान, करीम सिटी कॉलेज के जूलॉजी एवं बॉटनी विभाग के 80 स्नातक विद्यार्थियों को, जिन्होंने चिड़ियाघर में अपना इंटर्नशिप कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया था, प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उत्कृष्ट योगदान और समर्पित सेवाओं के लिए समरंजन महतो को बेस्ट एम्प्लॉयी ऑफ द ईयर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।

शिक्षा जमशेदपुर के निजी स्कूलों में नामांकन की प्रतीक्षा खत्म, 7,000 सीटों के लिए आए थे 72,000 से अधिक आवेदन

आज जारी होगी प्रवेश कक्षा के लिए चयनित बच्चों की सूची

PHOTON NEWS JSR : निजी स्कूलों में एंट्री लेवल कक्षाओं (नर्सरी/एलकेजी) में नामांकन के लिए अभिभावकों का चार महीने का लंबा इंतजार शनिवार को समाप्त होने जा रहा है। शहर के विभिन्न स्कूलों में लॉटरी की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है और अब शनिवार को 7000 उपलब्ध सीटों के लिए चयनित बच्चों की अंतिम सूची सार्वजनिक की जाएगी।

विभिन्न स्कूलों ने परिणाम घोषित करने के लिए अलग-अलग समय निर्धारित किया है। सूचना के अनुसार, लोयोला स्कूल, टेल्को सबसे पहले सुबह 8.30 बजे अपनी सूची जारी करेगा। इसके बाद लोयोला स्कूल, बिष्टुपुर सुबह 9 बजे और डीबीएमएस इंग्लिश स्कूल दोपहर 3 बजे के बाद

कड़ी प्रतिस्पर्धा और नामांकन प्रक्रिया

इस वर्ष नामांकन के लिए प्रतिस्पर्धा बेहद कठिन रही है। सामान्य श्रेणी की महज 7,000 सीटों के लिए शहरभर से 72,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक सीट के लिए औसतन 10 दावेदार कतार में हैं। लॉटरी में चयनित बच्चों का नामांकन 31 जनवरी तक पूरा किया जाना है।

परिणामों की घोषणा करेगा। अन्य स्कूल भी इसी अंतराल में अपने नोटिस बोर्ड और आधिकारिक वेबसाइटों पर सूची अपलोड करेंगे।

जानें, स्कूल कब जारी करेंगे लिस्ट

लोयोला स्कूल बिष्टुपुर	:	सुबह 9 बजे के बाद
लोयोला स्कूल टेल्को	:	सुबह 8.30 बजे के बाद
राजेंद्र विद्यालय	:	दोपहर 2 बजे
तारापोर स्कूल एग्रिको	:	सुबह 10 बजे के बाद
जेएच तारापोर धातकीडीह	:	सुबह 11 बजे के बाद
कारमेल जूनियर कॉलेज	:	सुबह 11 बजे के बाद
हिलटॉप स्कूल	:	सुबह 10 बजे के बाद
जुस्को स्कूल साउथ पार्क	:	सुबह 11 बजे के बाद
चिन्मया साउथ पार्क	:	सुबह 11 बजे के बाद
केरला पब्लिक स्कूल, कदमा	:	सुबह 10 बजे के बाद
केरला पब्लिक स्कूल, मानगो	:	सुबह 10 बजे के बाद
केरला समाजम मॉडल स्कूल	:	दोपहर 11 बजे के बाद
दयानंद पब्लिक स्कूल	:	दोपहर 11 बजे के बाद
मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल	:	दोपहर 11 बजे के बाद
गुलमोहर हाईस्कूल	:	दोपहर 1 बजे के बाद
सेक्रेड हार्ट कावेंट स्कूल	:	सुबह 11 बजे के बाद
डीबीएमएस इंग्लिश स्कूल कदमा	:	दोपहर 3 बजे के बाद

तीन माह में होगी अल्पसंख्यक स्कूलों के जर्जर भवनों की मरम्मत

JAMSHEDPUR : राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्ला खान ने कहा है कि पूर्वी सिंहभूम जिले में जितने भी जर्जर अल्पसंख्यक स्कूल हैं, उनके भवनों की मरम्मत का काम तीन महीने के अंदर शुरू कर दिया जाएगा। यही नहीं अल्पसंख्यक स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर की जाएगी। 3 महीने के अंदर शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए ठोस पहल शुरू होगी। आयोग के अध्यक्ष इस मुद्दे को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाएंगे। ये बातें हिदायतुल्ला खान ने जमशेदपुर सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक करने के बाद शुक्रवार को पत्रकारों से कहीं। उन्होंने कहा कि जिले में अल्पसंख्यक स्कूलों की स्थिति काफी जर्जर हो गई है।

कहीं जरूरत से ज्यादा मूंगफली तो नहीं खा रहे आप

जानें एक दिन में कितनी खाना सही?

सर्दियों के मौसम में मूंगफली खाना सभी को अच्छा लगता है. गर्म-गर्म मूंगफली सर्दियों में खाने से अलग ही स्वाद मिलता है. जैसे ही ठंड दस्तक देती है, सड़कों और मार्केटों में मूंगफली, गजक और रेवड़ी बिकनी शुरू हो जाती है और लोग बड़ी मात्रा में इसका सेवन करने लगते हैं. मूंगफली हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होती है. यह शरीर को कई बीमारियों से बचाने में मदद करती है, जैसे हार्ट की बीमारियां, हड्डियों की मजबूती और पाचन से जुड़ी दिक्कतें. लेकिन ठंड के मौसम में जरूरत से ज्यादा मूंगफली का सेवन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है और शरीर पर हानिकारक असर डालता है.

रोज कितनी मूंगफली खाना सही है?

मूंगफली का सेवन करने से शरीर पर कई सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं. यह हड्डियों की मजबूती से लेकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव में भी मददगार मानी जाती है. हालांकि, ज्यादा मात्रा में मूंगफली खाने से कई तरह की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है. डॉक्टर्स के अनुसार, हर व्यक्ति को अपने डेली रूटीन और डाइट में सिर्फ एक मुट्ठी मूंगफली ही खानी चाहिए. यानी एक दिन में लगभग 30 से 50 ग्राम मूंगफली का सेवन करना सही माना जाता है. आप चाहें तो इससे भी कम मात्रा, यानी 25 से 30 ग्राम मूंगफली का सेवन कर सकते हैं. इतनी मात्रा में मूंगफली खाने से वजन बढ़ने जैसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता.

ज्यादा मूंगफली खाने से वजन बढ़ना

अगर कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा मूंगफली का सेवन करता है, तो उसे वजन बढ़ने जैसी समस्या हो सकती है. मूंगफली में कैलोरी और फैट की मात्रा ज्यादा होती है. अगर आप रोज जरूरत से ज्यादा मूंगफली खाते हैं, तो धीरे-धीरे आपके वजन में बढ़ोतरी हो सकती है.

जोड़ों के दर्द में मूंगफली से बचें

अगर किसी व्यक्ति को जोड़ों का दर्द या हड्डियों से जुड़ी बीमारियां हैं, जैसे आर्थराइटिस या गठिया, तो ऐसे लोगों को मूंगफली का सेवन बहुत कम या बिल्कुल नहीं करना चाहिए. मूंगफली में मौजूद प्रोटीन और यूरिक एसिड जोड़ों के दर्द को बढ़ा सकते हैं.

पाचन से जुड़ी समस्याएं

ज्यादा मात्रा में मूंगफली खाने से पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. अगर आप जरूरत से ज्यादा मूंगफली का सेवन करते हैं, तो गैस, कब्ज और एसिडिटी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

लीवर पर हानिकारक असर

ज्यादा मात्रा में मूंगफली के सेवन से हमारे लीवर पर हानिकारक असर हो सकता है. इससे लीवर में फैट जमा होने लगता है, जो फैटी लीवर जैसी समस्या का कारण बन सकता है और लीवर की कार्यक्षमता भी कम हो सकती है. इसलिए मूंगफली का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए.

तेज हवा या घने कोहरे में किसान ना करें ये काम, कृषि विभाग ने किया अलर्ट

घने कोहरे की चादर इन दिनों देश के कई हिस्सों पर छाई हुई है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (ढ्डस्ष्ठ) ने कई राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है. कोहरे और बढ़ती ठंड ने आमजन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. विजिबिलिटी घटने से सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो रहे हैं. किसानों पर भी मौसम के बदलाव का असर पड़ सकता है. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किसानों के लिए कुछ सुझाव शेयर किए हैं.

दवा के छिड़काव से बचें किसान

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किसानों के लिए जानकारी शेयर की है. कृषि विभाग ने बताया कि किसानों को मौसम देखकर दवा का छिड़काव करना चाहिए. तेज हवा या कोहरे के समय दवा का छिड़काव करने से बचना चाहिए. शांत मौसम में दवा के छिड़काव करने से दवा का पूरा असर फसल पर होता है. इससे किसानों का खर्च भी बचता है.

किसानों को मौसम विभाग की साप्ताहिक सलाह देखकर बुवाई का समय तय करना चाहिए. यह नुकसान को कम करने में मदद कर सकता है. बारिश, ठंड की लहर या गर्मी की बढ़ोतरी जैसी परिस्थितियों में सही फैसले लेने से फसल सुरक्षित रहती है. इससे सिंचाई और दवा पर होने वाला अतिरिक्त खर्च भी बचाया जा सकता है.

खेत में लगा है सोलर पैनल तो भूलकर भी ना करें ये गलतियां, होगा भारी नुकसान!

सोलर पैनल किसानों के लिए लंबे समय का निवेश होते हैं, इसलिए इनके साथ कई सावधानियां रखनी जरूरी होती है. कई बार सफाई के समय की गई छोटी-सी लापरवाही भी भारी नुकसान का कारण बन सकती है. सही तरीके से की गई सफाई सोलर पैनल को सालों तक बेहतर प्रदर्शन देने में मदद करती है. आइए जानते हैं सोलर पैनल की सफाई के वक्त किन गलतियों से बचना चाहिए?

खेती में बिजली की बढ़ती मांग और डीजल की ऊंची कीमतों से बचने के लिए किसान तेजी से सोलर पैनल अपना रहे हैं. सिंचाई हो या पंप चलाना, सोलर ऊर्जा आज किसानों के लिए बड़ी राहत बन रही है, लेकिन सोलर पैनल से अधिकतम बिजली पाने के लिए उसकी सफाई नियमित और सही तरीके से करना जरूरी होता है.

सतह पर धूल, मिट्टी, परागकण और पक्षियों की बीट से उत्पादन क्षमता घट सकती है. सफाई के दौरान की गई छोटी-सी गलती भी पैनल को नुकसान पहुंचा सकती है और किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है. ऐसे में किसानों को कई गलतियों को करने से बचना चाहिए.

खुरदरे ब्रश का इस्तेमाल करने से बचें

सोलर पैनल की सफाई के लिए झाड़ू, सख्त ब्रश या बोरे के कपड़े जैसी चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल न करें. सोलर पैनल की ऊपरी सतह कांच की होती है, जिस पर एक खास कोटिंग लगी होती है. खुरदरी चीजों से सफाई करने पर सतह पर खरोंच पड़ सकती है और इसकी दक्षता स्थायी रूप से कम हो सकती है. सफाई के लिए हमेशा मुलायम कपड़े, स्पंज या माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए.

तेज केमिकल और साबुन का इस्तेमाल न करें

पैनल को चमकाने के लिए डिटर्जेंट, फिनाइल, एसिड या अन्य केमिकल का प्रयोग न करें. यह सोलर पैनल को नुकसान पहुंचा सकता है. केमिकल्स पैनल की कोटिंग को खराब कर सकते हैं, जिससे धूप को सोखने की क्षमता पर असर हो सकता है. सफाई के लिए साफ पानी या बहुत हल्के साबुन का घोल इस्तेमाल किया जा सकता है.

तेज धूप में सफाई न करें

तेज धूप में सोलर पैनल अत्यधिक गर्म हो जाते हैं. ऐसे में पानी डालने से थर्मल शॉक लग सकता है, जिससे कांच चटकने का खतरा रहता है. इसके अलावा गर्म पैनल पर पानी डालने से दाग भी पड़ सकते हैं. सफाई के लिए सुबह या शाम का समय उचित माना जाता है.

बिजली चालू न रखें

सफाई के दौरान सोलर सिस्टम को चालू छोड़ना बेहद खतरनाक हो सकता है. गीले हाथों या पानी के संपर्क में बिजली प्रवाहित होने से करंट लगने का खतरा रहता है. इसलिए सफाई शुरू करने से पहले सोलर सिस्टम को पूरी तरह बंद करना और इन्वर्टर का स्विच ऑफ करना सुरक्षित माना जाता है.

पैनल पर चढ़कर सफाई करने से बचें

खेतों में लगे सोलर पैनल अक्सर ऊंचाई पर या ढांचे पर लगाए जाते हैं. कई लोग सीधे पैनल पर चढ़कर सफाई करने लगते हैं, जिससे पैनल टूटने या ढांचे के कमजोर होने का जोखिम बढ़ सकता है. सुरक्षित सफाई के लिए हमेशा नीचे से काम करें या सीढ़ी की मदद लें.

तेज प्रेशर के पानी से बचें

सोलर पैनल की सफाई करते समय मोटर या पाइप से तेज प्रेशर वाला पानी इस्तेमाल करना नुकसानदायक हो सकता है. इससे पैनल की सीलिंग खराब हो सकती है और पानी अंदर घुस सकता है. सुरक्षित सफाई के लिए हमेशा हल्के प्रेशर से पानी डालना चाहिए.

ठंड-कोहरे में खराब नहीं होगा तुलसी का पौधा, हल्दी का उपाय करेगा कमाल, जानें तरीका

सर्दियों में तुलसी के पौधे की देखभाल चुनौतीपूर्ण होती है. ज्यादा नमी और कम धूप से पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और फंगस लग जाता है. हल्दी एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक और एंटीफंगल है, जो तुलसी के पौधे को फंगस से बचाता है और उसे मजबूत बनाता है. आइए जानते हैं हल्दी के उपाय से कैसे तुलसी के पौधे को हरा-भरा रखा जा सकता है.

तुलसी का पौधा सिर्फ पूजा के लिए नहीं, बल्कि आयुर्वेद में भी एक औषधीय दवा के तौर पर उपयोगी माना जाता है. लगभग हर भारतीय घर में तुलसी का पौधा लगाया जाता है. घने कोहरे और ठंड के मौसम में तुलसी के पौधे की देखभाल करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है. ज्यादा नमी, कम धूप और ठंडी हवा की वजह से तुलसी के पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, उन पर फंगस लग जाता है और पौधा मुरझाने लगता है. ऐसे में हल्दी का एक घरेलू नुस्खा तुलसी के पौधे को नया जीवन दे सकता है. हल्दी प्राकृतिक तरीके से फंगस को रोकती है और पौधे को मजबूत बनाती है.

कोहरे में तुलसी को नुकसान क्यों होता है?

कोहरे की वजह से हवा में बहुत नमी रहती है. यह नमी मिट्टी में ज्यादा देर तक रहती है, जिससे जड़ें सड़ सकती हैं. धूप कम मिलने से पौधा ठीक से खाना नहीं बना पाता.साथ ही फंगस लगने से पत्तियों पर सफेद-काले धब्बे पड़ जाते हैं और तना कमजोर हो जाता है.

तुलसी के लिए हल्दी फायदेमंद कैसे है?

हल्दी को प्राकृतिक एंटीसेप्टिक और एंटीफंगल माना जाता है. हल्दी में करक्यूमिन नाम का तत्व होता है जो प्राकृतिक रूप से बैक्टीरिया और फंगस को मारता है. इससे पौधे की बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ती है.

हल्दी का सही इस्तेमाल कैसे करें?

तुलसी के लिए हल्दी का प्रयोग बहुत सरल है लेकिन मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है. एक गिलास गुनगुने पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाएं. इस पानी को अच्छे से घोल लें ताकि हल्दी नीचे न बैठे. हफ्ते में एक बार इस पानी को तुलसी की जड़ में धीरे-धीरे डालें. ध्यान रखें कि मिट्टी पहले से बहुत ज्यादा गीली न हो. अगर आप चाहें तो सूखी हल्दी का पाउडर भी सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए एक चुटकी हल्दी पाउडर मिट्टी के ऊपर छिड़कें. फिर हल्के हाथ से मिट्टी को खुरच कर मिला दें.

इनमें से कोई भी तरीका नियमित अपनाने से 10-15 दिनों में आपको फर्क दिखने लगेगा. पत्तियां फिर से हरी और चमकदार हो जाएंगी. साथ ही नई पत्तियां भी आएंगी और पौधा मजबूत हो जाएगा.

कुछ और जरूरी टिप्स

तुलसी को ऐसी जगह रखें जहां सुबह की धूप कम से कम 2-3 घंटे मिले.

ज्यादा पानी न डालें. मिट्टी सूखने पर ही पानी दें.

बहुत ठंडी हवा या पाले से बचाने के लिए रात में पौधे को किसी कपड़े से ढक दें.

पीली या खराब पत्तियों को समय पर तोड़कर हटा दें.

इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो सर्दियों में भी तुलसी का पौधा हरा-भरा रहेगा.

दूध के लिए पालें गाय की ये 5 देसी नस्ल, पशुपालकों को मिलेगा बढ़िया मुनाफा

गाय की सही नस्ल का पालन करने से पशुपालकों को कई तरह के फायदे मिलते हैं. सही नस्ल न केवल बेहतर और पौष्टिक दूध उत्पादन करती है, बल्कि किसानों को अधिक मुनाफा कमाने में भी मदद करती है. पशुपालक अपनी जरूरत के अनुसार बेस्ट नस्ल चुन सकते हैं. आइए जानते हैं भारत की 5 खास देसी गायों की नस्लों के बारे में, जिनका पालन करके आपको लाभ मिल सकता है.

भारत में गायों की कई देसी नस्लें पाई जाती हैं, जिनकी अपनी-अपनी विशेषताएं होती हैं. पशुपालक अपनी जरूरत और क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुसार इन नस्लों का पालन कर सकते हैं और इनसे भरपूर लाभ कमा सकते हैं. सही नस्ल की गाय चयन न केवल दूध उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है, बल्कि पशुपालक को आर्थिक रूप से मजबूत भी बना सकता है. पशुपालक गाय की खास नस्लों की जानकारी रखकर उनका पालन करें, तो उन्हें बेहतर गुणवत्ता वाला दूध, अधिक मात्रा में उत्पादन, और लंबे समय तक फायदे मिल सकते हैं. पशुपालन और डेयरी विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म

मालवी गाय

भारत की एक स्वदेशी नस्ल है, जिसका नाम इसके मूल क्षेत्र मालवा (मध्य प्रदेश) से जुड़ा है. यह खास गाय मजबूत शरीर और उचित दूध उत्पादन जैसी खूबियों के कारण भारतीय पशुपालन में अपनी खास पहचान रखती है.

थारपारकर गाय

थारपारकर गाय भारत की एक प्रमुख देसी नस्ल है, जिसका मूल क्षेत्र राजस्थान का थर मरुस्थल माना जाता है. यह नस्ल कठोर जलवायु में भी आसानी से ढल जाती है और अपनी मजबूत रोग-प्रतिरोधक क्षमता के लिए प्रसिद्ध है. इस गाय का रंग सफेद से हल्का स्लेटी होता है. यह न केवल उच्च गुणवत्ता वाला दूध देती है बल्कि कृषि कार्यों में भी उपयोगी साबित हो सकती है. थारपारकर गाय संतुलित देखभाल और सही पोषण मिलने पर पर्याप्त मात्रा में बेहतर दूध देती है. इससे पशुपालकों की आय बढ़ने में मदद मिलती है.

गिर गाय

गिर गाय भारत की सबसे मशहूर देसी दुग्ध नस्लों में से एक है. इसका मूल क्षेत्र गुजरात के गिर जंगल और आसपास का इलाका माना जाता है. यह नस्ल खास तौर पर ज्यादा दूध देने के लिए जानी जाती है और लंबे समय से भारतीय खेती और पशुपालन में अहम भूमिका निभाती रही है. गिर गाय का शरीर मजबूत होता है और इसका रंग लाल-भूरा होता है. यह गाय कम चारे में भी अच्छा दूध देने की क्षमता रखती है.यह गाय एक दिन में लगभग 50 लीटर तक दूध दे सकती है.

देओनी गाय

देओनी गाय, भारत की एक मजबूत देसी नस्ल है. यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र में पाई जाती है. ये नस्ल कम देखभाल में भी अच्छा दूध उत्पादन करती है और अपनी रोग-प्रतिरोधक क्षमता के लिए जानी जाती है. देओनी गाय का दूध पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो आपके परिवार की सेहत को बेहतर बना सकता है और साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद करता है. छोटे और मध्यम स्तर के किसानों के लिए यह नस्ल भरोसेमंद और लाभकारी साबित हो सकती है. यह गाय सालाना लगभग 1500 लीटर तक दूध उत्पादन कर सकती है.

साहीवाल गाय

साहीवाल गाय भारत की मशहूर देसी नस्लों में से एक है. इस गाय का रंग लाल-भूरा से गहरे भूरा होता है. यह नस्ल ज्यादा दूध देने के लिए जानी जाती है।साहीवाल गाय गर्म मौसम को आसानी से सह लेती है. इस गाय में परजीवियों से लड़ने की क्षमता होती है. इसका स्वभाव भी शांत माना जाता है. इसलिए इसे पालना आसान बन सकता है. यह गाय पशुपालकों के लिए बेहतर मानी जाती है.

ईरान की उथल-पुथल एवं अमेरिका से टकराव गंभीर चुनौती

ललित गर्ग

ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता टकराव केवल द्विपक्षीय तनाव नहीं है, बल्कि इसके दुष्प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ सकते हैं। इस संघर्ष से पश्चिम एशिया में युद्ध का खतरा बढ़ता है, जिसका सीधा असर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और तेल की कीमतों पर पड़ सकता है।

ईरान में बार-बार उभरती उथल-पुथल केवल किसी एक घटना, किसी एक फैसले या किसी एक पीढ़ी का आक्रोश नहीं है, बल्कि यह उस ऐतिहासिक, वैचारिक और भू-राजनीतिक संरचना की परिणति है, जिसने 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से इस देश को आकार दिया है। आज जब सड़कों पर विरोध के दृश्य, सोशल मीडिया पर आक्रोश और पश्चिमी विश्लेषकों की ओर से सत्ता परिवर्तन की अटकलें तेज हैं, तब यह समझना जरूरी हो जाता है कि ईरान का संकट साधारण आंतरिक असंतोष नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति-संतुलन से गहराई से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ईरान की आंतरिक उथल-पुथल एवं अस्थिरता के साथ-साथ उसका अमेरिका के साथ टकराव युद्ध की स्थितियों एवं वैश्विक असंतुलन का बड़ा कारण बन रहा है।

ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता टकराव केवल द्विपक्षीय तनाव नहीं है, बल्कि इसके दुष्प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ सकते हैं। इस संघर्ष से पश्चिम एशिया में युद्ध का खतरा बढ़ता है, जिसका सीधा असर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और तेल की कीमतों पर पड़ सकता है। होर्मुज जलडमरूमध्य में किसी भी तरह की अस्थिरता अंतरराष्ट्रीय व्यापार की धमनियों को बाधित कर सकती है, जिससे महंगाई और आर्थिक मंदी का खतरा बढ़ेगा। इसके साथ ही यह टकराव क्षेत्रीय देशों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से युद्ध में खींच सकता है, जिससे शरणार्थी संकट, आतंकवाद और साम्प्रदायिक तनाव गहराने की आशंका है। महाशक्तियों के परस्पर टकराव की स्थिति में विश्व राजनीति और अधिक ध्रुवीकृत होगी, अंतरराष्ट्रीय सहयोग कमजोर पड़ेगा और शांति की जगह अविश्वास व सैन्य प्रतिस्पर्धा का वातावरण बनेगा, जिसका खामियाजा अंततः पूरी मानवता को भुगतना पड़ सकता है।

1979 की इस्लामिक क्रांति ने ईरान में केवल शाह मोहम्मद रजा पहलवी को सत्ता से हटाकर एक नई सरकार स्थापित नहीं की थी, बल्कि एक ऐसी वैचारिक-राजनीतिक संरचना रची थी, जिसमें धर्म, राजनीति और सुरक्षा-तंत्र एक-दूसरे में घुलमिल गए। ह्यविलायत-ए-फकीहह्ल की अवधारणा के तहत सर्वोच्च धार्मिक नेतृत्व को अंतिम राजनीतिक अधिकार सौंपा गया। इसी व्यवस्था के संरक्षण और विस्तार के लिए इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी को खड़ा किया गया, जो समय के साथ केवल सैन्य शक्ति नहीं, बल्कि आर्थिक, राजनीतिक और वैचारिक ताकत का भी केंद्र बन गया। यही कारण है कि ईरान की व्यवस्था को केवल सरकार या शासन कहकर नहीं समझा जा सकता; यह एक संपूर्ण तंत्र है, जिसे हटाने के लिए केवल विरोध-प्रदर्शन पर्याप्त नहीं होते।

ईरान ने पिछले चार दशकों में कई बड़े जनांदोलन देखे हैं। 2009 का ग्रीन मूवमेंट, 2017-18 की आर्थिक असंतोष की

लहर, 2019 में ईंधन मूल्य वृद्धि के खिलाफ उग्र प्रदर्शन और 2022 में सामाजिक स्वतंत्रताओं को लेकर उठी आवाजेंकृहर बार यह माना गया कि शायद अब व्यवस्था डगमगाएगी। लेकिन हर बार वही सत्ता, वही ढांचा और वही शक्ति-संतुलन कायम रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान में सुरक्षा-तंत्र राज्य से अलग नहीं, बल्कि राज्य का ही विस्तार है। अरब स्प्रिंग के दौरान मिस्र या तुर्किए में सेनाओं ने अंततः राष्ट्र-राज्य को बचाने का रास्ता चुना, लेकिन ईरान में आईआरजीसी खुद को क्रांति और इस्लामिक रिपब्लिक का संरक्षक मानती है, न कि केवल सीमाओं की रक्षा करने वाली संस्था। फिर भी यह कहना गलत होगा कि ईरान की व्यवस्था पर कोई दबाव नहीं है। वास्तव में, आज का दबाव पहले से कहीं अधिक जटिल और गहरा है। इसका सबसे बड़ा कारण है पीढ़ीगत बदलाव। ईरान की आबादी का बड़ा हिस्सा युवा है, जिसने 1979 की क्रांति न देखी है और न ही उससे भावनात्मक रूप से जुड़ा है। उनके लिए क्रांति कोई जीवित स्मृति नहीं, बल्कि इतिहास की किताबों का अध्याय है। उनकी आकांक्षाएं इंटरनेट, वैश्विक संस्कृति, शिक्षा, रोजगार और व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं से प्रेरित हैं। जब ये आकांक्षाएं एक सख्त सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था से टकराती हैं, तो असंतोष स्वाभाविक रूप से जन्म लेता है।

इस असंतोष को और तीखा बनाया है दशकों से चले आ रहे अमेरिकी और पश्चिमी प्रतिबंधों ने। इन प्रतिबंधों ने ईरान की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। तेल निर्यात सीमित हुआ, विदेशी निवेश रुका, मुद्रा कमजोर पड़ी और महंगाई ने आम नागरिक की कमर तोड़ दी। विकास और आधुनिकीकरण की गति धीमी पड़ी, जिससे खासकर शहरी मध्यम वर्ग और युवा वर्ग में भविष्य को लेकर निराशा बढ़ी। आज ईरान के कई नागरिक यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अमेरिका और इजराइल के साथ अंतहीन दुश्मनी का बोझ उन्हीं के कंधों पर डाला जाना जरूरी है। धीरे-धीरे यह वैचारिक टकराव राष्ट्रवादी गौरव से अधिक सामाजिक बोझ के रूप में देखा जाने लगा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव इस पूरे परिदृश्य को और खतरनाक बना देता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने के आदेश और सैन्य हस्तक्षेप के संकेतों ने पश्चिम एशिया को एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया है। ईरान आज 1979 के बाद से शायद सबसे गंभीर बाहरी दबाव का सामना कर रहा है। यह टकराव केवल दो देशों के बीच का संघर्ष नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा भू-राजनीतिक खेल बन चुका है, जिसमें महाशक्तियां अपने-अपने हित साधना चाहती हैं।

अकसर यह धारणा बनाई जाती है कि बाहरी हस्तक्षेप से ईरान में सत्ता परिवर्तन संभव है। लेकिन इतिहास बताता है कि ईरान में विदेशी दखलअंदाजी ने हमेशा उल्टा असर डाला है। 1953 में मोसादेग सरकार के तख्तापलट से लेकर आज तक, ह्यविदेशी साजिशह्ल का कथानक ईरानी राष्ट्रवाद को मजबूत करता रहा है। बाहरी समर्थन से होने वाले आंदोलनों को जनता का व्यापक और स्थायी समर्थन नहीं मिल पाता। यही वजह है कि विपक्षी नेतृत्व, जो अक्सर देश से बाहर बैठा होता है, ईरान के भीतर विश्वसनीय विकल्प नहीं बन सका। इसके अलावा, ईरान वेनेजुएला नहीं है। यह एक बड़ा, संगठित और रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण देश है, जिसकी पकड़ इराक, सीरिया, लेबनान और यमन तक फैली हुई है। यहां किसी भी प्रकार का सैन्य हस्तक्षेप पूरे पश्चिम एशिया को आग में झोंक सकता है। इजराइल, खाड़ी देश, अमेरिका और यूरोपीय शक्तियां-सब इसके प्रभाव में आएंगे। चीन और रूस भी एक अस्थिर ईरान नहीं चाहते, क्योंकि वह उनके क्षेत्रीय और वैश्विक हितों के खिलाफ होगा। यह बहुध्रुवीय संतुलन ईरान की व्यवस्था को एक अप्रत्यक्ष सुरक्षा कवच प्रदान करता है।

ईरान के भीतर आम नागरिकों का गुस्सा अब केवल आर्थिक कुप्रबंधन या भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं रह गया है। एक बड़ा वर्ग यह मानने लगा है कि शासन की प्राथमिकताएं आम लोगों की जरूरतों से कट चुकी हैं। जब नागरिक भोजन, रोजगार और सम्मानजनक जीवन की मांग कर रहे हों, तब बाहरी दुश्मनों के खिलाफ वैचारिक युद्ध और यहूदी-विरोधी राजनीति उन्हें खोखली प्रतीत होती है। कई ईरानी मानते हैं कि इसी नीति ने देश को अंतरराष्ट्रीय अलगाव में धकेला और आर्थिक बबार्दी को जन्म दिया। यदि ईरान में बाहरी मदद से सत्ता परिवर्तन की कोशिश होती है, तो इसके परिणाम केवल ईरान तक सीमित नहीं रहेंगे। मध्य पूर्व में शक्ति-संतुलन बुरी तरह बिगड़ सकता है। शिया-सुन्नी तनाव, इजराइल-ईरान संघर्ष और वैश्विक ऊर्जा बाजार-सब पर इसका गहरा असर पड़ेगा। भारत के लिए यह स्थिति विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण होगी। भारत के ईरान के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंध रहे हैं। चाबहार बंदरगाह से लेकर ऊर्जा सुरक्षा तक, ईरान भारत की विदेश नीति में अहम स्थान रखता है। ऐसे में भारत को अत्यंत सावधानी के साथ अपने रणनीतिक संतुलन को बनाए रखना होगा, ताकि वह किसी एक ध्रुव का मोहरा बनने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सके। अंततः, ईरान की वर्तमान उथल-पुथल यह संकेत देती है कि व्यवस्था पर दबाव वास्तविक है, लेकिन तात्कालिक पतन की भविष्यवाणियां अक्सर जल्दबाजी साबित होती हैं। यह संघर्ष केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि पहचान, वैचारिक दिशा और भविष्य की कल्पना का संघर्ष है। ईरान का भविष्य संभवतः न तो अचानक क्रांति से बदलेगा और न ही केवल दमन से स्थिर रहेगा। यह एक लंबी, जटिल और अंतर्द्वंद्वों से भरी प्रक्रिया होगी, जिसके परिणाम न केवल ईरान, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित करेंगे।

(लेखक, पत्रकार, स्तंभकार)

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

संपादकीय

संवैधानिक व्यवस्था दायरे में नहीं

कोलकाता की घटना संघीय ढांचे के चरमराने का संकेत है। संबंधित पक्ष ऐसे विवादों से सड़कों पर निपटने लगें, तो उसका अर्थ है कि बात संवैधानिक व्यवस्था के दायरे में नहीं रह गई है। आखिर इस तरह की नौबत क्यों आई? कोलकाता में आई-पैक के दफ्तर पर प्रवर्तन निदेशालय के छापे का मुकाबला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सड़क पर उतर कर किया। ऐसा शायद पहली बार हुआ, जब एक केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई के बीच किसी मुख्यमंत्री ने इस तरह का दखल दिया हो। उस घटना के बाद से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने इसको लेकर एक बड़ा राजनीतिक अभियान छेड़ रखा है। उधर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट की पनाह ली है। ईडी का इल्जाम है कि आई-पैक एजेंसी से जुड़े व्यक्तियों ने हवाला के जरिए अवैध रूप से धन का लेन-देन किया है। जबकि तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि चूंकि आई-पैक को उसने अपने विधानसभा चुनाव अभियान के प्रबंधन का ठेका दिया है और इसलिए उसके पास पार्टी की रणनीति संबंधी आंकड़े हैं, तो उन्हें ही चुराने ईडी वहां गई थी। तृणमूल की शिकायत पर कोलकाता पुलिस ने दस्तावेजों की चोरी का केस दर्ज किया है। उसने उन ईडी तथा केंद्रीय शस्त्र बल के कर्मियों की पहचान शुरू कर दी है, जो आई-पैक के दफ्तर पर गए। तो इस रूप में ये मामला केंद्र और राज्य सरकारों के बीच टकराव में तब्दील हो गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि तृणमूल ने अपनी शिकायत को बयानों या कानूनी चुनौती तक सीमित नहीं रखा। उसकी नेता एवं मुख्यमंत्री ने प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से ईडी के छापे में रुकावट डाली। यह घटना देश के संघीय ढांचे के चरमराने का संकेत है। संबंधित पक्ष ऐसे विवादों से सड़कों पर निपटने लगें, तो उसका अर्थ है कि बात संवैधानिक व्यवस्था के दायरे में नहीं रह गई है। यह गंभीर विचार-विमर्श का विषय है कि ये नौबत क्यों आई? साफ वजह राजनीतिक वर्ग में आपसी भरोसे का टूट जाना है। विपक्षी खेमों में आम धारणा है कि केंद्रीय एजेंसियां सत्ताधारी भाजपा के सियासी मकसद को साधने का औजार बन गई हैं। इस दौर में कानूनों की व्याख्या के क्रम में न्यायपालिका ने भी राजनीतिक परिदृश्य की अनदेखी कर तकनीकी नजरिया अपना रखा है।

चिंतन-मनन

द्वंद्व के बीच शांति की खोज

केवल ज्ञान की बातें करों। किसी व्यक्ति के बारे में दूसरे व्यक्ति से सुनी बातें मत दोहराओ। जब कोई व्यक्ति तुम्हें नकारात्मक बातें कहे, तो उसे वहीं रोक दो, उस पर वास भी मत करो। यदि कोई तुम पर कुछ आरोप लगाये, तो उस पर वास न करो। यह जान लो कि वह बस तुम्हारे बुरे कर्मों को ले रहा है और उसे छोड़ दो। यदि तुम गुरु के निकटतम में से एक हो तो संसार के सारे आरोपों को हंसते हुए ले लोगे। द्वंद्व संसार का स्वभाव है और शांति आत्मा का स्वभाव है। द्वंद्व के बीच शान्ति की खोज करो। द्वंद्व समाप्त करने की चेष्टा द्वंद्व को और ज्यादा बढ़ाती है। आत्मा की शरण में आकर विरोध के साथ रहो। जब शान्ति से मन ऊबने लगे तो सांसारिक क्रिया-कलापों का मजा लो। और जब इनसे थक जाओ तो आत्मा की शान्ति में आ जाओ। यदि तुम गुरु के करीब हो, तो दोनों क्रिया कलाप साथ-साथ करोगे। ईश्वर व्यापक हैं। और अन्नत काल से ईश्वर सभी विरोधों को संभालते आए हैं। यदि ईश्वर सारे विरोधों को ले सकते हैं, तो निश्चित ही तुम भी ऐसा कर सकते हो। जैसे ही तुम विरोध के साथ रहना स्वीकार कर लेते हो, विरोध स्वतः समाप्त हो जाता है। शान्ति चाहने वाले लोग लड़ना नहीं चाहते और इसके विपरीत लड़ाई करने वाले शान्ति पसन्द नहीं करते। शान्ति चाहने वाले लड़ाई से बचना चाहते हैं। आवश्यक यह है कि मन को शांत करें और फिर लड़ें। गीता की यही मूल शिक्षा है। कृष्ण अजरुन को उपदेश देते हैं कि अजरुन युद्ध करो मगर हृदय को शान्त रखकर। संसार में जैसे ही तुम एक विरोध को समाप्त करते हो तो दूसरा खड़ा हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे ही रूस की समस्या समाप्त हुई, बोस्निया की समस्या खड़ी हो गई। एक समस्या हल होती है, तो दूसरी शुरू हो जाती है। तुम्हें जुकाम हुआ। वह जरा ठीक हुआ नहीं कि फिर कमर में दर्द शुरू हो गया। फिर यह ठीक हो गया। और तो और, शरीर ठीक ठाक है तो मन अशान्त हो जाता है। बिना किसी इरादे के गलतफहमियां पैदा होती हैं, उलझन पैदा होती है। यह तुम्हारे ऊपर नहीं कि तुम उनका समाधान करो। तुम तो बस उन पर ध्यान न दो, बस जीवन्त रहो।

युवाओं को साइबर स्लेवरी में धकेल रहे हैं कबूतर बाज

मनोज कुमार अग्रवाल

विदेश मे जाकर नौकरी रोजगार कर बेशुमार दौलत कमाने का सपना किसे अच्छा नही लगता है? अच्छे पैसे कमाए और बेहतर जीवन जीने की अभिलाषा कबूतर बाज एजेंटों के जाल में फंस कर जीवन बर्बाद कर रही है । इन एजेंटों के दिखाए सब्जबाग में अपने सुखद भविष्य के सपने संजोकर अनेक युवा किसी भी तरीके से विदेश पहुंचने की कोशिश करते रहते हैं परंतु उनमें से अनेक युवक जालसाज ट्रैवल एजेंटों के हाथों ठगी का शिकार हो रहे हैं जिनकी मात्र इसी महीने के 4 दिनों में सामने आई घटनाएं निम्न में दर्ज हैं :

14 जनवरी मेरठ शहर के आजाद चौक व कांधला क्षेत्र के छह युवकों को सिंगापुर और मलेशिया में मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी का झांसा देकर 26 लाख रुपये की ठगी कर ली गई। यही नहीं, दो युवकों को फर्जी कागजात के आधार पर मलेशिया भेज दिया गया, जहां उन्हें 15 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया। तीन जनवरी को दोनों युवक किसी तरह भारत लौटे। पीड़ितों ने एसपी को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। एसपी ने मामले की जांच शुरू करा दी है।

14 जनवरी नोएडा पुलिस ने विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं को ठगने और साइबर अपराधियों के हवाले करने वाले फर्जी एजेंट शुभम को गिरफ्तार किया है. आरोपी सोशल मीडिया के जरिए पीड़ितों से पैसे वसूल करता था और उन्हें थाईलैंड, म्यांमार में साइबर स्लेवरी में फंसा देता था. पुलिस आरोपी के नेटवर्क और अन्य सहयोगियों की गहन जांच कर रही है.

14 जनवरी को ही दुबई में फंसे उत्तराखंड रुद्रपुर के चार युवकों ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर पुलिस से गुहार लगाई है. जिसके बाद एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने मामले की जांच सौंपते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

4 जनवरी, 2026 को सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) में एक एजेंट द्वारा विदेश जाने के इच्छुक युवक को अमरीका पहुंचाने का वायदा करके उससे 60 लाख रुपयों की ठगी करने का मामला सामने आया। शिकायतकर्त्ता के अनुसार पहले उसे दुबई ले जाया गया और वहां से अजरबैजान भेज दिया। 6 जनवरी को जम्मू में अनिल किशोर नामक एक पीड़ित ने एक ट्रैवल एजैंट मां-बेटे के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाई कि आरोपियों ने उसे कम्बोडिया का वर्क वीजा दिलाने के नाम पर उससे 1.20 लाख रुपए लिए थे परंतु न तो वीजा दिलवाया और न ही रकम वापस की गई।

6 जनवरी को ही नवादा (बिहार) में एजाजुल हसन नामक युवक ने विदेश भेजने का झांसा देकर उससे 1 लाख 30 हजार रुपए ठगने के आरोप में ठग ट्रैवल एजैंट के विरुद्ध पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई।

6 जनवरी को ही फतेहपुर (उत्तर प्रदेश) में एक युवक को विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर उससे 1.40 लाख रुपए ठग लेने के आरोप में एक ठग ट्रैवल एजैंट को गिरफ्तार किया गया।

7 जनवरी को हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) के भोरंज में विदेश में नौकरी दिलवाने के नाम पर एक युवक से ठगी का मामला सामने आया। आरोप है कि बोगस ठग ट्रैवल एजैंट ने उक्त युवक को थाईलैंड में अच्छी नौकरी दिलवाने का लालच देकर वहां भेजने की बजाय म्यांमार भेज दिया।

7 जनवरी को ही एक व्यक्ति ने चंडीगढ़ के सैक्टर 17 थाने में कनाडा का वर्क परमिट दिलाने का झांसा देकर उससे 18 लाख रुपए की ठगी करने के आरोप में एक ट्रैवल एजैंट के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाई।

7 जनवरी को ही पंचकूला (हरियाणा) में एंटी इमीग्रेशन फ्राड यूनिट ने शिकायतकर्ता को स्टडी वीजा दिलाने का झांसा देकर उससे 13 लाख रुपए ठग लेने के आरोप में एक बोगस ट्रैवल एजैंट को गिरफ्तार किया।

7 जनवरी को ही कौशाम्बी (उत्तर प्रदेश) में एक व्यक्ति को विदेश भेजने के बहाने उससे 60,000 रुपए ठग लेने के आरोप में पुलिस ने एक ठग ट्रैवल एजेंट के विरुद्ध केस दर्ज किया। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी ने उसे विदेश नहीं भेजा और अपने पैसे वापस मांगने पर गंभीर परिणामों की धमकियां देनी शुरू कर दीं।

7 जनवरी को ही प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) में एक युवक को सऊदी अरब में नौकरी दिलवाने के बहाने एक ट्रैवल एजैंट द्वारा उससे 1.25 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। आरोपी ने न तो उसे वीजा दिलवाया और न ही नौकरी दिलवाई तथा बाद में उसका फोन उठाना भी बंद कर दिया।

7 जनवरी को ही गोपालगंज (बिहार) में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने छापेमारी करके विदेश में नौकरी दिलवाने का झांसा देकर लोगों को ठगने वाले एक फर्जी ट्रैवल एजेंट मृत्युंजय सिंह को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 349 भारतीय पासपोर्ट बरामद किए।

ये तो सिर्फ चंद घटनाओं की बानगी है आजकल रोजाना सैकड़ों युवाओं से विदेश में पढ़ाई रोजगार के नाम पर ठगी का बड़ा धंधा चल रहा है

ऐसी घटनाओं के दृष्टिगत जरूरी है कि विदेश जाने के इच्छुक लोग पहले संबंधित कम्पनी, एजेंट और दस्तावेजों की पूरी जांच-पड़ताल अवश्य करें और केवल अधिकृत एवं पंजीकृत एजेंटों के माध्यमों से ही विदेश जाएं।

इमीग्रेशन नियमों में हो रही सख्ती और बिगड़ रही अर्थव्यवस्था के कारण वैसे भी विदेश में बसना मुश्किल हो गया है। कनाडा और अमरीका के अलावा यूरोप में भी इमीग्रेशन कानून सख्त हो रहे हैं।

अतः जितनी रकम माता-पिता अपने बच्चों को विदेश भेजने पर खर्च करते हैं, उतनी ही रकम भारत में खर्च करके वे अपने बच्चों को अच्छा कारोबार शुरू करवा दें ताकि वे अपने साथ-साथ दूसरों के लिए भी रोजगार व आय के साधन पैदा करके देश में बेरोजगारी दूर कर सकें।जरा सा असावधानी से न सिर्फ माँ बाप के खून पसीने की कमाई जालसाज हड़प लेंगे वरन विदेश पहुच कर साइबर स्लेवरी के शिकार भी बन सकते हैं वहा हजारों पढे लिखे नौजवान संडास की सफाई और जबरन युद्ध के मैदान मे भी उतार दिए गए हैं जिस कारण उनका सुरक्षित वापस लौटना भी भगवान भरोसे है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

माँ-बाप की नीयत, परवरिश और टूटते घर

डॉ. प्रियंका सौरभ

भारतीय समाज में माता-पिता को सर्वोच्च नैतिक स्थान प्राप्त है। उन्हें त्याग, तपस्या और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक माना जाता है। बचपन से ही यह सिखाया जाता है कि माँ-बाप कभी गलत नहीं हो सकते। उनकी हर बात आदेश है, हर निर्णय अंतिम सत्य। लेकिन बदलते सामाजिक परिदृश्य में यह धारणा अब कई सवालों के घेरे में है। आज जब पारिवारिक विघटन, तलाक, अलगाव और घरेलू तनाव की घटनाएँ बढ़ रही हैं, तब यह जरूरी हो गया है कि हम ईमानदारी से यह स्वीकार करें-माँ-बाप भी हमेशा सही नहीं होते। आज अनेक परिवारों में टूटन का कारण केवल पति-पत्नी के बीच का मतभेद नहीं है, बल्कि उसके पीछे माता-पिता की भूमिका भी उतनी ही निर्णायक होती जा रही है। यह कहना कठोर लग सकता है, लेकिन सच्चाई यही है कि कई घरों में माता-पिता द्वारा किया गया पक्षपात, हस्तक्षेप और नियंत्रण रिश्तों को भीतर से खोखला कर रहा है।

सबसे पहले बात करते हैं भेदभाव की संस्कृति की। भारतीय परिवारों में यह कोई नई बात नहीं है कि बच्चों के बीच तुलना और पक्षपात होता रहा है। बड़ा बेटा 'वारिस' माना जाता है, छोटा 'समझौता' करता है, बेटी 'पराया धन' होती है और बहू 'बाहरी'। यही सोच जब व्यवहार में उतरती है, तो घर में स्थायी तनाव पैदा हो जाता है। माता-पिता अनजाने में या जानबूझकर एक बेटे के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, दूसरे को उपेक्षित कर देते हैं। बहू को हर विवाद की जड़ मान लिया जाता है, जबकि बेटी के दोष पर पर्दा डाल दिया जाता है। यह असमानता रिश्तों को धीरे-धीरे तोड़ देती है। विवाह के बाद बहू का स्थान आज भी कई घरों में संदिग्ध बना रहता है। उससे उम्मीद की जाती है कि वह बिना सवाल किए हर परंपरा को स्वीकार करे, हर निर्णय माने और अपनी पहचान को त्याग दे। यदि वह अपने अधिकार, सम्मान या स्वतंत्रता की बात करती है, तो उसे 'घर तोड़ने वाली' करार दे दिया जाता है। जबकि सच्चाई यह है कि कई बार घर पहले ही भीतर से टूट चुका होता है-सिर्फ दिखावा बचा होता है।

माता-पिता का अत्यधिक हस्तक्षेप भी आज पारिवारिक विघटन का बड़ा कारण बन रहा है। बेटे-बहू के निजी मामलों में दखल देना, छोटी-छोटी बातों को तूल देना, बहू की शिकायतों को नजरअंदाज करना और बेटे को भावनात्मक दबाव में रखना-ये सब स्थितियाँ विवाह को बोझ बना देती हैं। बेटा अक्सर दो पाटों के बीच फँस जाता है-एक ओर पत्नी, दूसरी ओर माता-पिता। और समाज उसे यही सिखाता है कि माता-पिता का साथ देना ही धर्म है, चाहे इसके लिए दांपत्य जीवन की बलि क्यों न देनी पड़े। यह भी देखने में आता है कि बेटी की शादी के बाद भी माता-पिता उसे अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। बेटी को बार-बार मायके बुलाकर, उसके वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप कर, दामाद के खिलाफ राय बनाकर, वे अनजाने में बेटी का घर कमजोर कर देते हैं। नतीजा यह होता है कि बेटी और दामाद के बीच अविश्वास पनपता है, और अंततः रिश्ता टूटने की कगार पर पहुँच जाता है।

एक और गंभीर पहलू है भावनात्मक ब्लैकमेल। 'हमने तुम्हारे लिए क्या-क्या नहीं किया', 'हमारे कारण तुम इस मुकाम पर हो', 'अगर हमारी बात नहीं मानी तो लोग क्या कहेंगे'-ऐसे वाक्य बच्चों को मानसिक रूप से जकड़ लेते हैं। वे अपनी खुशी, अपने रिश्ते और अपने सपनों की कीमत पर भी माता-पिता को खुश रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह दबा हुआ असंतोष किसी न किसी दिन विस्फोट बनकर सामने आता है। समस्या तब और गंभीर हो जाती है जब समाज भी इस मानसिकता को बढ़ावा देता है। हर विवाद में सबसे पहले सवाल बहू से किया जाता है-'क्या किया तुमने?' बेटे को 'मजबूर' मान लिया जाता है और माता-पिता को 'पीड़ित'। इस सामूहिक पूर्वाग्रह के कारण सच्चाई कभी सामने नहीं आ पाती। जिन घरों में माता-पिता की भूमिका नकारात्मक होती है, वहाँ भी उन्हें प्रश्नों से ऊपर रखा जाता है।

यह कहना भी जरूरी है कि हर माता-पिता दोषी नहीं होते। असंख्य माता-पिता ऐसे हैं जो संतुलित, संवेदनशील और न्यायप्रिय होते हैं। वे बच्चों को स्वतंत्र निर्णय लेने देते हैं, बहू-दामाद को सम्मान देते हैं और संवाद को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन समस्या उन माता-पिता की है जो अपने अनुभव को अंतिम सत्य मान लेते हैं और बदलते समय को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। आज का युवा अलग सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में जी रहा है। उसके सामने करियर का दबाव है, आर्थिक असुरक्षा है, बदलते रिश्तों की चुनौतियाँ हैं। ऐसे में उसे सहयोग चाहिए, नियंत्रण नहीं। उसे समझ चाहिए, आदेश नहीं। माता-पिता यदि यह समझने में असफल रहते हैं, तो टकराव स्वाभाविक है। परिवार संस्था को बचाने के लिए सबसे जरूरी है आत्ममंथन। माता-पिता को यह स्वीकार करना होगा कि उम्र के साथ-साथ अधिकार नहीं, जिम्मेदारी बढ़ती है। मार्गदर्शन और हस्तक्षेप में अंतर होता है। बच्चों की शादी का अर्थ यह नहीं कि वे हमेशा माता-पिता की इच्छाओं के अनुसार ही जिएँ। उन्हें अपनी गलतियों से सीखने का अवसर देना भी परवरिश का हिस्सा है।

साथ ही, बच्चों को भी यह समझना होगा कि संवाद ही समाधान है। टकराव, कटुता और अलगाव स्थायी समाधान नहीं हैं। लेकिन संवाद तभी संभव है जब माता-पिता भी सुनने को तैयार हों-बिना जजमेंट, बिना अहंकार। आज जरूरत है कि हम 'माँ-बाप हमेशा सही होते हैं' जैसी भावनात्मक लेकिन अव्यावहारिक धारणाओं से बाहर आएँ। सम्मान और प्रश्न एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। माता-पिता का सम्मान करते हुए भी उनकी भूमिका की समीक्षा की जा सकती है। यही स्वस्थ समाज की पहचान है। घर टूटने का कारण कभी एक व्यक्ति नहीं होता। यह कई गलत फैसलों, दबे हुए दर्द और अनसुनी आवाजों का परिणाम होता है। यदि सच में हम परिवारों को टूटने से बचाना चाहते हैं, तो हमें साहस के साथ यह स्वीकार करना होगा कि कभी-कभी आईना माता-पिता को भी दिखाना पड़ता है। यही कड़वा सच आगे चलकर मीठे रिश्तों की नींव बन सकता है।

Printed and Published by Fahim Akhtar on behalf of MAA MEDIA VENTURE and Printed at SHIVA SAI PUBLICATION PVT.LTD, Ratu, Kathitand, Near Tender Bagicha, H.P. Petrol Pump P.O.+P.S.- Ratu, Dist.-Ranchi, 835222, Jharkhand And Published at Roshpa Tower, 5th Floor, Main Road, Ranchi, Jharkhand-834001. R.N.I Number - JHABIL/2022/85899, Editor- Fahim Akhtar. Mob - 9431311669, E-mail : thephotonnewsjharkhand@gmail.com

Listening to the land and its people, the Gadgil way

At the ground level, people are really interested and they want to get involved. Our report, if nothing else, seems to have served the purpose of triggering such kind of an interest," said Dr Madhav Gadgil while delivering a lecture on 'Democracy and ecology in contemporary India'in Delhi in July, 2013. He was referring to the 2010-11 report of the Western Ghats Ecology Expert Panel (WGEEP), which he chaired and which was one of the major contributions of Gadgil to India's environmental governance.We accompanied him during some of his travels. They mainly consisted of back-to-back and often heated meetings in some of the remotest corners of the Western Ghats. The meetings were not only about plants, trees and rivers, but also about what the villagers feel about development and how it should happen. No one had asked such questions before. It was the democratisation of environmental governance at its messiest and the most beautiful. Something that was never attempted before. Nor has it been attempted since.

No wonder, the report, produced after such a radically different approach — trusting the people of the land — was not acceptable to the vested interests. In Maharashtra, Karnataka and Kerala, politicians twisted the report, made false claims, did what they knew best: spread fear amongst people.he report was rejected and the government set up a High-Level Working Group, headed by Dr Kasturirangan, essentially to dilute the recommendations of the WGEEP Report. But the Kasturirangan Committee ended up with a report that was at odds with facts and science. Under the leadership of Dr Gadgil, the Western Ghats saw a brief period of tender hope.The Gadgil report is a veritable textbook about managing rivers in ecologically important places. No wonder, because one of the initiators of the Movement against Athirapally Dam in Kerala, the late Dr Latha Anantha, worked with Gadgil on this section. Gadgil was an important figure in Kerala's landmark Silent Valley struggle against a hydropower project, which led to a cascade of environmental laws in the country. He also supported the movement against the Athirapally Dam, led by local communities. He was a vocal supporter of the Narmada Bachao Andolan's epic struggle against the Sardar Sarovar project on the Narmada river.He hailed the Plachimada struggle against Coca-Cola as a ray of hope since this was a struggle led by a panchayat, which brought a multi-national company to its knees. The stance he took against chemical pollution in the Lote Parshuram region of the Western Ghats was so decisive and people-centred that his work is used by the people to this day.He laid stress on the need to engage local people in the decision-making process and increase dissemination of information. He took the example of the 'Australian River Watch' programme, where citizens are trained to monitor the health of a river just by looking at the bio-logical indicators. He said that India should take lessons from this and initiate such programmes.

He added that for India to progress, we should take the bottom-up approach and strengthen democracy, rule of law, scientific temperament and traditional ecological knowledge.Indicating how forward-thinking he was, was a key recommendation of the WGEEP report, asking for the initiation of policy and legal steps towards decommissioning of dams in India, when India had no policy or laws in this regard.Gadgil played an important role in drafting the National Biodiversity Act of 2002. He also helped set up the Centre for Ecological Sciences at the Indian Institute of Science, Bangalore.As former Environment Minister Jairam Ramesh said, "Nation builders come in many forms. Gadgil was definitely one of them.

Speedy trial is Umar-Sharjeel's right

If a trial is delayed without any valid justification, the accused should be granted bail

BOB Dylan might well ask: How many years must a man spend in jail, before he can get bail? The answer, my friend, has been blown away in the wind.Recently, the Supreme Court (SC) held in the lead case of Gulfisha Fatima that Umar Khalid and Sharjeel Imam were not entitled to bail effectively for another year. They have already been in jail for more than five years, without charges being framed against them by the court concerned. This is tragic as far as the right to personal liberty and the right to a speedy trial are concerned.

Umar and Sharjeel have been chargesheeted for allegedly masterminding the Delhi riots in February 2020 in what is described as a larger conspiracy. In furtherance of the so-called larger conspiracy, they are accused of having committed a "terrorist act" within the meaning of this expression under Section 15 of the Unlawful Activities (Prevention) Act or UAPA. Given space constraints, it is not possible to delve into or unravel the conspiracy, but it is possible to try and understand whether their continued detention for more than five years is constitutionally justified.Riots took place in Delhi in the last week of February 2020; an FIR was lodged on March 6. The Supreme Court records that "the riots were allegedly the outcome of a pre-planned conspiracy orchestrated by Jawaharlal Nehru University student Umar Khalid along with his associates, who were stated to be affiliated with different organisations.

" Neither Sharjeel nor Umar were named as accused in that FIR. Perhaps their alleged role in a larger conspiracy came to notice much later. They were accused for the first time in a supplementary chargesheet filed on November 22, 2020.Interestingly, Sharjeel had been arrested in the last week of January 2020, a month before the riots. It appears that he got bail subsequently and was again arrested on August 25 that year. Umar was arrested on October 1, 2020, about seven months after the riots. They have been in jail ever since, without trial.An accused person is entitled, as per provisions of the Criminal Procedure Code (CrPC, which was in force at that time), access to all the material and documents relied on by the prosecution in the chargesheet. In all fairness, the chargesheets, with all documents, should have been handed over to all the accused persons simultaneously with their filing. For reasons best known to the prosecution, compliance with the statutory mandate was recorded by the trial judge only on August 5, 2023 — about three years later. Meanwhile, the prosecution kept filing supplementary chargesheets one after another, with the fourth one on June 7, 2023.All this while, the accused were in jail and without necessary documentary evidence against them. What is the cause of the delay in framing charges? In this regard, the Supreme Court referred to the case of Tasleem Ahmed (2025) decided by the Delhi High Court. A perusal of the judgment shows that Sharjeel sought an adjournment on two occasions to argue on framing charges. Umar wanted arguments on the charges to begin on September 18, 2023, but his arguments were not heard.In October 2024, he requested an adjournment to argue on framing charges. The Supreme Court noted that it did not want to apportion blame for the delay in framing charges either on the prosecution or the accused persons. I am of the view that this was an incorrect approach to the issue of bail to the accused. The cause of delay ought to have been apportioned, and the initial delay by the prosecution in complying with the mandate of Section 207 of the CrPC ought not to have been ignored or overlooked in a matter of personal liberty.

That personal liberty is a valuable right has been recognised by the Constitution in Article 21 and by the SC in several judgments. The Court has gone a step further and held that the right to a speedy trial is also a valuable right tied up with personal liberty and Article 21.What does this mean? It simply means that if a trial is delayed without any valid justification, the right to a speedy trial is negated and the accused must be granted bail. The reason is fairly obvious — if the alleged crime is of a very serious nature, such as adversely impacting on the unity or integrity of the country, it must be tried with the greatest urgency and not in a lethargic manner.

Recall the Parliament attack that took place in December 2001: the case was decided by the trial court in about six months and eventually by the Supreme Court in 2005 within five years of the incident. Similarly, the case of Ajmal Kasab was decided by the apex court within four years of the 26/11 terror attack. The prosecution was serious about those cases.Is the prosecution serious about this case? Umar and Sharjeel have been accused of grave offences, a larger conspiracy including a terrorist act resulting in the death of a large number of people, trying to engineer regime change and internationalise the protest against the Citizenship (Amendment) Act during the visit of the US President.Surely, this was a case that should have been decided within six months and not one where documents were supplied to the accused after three years. Should the accused be deprived of their personal liberty due to a somnambulant prosecution and a meandering case? More than 800 witnesses are yet to be examined. Is there any hope of the trial concluding in the near future? Is the answer blowing in the wind?s

End of 10-minute delivery offer is a breakthrough

The Tribune Editorial: Dropping the 10-minute delivery offer is a necessary corrective, but it is not a cure.

THE Central government's intervention to end the 10-minute delivery offer in the booming quick-commerce sector has been rightly welcomed by gig workers and their well-wishers. The Labour Ministry has prevailed upon leading platforms to shun the ultra-fast route, which was putting immense pressure on delivery agents and making them take life-threatening risks on the roads. In recent years, the 10-minute promise was defended as a triumph of logistics. Major aggregators argued that dense networks of dark stores and short distances made rapid delivery possible without forcing bikers to speed. However, when incentives, ratings and penalties decide income, workers inevitably become desperate.The nationwide strike by gig workers on New Year's Eve may not have derailed operations, but it did serve to highlight their problems. Protesters red-flagged an unfair system that punished delay without accounting for traffic, weather or fatigue. Dropping the 10-minute attraction is a necessary corrective, but it is not a cure. As even some platforms admit, most deliveries already take longer than 10 minutes. The slogan was as much about shaping consumer expectations as it was about operational reality. Removing it does little to address the vulnerabilities of gig work: income insecurity, arbitrary deactivations, lack of collective bargaining and inadequate social protection.

The Code on Social Security, which finally recognises gig and platform workers, offers a framework for welfare funds, insurance and old-age support. Yet implementation will matter more than intent. Contributions by aggregators, transparent pay calculations and enforceable safety standards must be the order of the day. India's quick-commerce revolution has undeniably transformed urban life. Customers' convenience, however, should not come at the cost of workers' dignity and safety.

Turmoil puts Iran at a crossroads

Calls for regime change may be premature, but change within the regime is on the cards

UNPRECEDENTED nationwide protests have shaken the Islamic Republic of Iran during the past fortnight. There seems to be no sign that they will abate anytime soon. Iran is no stranger to social unrest, but the intensity of the latest round of public demonstrations appears to represent an existential crisis for the republic.

It is widely being seen as posing the gravest threat the regime has faced in 47 years since the February 1979 Islamic revolution. The country is under a lockdown with the suspension of Internet connectivity and international telephony. The regime is also said to have deployed military-grade technology of Russian or Chinese origin to block Starlink, the global satellite communications network.

In an atmosphere of rumours and social media disinformation, an accurate assessment of the prevailing situation in Iran has been hard to come by. However, a range of sources report that recent days have seen a brutal crackdown by security forces; this has so far resulted in the death of several hundred demonstrators — the figures vary between 500 and 2,000 — and several thousands being detained. The coming days, perhaps even weeks, could therefore determine what the future holds for a widely unpopular regime but one which has long endured and is set to enter its 48th year next month.Beginning December 28, widespread demonstrations and rioting have taken place across Iran. These organic protests started in Tehran's Grand Bazaar. Traders shut shops and staged a sit-in, protesting the collapse of the Iranian currency, the Rial, against its principle benchmark, the US dollar. The trigger was a decision by the government of President Masoud Pezeshkian to undertake financial and economic reforms, compelled by the all-pervasive US sanctions.

One proposal was to withdraw a preferential exchange rate mechanism whereby trading guilds, the bazaaris, receive scarce forex at highly subsidised rates, disproportionately below the market rate. The bazaaris are fiercely protective of this access to preferential state funds via a controlled forex system. Pezeshkian's decision has divided the ruling clerical regime which is keenly mindful of the economic influence of the bazaaris.What started as a pressure tactic by the bazaaris spread like wildfire, drawing in students and a cross-section of society, where frustration and despair are ever present, particularly among the youth. Contributory factors are the severely depressed economic and employment conditions, an inflation rate estimated to be over 45 per cent and popular frustration with the regime's economic mismanagement, widespread corruption and rent-seeking.

The pattern of past protests in Iran, most recently the 2022 anti-hijab demonstrations, is that popular discontent is initially fuelled by either a social (anti-hijab) or economic grievance and thereafter it rapidly transforms into a political uprising. The current demonstrations are following a similar pattern. However, this time around, the protests, as also the diversity of protesters — drawn from all segments of society — have shifted into a higher gear with an intensity never seen before. An additional element has been the open expression of disenchantment over the economic costs of the regime's interventions in Palestine, Syria and Lebanon.

The common anti-regime slogans of "death to the dictator" - a reference to Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei — are now being accompanied by shouts of "Neither Gaza nor Lebanon, my life for Iran." A new element is the slogan "Javid Shah" (long live the Shah), a reference to Crown Prince Reza Pahlavi, who is based in the United States. Pahlavi is seeking to take ownership for the protests and position himself as a viable alternative. Given Iran's fractious polity and Pahlavi's own disconnect from the current generation of Iranians, this seems to be a hard ask. The monarchy remains a divisive issue among Iranians.

The intensity of the ongoing social turmoil and the regime's typically harsh response has raised valid anxieties about the continued internal stability of one of West Asia's most important geo-strategic players. The unfolding situation will be of deep concern for Iran's neighbours. Iran is the second largest country in West Asia, second only to its geo-strategic and religious rival, Saudi Arabia. Both countries contest for leadership of the Islamic Ummah through competing Sunni and Shia sectarian ideologies. Both sects coexist peacefully in India, unlike almost every OIC (Organisation of Islamic Cooperation) country.The traditionally close historical relations between India and Iran have greatly deepened in recent years, particularly through partnerships such as India's management and operation of the strategic Chabahar Port. Membership of BRICS and the SCO enables both nations to broaden opportunities for cooperation. It is generally under-appreciated that Iran has weathered decades of financial and economic sanctions and adroitly managed to avoid isolation.Iran is fiercely independent and positions itself as a vital geo-strategic actor, including in the global energy markets. It holds the world's fourth largest reserves of crude oil and second largest reserves of natural gas. Exports of Iranian light, the much-valued low sulphuric content crude, amount to around two million barrels per day. Thus, the protests in Iran, coupled with the extraordinary incidents in Venezuela, have triggered an uptick in global crude oil prices, a rise that Delhi's policymakers will be closely tracking ahead of the Union Budget.

The situation in Iran remains highly fluid. As per reports, riots and demonstrations continue to take place in major cities, including Tehran, Isfahan and Shiraz. The state of affairs seems to be especially critical in Iran's provinces bordering Iraq which have Kurds in the majority. For now, the Islamic regime has shown no signs of disunity and the Supreme Leader has shown no inclination to compromise and reach out to his people. Pezeshkian was initially conciliatory but then retreated from public life.India has been typically cautious, issuing only a brief travel advisory while eschewing any public commentary. After all, there are roughly 3,000 Indian students in Iran, including those in the religious seminaries in Qom and Mashhad, and this caution is warranted.On the other hand, official comments from most Western capitals have been critical of the Iranian authorities' harsh response. US President Donald Trump wavered between threatening to launch military strikes on Iran while simultaneously claiming that he had received messages from Iran for renewed talks.

Infosys shares rally after Q3 FY26 results: Should you buy now

Infosys stock: The stock opened at Rs 1,670.30, touched an intraday high of Rs 1,683.45 and a low of Rs 1,654.55. The 52-week high of the stock stands at Rs 1,967.75, while the 52-week low is Rs 1,307.10.

New Delhi.(Agency)

Shares of Infosys Ltd rose sharply on Dalal Street on Friday after the company announced its Q3 FY26 results. The rally in Infosys also helped broader markets move higher, with benchmark indices gaining close to 1% and snapping their recent losing streak.

Infosys share price jumped more than 5% in early trade. As per exchange data, the stock was trading around Rs 1,681.55, up Rs 82.50 or 5.16% from its previous close of Rs 1,599.05.The stock opened at Rs 1,670.30, touched an intraday high of Rs 1,683.45 and a low of Rs 1,654.55. The 52-week high of the stock stands at Rs 1,967.75, while the 52-week low is Rs 1,307.10.

WHAT DROVE THE RALLY IN INFOSYS SHARES

The main reason behind the sharp rise in Infosys shares was its Q3 FY26 performance and the guidance upgrade announced by the company.Infosys reported constant currency revenue growth of 0.6% quarter-on-quarter, which was better than market expectations. The company also raised its FY26 constant currency revenue growth guidance to 3%–3.5%, up from the earlier range of 2%–3%. This came as a surprise to the Street at a time when global tech spending remains uneven.The company said it is seeing steady discretionary tech spending and better momentum in its key financial services business. This improved outlook helped boost investor confidence in the stock.

STRONG DEAL WINS SUPPORT GROWTH VISIBILITY

Another key positive from the quarter was

strong deal activity. Infosys reported total contract value of $4.8 billion in Q3 FY26 from 26 deals. This was a sharp jump compared with $3.1 billion in the previous quarter.Around 57% of these deals were classified as net new, which means they were fresh additions rather than renewals.Strong deal wins are often seen as an early sign of demand recovery, and this played a big role in driving buying interest in the stock.BROKERAGES REACT POSITIVELY

Following the Q3 results, several domestic brokerages maintained a positive view on Infosys, citing better revenue growth and improved visibility.Choice Institutional Equities said Infosys delivered a resilient quarter despite seasonal challenges. It highlighted the strong large-deal momentum and said the company is sharpening its focus on six AI value areas.

These include AI engineering, data for AI, AI agents for operations, AI-led software development and legacy modernisation, AI with physical devices, and AI services.

Choice said this strategy positions Infosys well to gain market share in AI-led services and solutions. The brokerage added that Infosys expects stronger growth in FY27, led by the Energy and Utilities vertical and a pickup in discretionary spending in BFSI.Based on this, Choice said it has revised its estimates and expects revenue, EBIT and PAT to grow at a CAGR of 10.2%, 11.8% and 10.8%, respectively, over FY25 to FY28E. It maintained its Buy rating with a revised target price of Rs 1,865.

State Bank of India IMPS Charges To Go Up From February 15 -- Check Latest Rates

New Delhi.(Agency)

India's largest public sector lender State Bank of India (SBI) has announced revision on its Immediate Payment Service (IMPS) charges for retail customers. SBI's latest IPMS charges are applicable from February 15.

The National Payments Corporation of India (NPCI) offers IMPS, a real-time payment system that is accessible around the clock and has a Rs 5 lakh transaction limit (apart from SMS and IVR channels). SBI IMPS transaction charges waived for following Salary Package accounts

-- DSP, PMSP, ICGSP, CGSP, PSP and RSP including Shaurya Family Pension Accounts.

-- CSP/ SGSP/SUSP and Family Savings Account-SBI RISHTEYIMPS, known as Immediate Payment Service, is a popular method of transferring money. It allows for 24x7 instant domestic funds transfer through various channels such as mobile banking apps, bank branches, ATMs, SMS, and IVRS.

India's Fiscal Deficit To Be Set At 4.2% Of GDP For FY27: Morgan Stanley

New Delhi.(Agency)

The central government's fiscal deficit is expected to be set at 4.2 per cent of GDP for FY27 in the upcoming Union Budget (against the target of 4.4 per cent in FY26) — corresponding to moderation in debt to 55.1 per cent of GDP, a Morgan Stanley report said on Friday. The pace of consolidation will be consistent with central government debt reduction to 55.1 per cent of GDP from 56.1 per cent in FY26.A pickup in nominal growth will help to lift tax buoyancy and improve tax collections in FY2027, helping the government to prioritise capex and social infrastructure-related spending alongside gradual consolidation," the report mentioned.Focus on capex to help create jobs, targeted social sector spending, and a step up in structural reform momentum are likely to be key themes, it added.The impact of the budget on the market has been on a secular decline, albeit actual performance is a function of pre-budget expectations (as measured by market performance ahead of the budget)."As of now, the market appears to be approaching the budget with skepticism and could be dealing with both volatility and upside risk post-budget, if history is a guide," said the report.

For the market, the key things to watch are the extent of fiscal consolidation, capex, and sector-level actions.

"Of particular interest will be capital market reforms to encourage a revival in foreign portfolio flows. We are overweight on Financials, Consumer Discretionary, and Industrials," the report mentioned.

Consistent with the path of continued fiscal consolidation, "we expect net issuance of G-Secs to remain broadly stable at Rs 11.6 trillion (FY26: Rs 11.5 trillion)."Gross issuance may pick up to Rs 15.8 trillion (FY26: INR 14.8 trillion) given the larger amount of redemptions. Our issuance projections are on the lower end of market expectations and could help G-secs rally temporarily if realised, providing an opportunity to pay rates," said the report.

Union Budget 2026: Strengthening India's fertiliser backbone for sustainable agriculture

New Delhi.(Agency)

As the world's second-largest fertiliser consumer and with agriculture employing about 45% of the workforce, fertiliser self-reliance remains a strategic national priority. Government policy has therefore focused on ensuring affordable and timely availability through subsidies, alongside expanding domestic manufacturing capacity. As India approaches the Union Budget 2026–27, the fertiliser sector merits focused policy attention to strengthen soil health, ensure long-term agricultural sustainability, and advance Atma Nirbhar Bharat objectives.

Ensuring subsidy adequacy

In developed economies such as the US, EU and Japan, agriculture policy has shifted away from production-linked subsidies toward income support, risk management, crop insurance, environmental services and climate resilience.

In contrast, farm subsidies in India are primarily designed to ensure food security, support farmer incomes, and maintain the affordability of key agricultural inputs. Fertiliser subsidy remains one of the most critical elements, shielding farmers from global price volatility and ensuring timely access to nutrients at affordable prices.

Under India's fertiliser subsidy framework, Urea is governed by a cost-plus regime, phosphatic and potassic (P&K) fertilisers fall under the Nutrient Based Subsidy (NBS) mechanism. But of the nearly ?2 lakh crore spent annually on fertiliser subsidies, close to 70% is absorbed by urea, with the remainder supporting phosphatic fertilisers.

There is a reasonable case for revisiting the subsidy framework by gradually bringing urea under the NBS regime, while protecting marginal farmers through targeted direct subsidy support.The recent surge in prices of key inputs such as sulphur and ammonia has strained Phosphatic industry viability, as NBS rates have not kept pace with global trends especially for N and K nutrients. The forthcoming Budget should therefore provide adequate, price-aligned fertiliser subsidy allocations under NBS to ensure uninterrupted nutrient supplies ahead of the cropping season.To promote balanced nutrition, there is a need to encourage innovations such as nano and slow-release fertilisers, along with organic and bio-fertilisers. Inclusion of such resource efficient solutions under schemes like PM-PRANAM, which incentivise States to adopt integrated nutrient management by reinvesting subsidy savings in alternative fertilisers, farmer training and awareness, can play a pivotal role

Can Budget 2026 address tax, talent and cost pressures in tourism and hospitality

New Delhi.(Agency)

As the Union Budget 2026 approaches, voices from India's tourism and hospitality sectors are calling for deeper reforms to sustain growth. While travel demand has improved and new destinations are emerging, industry leaders say policy support is now needed to tackle skill gaps, high costs and infrastructure challenges.

From workforce training to tax relief and easier credit, expectations from the upcoming budget reflect the sector's changing needs in a more competitive and digital-first environment.

HOTELS WANT TAX RELIEF AND COST SUPPORT

Hotel operators say that while demand has been strong, profitability continues to face pressure. Rising operating costs, staff shortages and compliance requirements remain major hurdles.Dr Vikram Kamat, Chairman and Managing Director, VITSKAMATS Group, says 2025 has been a positive year in terms of travel and occupancy. "Rising domestic travel, improved occupancy levels, and greater preference for branded hospitality have supported growth," he says.

However, he adds that the sector now needs more focused reforms. "In the Union Budget 2026, we expect rationalisation of GST, incentives for green and tech-enabled hotels, easier access to credit for expansion, and focused skill development," Kamat says. According to him, better infrastructure and promotion of new tourist circuits can help the industry maintain its momentum.BOOST FOR TIER 2 AND TIER 3 MARKETS

Smaller cities and emerging destinations are becoming important growth drivers for hospitality players. Industry leaders believe Budget 2026 can play a role in supporting this shift.Amit Kumar Singh, Founder and Managing Director, OPO Hotels and Resorts, says policy support should focus on regional expansion.

"We expect enhanced tax incentives for hotel infrastructure, especially in Tier 2 and Tier 3 markets, where demand is rising," he says.Singh also calls for a reduction in GST for budget and mid-scale hotels, which he believes would boost domestic travel and improve margins for smaller operators. "Easing credit access for hotel renovations and brownfield conversions can accelerate organised growth," he adds, while stressing the need for better connectivity and digital tourism initiatives.

TCS headcount dips sharply: Why is India's IT sector facing a job crisis

New Delhi.(Agency)

Tata Consultancy Services (TCS) reported a sharp fall in its employee strength for the second quarter in a row, suggesting India's IT job market maybe under pressure again.At the end of Q3 FY26, Tata Consultancy Services said its total headcount stood at 582,163, down by 11,151 employees from 593,314 at the end of the September quarter.

This comes after an even steeper decline in Q2 FY26, when TCS reduced its workforce by 19,755 employees. The company's headcount had fallen from 613,069 in Q1 FY26 to 593,314 in Q2.In just two quarters, TCS has seen its workforce shrink by more than 30,000 employees, sparking questions over whether India's IT sector is facing a deeper and longer job crisis.

GLOBAL SLOWDOWN AND LOWER ATTRITION BEHIND CUTS

Experts say the decline in TCS's headcount reflects a mix of global and domestic factors.Sarthak Sharma, founder of ModxComputers, said the reduction is the result of both temporary and permanent changes in the industry."Tata Consultancy Services' employee reduction is an example of headcount reduction due to a combination of factors, both temporary and permanent," Sharma said.He explained that over the last 12 to 18 months, global companies, especially in the US and Europe, have cut technology spending due to high interest rates and ongoing geopolitical conflicts. These regions account for nearly 70% of India's IT revenue.Sharma added that spending on large digital transformation projects, legacy system upgrades and new technology initiatives has dropped by 15% to 20% across sectors such as banking and finance and retail.At the same time, attrition in Indian IT firms has fallen sharply, from 20% to 22% in FY22 to around 11% to 13% in FY25. "This has created a situation where the demand for replacement hires is very low, resulting in a natural contraction of net employee additions," he said.

SHIFT TOWARDS STRUCTURAL WORKFORCE REDUCTION

According to Sharma, the change in hiring is not limited to IT alone. "Companies are now practising workforce reductions on a structural basis," he said, adding that firms are adopting a permanent approach to reducing headcount rather than treating it as a short-term measure.He said companies are increasingly using automation, new technology and vertical solutions to improve efficiency and remove roles that are no longer required.

Gold, Silver Prices Expected To Remain Volatile This Week; Gold Futures At Rs 1,42,743 Per 10 Grams

New Delhi.(Agency)

Mumbai: Gold and silver prices fell on MCX and global markets on Friday as the US dollar strengthened, following weaker-than-expected weekly jobless claims. Further, a softer tone from US President Donald Trump on Iran reduced safe-haven demand for the precious metals.MCX gold February futures dipped 0.26 per cent to Rs 1,42,743 per 10 grams in morning trade, while MCX silver March futures eased 0.94 per cent to Rs 2,88,824 per kg.Spot gold eased about 0.29 per cent to $4,602.43 an ounce, though it remained around 2 per cent higher for the week. Spot silver fell roughly 0.8 per cent to $91.69 an ounce after earlier touching an all-time high of about $93.57–$93.70 during the session.

Analysts said the pullback came as the dollar index climbed toward 99.49, its strongest level since early December. Market watchers said that rising geopolitical risks stemming from unrest in Iran and tensions involving Venezuela and Greenland continue to provide demand for precious metals.

Gold and silver prices are expected to remain volatile this week amid volatility in the dollar index, ahead of the US Supreme Court decision on tariffs, they added.

The Augmont Bullion report said that silver retreated sharply from its record high of $93 after Trump refrained from announcing new tariffs on critical mineral imports. Instead, he said the US keeps negotiations open with foreign countries to secure supplies and swiftly cut supply-chain risks, while considering import curbs only if talks fail to yield timely results.

The report predicted that traders can witness some profitbooking and retracement, before prices move higher again.

Investors are looking for cues from the US Federal Reserve for a potential easing amid global uncertainty. Softer-than-expected November producer inflation, both headline and core, alongside mild December consumer inflation data, has increased hopes of the US Fed implementing multiple rate cuts later this year.

Amagi Media Labs IPO: Should investors apply

Amagi Media Labs has stepped into the IPO market, drawing attention from investors keen on the fast-growing connected TV and streaming space. With positive brokerage views and steady grey market signals, the key question is whether the issue is worth subscribing to.

New Delhi.(Agency)

Amagi Media Labs has entered the primary market with its initial public offering at a time when investor interest in technology-led businesses remains strong. The IPO has drawn attention due to the company's growing role in connected TV and free ad-supported streaming platforms. Here is a simple and clear look at whether the issue is worth considering.

WHAT IS THE IPO ABOUT?

The Amagi Media Labs IPO is a book-built issue worth Rs 1,788.62 crore. It includes a fresh issue of shares worth Rs 816 crore, while existing investors are selling shares worth Rs 972.62 crore through an offer for sale.The bidding opened on January 13, 2026, and will close on January 16, 2026. The allotment is expected on January 19, with a tentative listing on BSE and NSE on January 21.The price band has been fixed at Rs 343 to Rs 361 per share. Retail investors need to apply for a minimum of 41 shares, which means an investment of Rs 14,801 at the upper end of the band.Grey Market Signals and Listing Expectations

As of January 16, 2026 at 10:35 AM, Amagi Media Labs' IPO GMP stands at Rs 26.5. Based on the upper price band of Rs 361, the stock may list around Rs 387.5, indicating a potential upside of about 7.3%.UNDERSTANDING AMAGI'S BUSINESS

Founded in 2008 and based in Bengaluru, Amagi Media Labs works in cloud-based broadcast and connected TV technology. Simply put, the company helps broadcasters and content owners run and earn money from ad-supported TV channels, especially on FAST platforms such as Pluto TV, Samsung TV Plus and Roku Channel.Amagi offers tools for cloud playout, content scheduling, ad insertion and data analytics. As more viewers move away from traditional television towards streaming, the demand for such services has been rising steadily.

WHAT DO ANALYSTS SAY ABOUT VALUATION AND GROWTH?

Brokerages believe Amagi is entering a stronger phase, especially after turning profitable in the first half of FY26.

Anand Rathi believes the company is well-placed for long-term growth, though the valuation leaves limited room for comfort. The brokerage said, "At the upper price band, the company is valued at 6.7x FY25 P/S, translating into a post-issue market capitalisation of Rs 78,098 million. It has turned profitable in H1 FY26 and, supported by strong operating leverage, is well positioned to deliver full-year profitability in FY26. Continued investments in R&D to enhance scalability, automation, performance, and user experience further reinforce its positioning as the 'industry cloud' for video in the media and entertainment space." Based on this, Anand Rathi has recommended the IPO as a "Subscribe – Long Term".Arihant Capital, on the other hand, sees value mainly from a listing perspective. It said, "Amagi is well positioned to benefit from the continued shift of audiences and advertisers toward connected TV and FAST platforms globally. Its end-to-end, cloud-native platform and AI-driven capabilities are expected to support deeper customer penetration, higher monetisation, and sustained revenue growth." At the upper price band of Rs 361, Arihant Capital values the issue at 6.4 times FY25 sales and has given a "Subscribe for Listing Gains" rating.

Why Pakistan is once again sending drones into India

The UAVs being sent by Pakistan are not the suicide drones that were deployed during the hostilities in May last year. These are mostly small, reconnaissance-oriented drones flying at very low altitudes.

New Delhi.(Agency)

Pakistan's drone provocations are back, even as it recovers from the Operation Sindoor pounding it received eight months ago. Since January 9, multiple Pakistani drones have been spotted across Jammu and Kashmir's border sectors, prompting New Delhi to urge Islamabad to stop the intrusions. However, Pakistan seems to be undeterred as drones were again sighted on Thursday night. But why is Pakistan suddenly sending these drones across the border?Before delving into the possible reasons, it must be noted that the drones being sent by Pakistan are not the kamikaze-class ones that were deployed during the hostilities in May last year.

Kamikaze-class drones, also known as "suicide" drones, are UAVs designed to loiter over an area, search for a suitable target, before carrying out the attack.

SPURT IN PAK DRONE SIGHTINGS

In fact, the drones spotted recently are mostly small, reconnaissance-oriented units. This was mentioned by Army Chief General Upendra Dwivedi during his media briefing on Army Day earlier this week.

The Army chief asserted that Pakistan has been "on notice" over the repeated drone activities, underlining that firm responses would follow any misadventure. The concerns have been relayed to the chief of Pakistan's military operations.General Dwivedi said the drones spotted were "very small" and "come with their lights on". They were not flying at very high altitudes."In the period around January 15 (Army Day) and January 26 (Republic Day), Pakistan usually fears that India may take some action... We have seen small drones that came with their lights on and did not fly very high," the Army chief said.

Since January 9, Pakistan has sent at least 10-12 drones across different sectors along the International Border (IB) and Line of Control (LoC). On Thursday, drones were sighted over Poonch and in the Ramgarh sector of Samba. Previously, Nowshera and Rajouri sectors also witnessed drone activity, prompting the security forces to activate anti-unmanned aerial system (anti-UAS) defences and open fire.

On January 9, a drone from Pakistan is suspected to have dropped two pistols, three magazines, 16 bullets and one grenade in the Samba district. These were recovered by the forces during a search amid intensified vigil ahead of Republic Day celebrations. A suspected Pakistani drone was also sighted above Rajasthan's Jaisalmer on Monday night.

WHY PAKISTAN IS SENDING DRONES

Analysts believe the spurt in drone activities by Pakistan is mainly to probe weaknesses in Indian defences and test India's response times. The rugged terrain and sparse monitoring infrastructure in forward areas along the LoC make drones a vital element for monitoring activities.

"Pakistan is sending Drones for 'Recognition Operation'. Drone that Pakistan sends without payloads is to check the response of India. Pakistan is checking which radar system is activated by India. Checking in which sectors India's army movement increases," geopolitical expert, Sumit Raj, tweeted.It was also echoed by the Army chief, who suggested that the drone incursions were an attempt by Pakistan to check gaps in Indian defences through which they could send terrorists.

"It's possible they wanted to see if there were any gaps, any laxity in the Indian Army, any gaps through which they could send terrorists," General Dwivedi said.He asserted that Pakistan "must have received a negative response". "Pakistan must have seen that as of today, there is no such place, no such gap from where they can send the terrorists," the Army chief said.

ATTEMPT TO DELIVER ARMS?

Former Jammu and Kashmir top cop, SP Vaid, asserted that Pakistan was hell-bent on escalating tensions. He suggested that Pakistan might be trying to deliver arms and drugs through the drones to revive terrorism in the region, where local recruitment has almost stopped.

Anti-Terror Agency Arrests Accused In 2021 CPI Maoist Conspiracy Case

New Delhi.(Agency)

The National Investigation Agency (NIA) on Thursday arrested an absconding accused in a 2021 CPI (Maoist) conspiracy case involving attempts to re-energise the banned terrorist organisation in the Magadh Zone, the agency said in a press release.The accused, identified as Chandan Kumar, was arrested in Mumbai. A resident of district Jehanabad, Bihar, he was an active member of CPI (Maoist) and was involved in raising funds and also encouraging old cadres to rejoin the outfit to carry out acts of terrorism, it said.The NIA Special Court at Ranchi, Jharkhand, had earlier declared Chandan as an absconder and, in October 2023, issued non-bailable arrest warrants against him.

NIA had registered the case RC-05/2021/NIA/RNC suo moto in December 2021 against Pradyuman Sharma - a Special Area Committee Member of CPI(Maoist), along with Yogendra Ravidas, Nagendra Giri - an armed cadre of CPI (Maoist), Abhinav @ Gaurav @ Bittu, and Dhananjay Paswan, an arms supplier for the organisation.

As per NIA investigations, these accused had conspired to revive the CPI (Maoist) in Magadh Zone, and, in furtherance of the conspiracy, had raised funds for procuring arms and ammunition and training the organisation's cadres in the fabrication of IEDs. The funds were raised by the accused through extortion and collection of levy from contractors, and were laundered through various channels, the release said.NIA investigations had further revealed that the accused had also planned to connect with incarcerated Naxals and Over Ground Workers (OGWs) lodged in various jails for commission of terrorist acts as part of their revival agenda. Following its investigation, the agency had chargesheeted the five accused, all members of CPI (Maoist), and had launched a manhunt for Chandan.

Big Supreme Court Setback For Justice Yashwant Varma Over Parliamentary Panel

New Delhi.(Agency)

In a huge setback for Allahabad High Court judge Yashwant Varma, the Supreme Court has dismissed his petition challenging the Lok Sabha Speaker's decision to admit a motion seeking his removal and the legality of the parliamentary panel probing corruption charges against him.A bench of Justices Dipankar Datta and SC Sharma, which had reserved its decision on January 8 on Varma's plea, pronounced the verdict.

On December 16, the Supreme Court decided to examine the petition filed by Justice Varma assailing the action of the Lok Sabha Speaker to "unilaterally" constitute a committee under the Judges (Inquiry) Act to investigate him. Justice Varma, represented by senior advocate Mukul Rohatgi, had said the constitution of the committee under Section 3(2) of the 1968 Act violated both his right to be treated and protected equally by the law. He argued that though notices of motion for removal were given in both Houses of Parliament on the same day, the Speaker constituted the committee unilaterally.

A huge controversy broke out on March 15 last year after firefighters called to Justice Varma's bungalow in Delhi discovered piles of money that had been burnt by a fire. This raised questions about corruption in the highest levels of the judicial system in the country.

While Justice Varma denied any link to the cash and called the allegations against him "preposterous", the top court set up an in-house panel that recommended his impeachment. The panel's report was forwarded to President Droupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi - by then Chief Justice of India Sanjiv Khanna - with the same recommendation. Following this, Justice Varma wrote a petition challenging the top court panel's recommendation to remove him.

Efforts on to increase night shelters to protect homeless amid severe cold: CM Rekha Gupta

New Delhi.(Agency)

Days after Delhi High Court directed authorities to ensure that adequate facilities are provided in night shelters to protect its occupants from the cold, the Delhi government has intensified efforts in expanding night shelter facilities and stepping up rescue operations around major hospitals.

Chief Minister Rekha Gupta said special focus has been placed on areas surrounding AIIMS' Safdarjung and G B Pant Hospital, where a large number of destitute people are often found sleeping in the open. The Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB), along with shelter management agencies, is conducting regular night drives to look for the homeless and move them to shelters. Night shelters are providing essential facilities free of cost, including bedding, three meals a day, sanitation and safe drinking water.

The chief minister stated that under the Winter Action Plan 2025-26, around 250 temporary 'pagoda' night shelters have been established in sensitive and high-footfall areas across the capital to protect from the cold. In addition, DUSIB is operating 197 permanent night shelters across Delhi on a 24×7 basis, all equipped with basic amenities.

She further informed that, besides the existing 32 pagoda night shelters with a capacity of 320 beds in the AIIMS-Safdarjung area, three additional pagoda shelters have been set up, taking the total capacity in the area to 350 beds.

Considering the higher concentration of homeless people around AIIMS and Safdarjung hospitals, temporary shelter arrangements have also been made in subway areas.

Blankets and bedding are being provided immediately to those in need. Under a special drive, around 75 homeless persons were rescued from the AIIMS-Safdarjung area and shifted to safe locations, after which the area was cleared of people sleeping in the open.

Gupta also said that eight temporary 'pagoda' night shelters have been established around GB Pant hospital, providing accommodation for 80 people. Agencies operating the night shelters are conducting regular inspections every night between 10 pm and 4 am to ensure that homeless persons in open and unsafe locations are promptly brought to shelters.

A central control room is functioning round the clock to coordinate these efforts.The CM emphasised that the Delhi government's efforts are not limited to providing shelter alone, and that a city-wide alert and rescue mechanism has been activated.

Delhi government creates over 4K healthcare posts

Health department to hire junior and senior doctors, surgeons, nurses and paramedical staff

New Delhi.(Agency)

The Delhi government has approved the creation of 4,002 new posts across four government hospitals, a move which will enable the full utilisation of recently added beds and ease pressure on overcrowded public health facilities, officials said on Thursday.The proposal, cleared by Lieutenant Governor VK Saxena on the government's recommendation, follows the addition of 1,515 beds in hospitals located throughout the capital.

Officials said these hospitals had expanded their infrastructure but were struggling to function at full capacity because staff strength had not kept pace.

The new posts include doctors, surgeons, senior residents, specialists, nurses, nursing attendants, technicians, paramedical staff, administrative officers, clerical workers and security personnel.Of the total, 3,031 posts will be filled through permanent recruitment, while 971 positions will be outsourced.

The largest allocation, comprising 1,737 posts, has been designated for the Sant Durbal Nath Ji Trauma Centre at Sanjay Gandhi Memorial hospital Mangolpuri, where a 362-bed trauma block was inaugurated in September 2025.

Ambedkar Nagar Hospital will receive 666 additional staff for 400 new beds, while Guru Gobind Singh Hospital will be allotted 1,491 posts to support the addition of 472 beds.The staffing boost covers Guru Gobind Singh Hospital in Raghubir Nagar, Ambedkar Nagar Hospital in Dakshinpuri, Sant Durbal Nath Ji Trauma Centre at Sanjay Gandhi Memorial Hospital in Mangolpuri, and Shri Dada Dev Maitri Avum Shishu Chikitsalaya in Dwarka.Officials said the new appointments will help reduce doctors' workloads, improve patient care, and redirect cases from overburdened central hospitals like GTB, Lok Nayak, and GB Pant. The move will involve an expenditure of about Rs 408 crore, for which budgetary provision has already been made, the officials added.Sources alleged that the previous AAP administration failed to plan manpower alongside infrastructure. Officials said these hospitals remained underutilised for years despite expanded bed capacity due to the absence of sanctioned staff.

Additionally, they highlighted concerns regarding 24 hospitals initiated during the AAP government, citing delays, cost overruns, and corruption, with investigations ongoing.

Jamia to boost campus mental health support via professional counsellors

New Delhi.(Agency)

Jamia Millia Islamia's Mental Health and Wellness Cell (MHWC), inaugurated a year ago, will soon be strengthened with professional counsellors for students, faculty and staff following the signing of a MoU with the Society for Promotion of Youth and Masses (SPYM). The MoU was signed on Thursday by Prof. Md Mahtab Alam Rizvi, Registrar, JMI, and Dr. Rajesh Kumar, Executive Director, SPYM.The collaboration aims to expand mental health services on campus, catering to nearly 29,000 regular students, in addition to faculty and staff. The university also has around 23,000 distance education students and nearly 7,000 school students.The MHWC was established in pursuance of the Supreme Court guidelines issued in the Sukhdeb Saha case on July 25, 2025, highlighting the importance of mental health in educational institutions.

The Cell implements the Students' Mental Health and Wellness Policy, 2025, ensures compliance with directives from the Supreme Court, University Grants Commission, and Ministry of Education, and coordinates mental health initiatives across departments. It also engages with government and non-government mental health programmes, maintains records with the Internal Quality Assurance Cell (IQAC), and prepares a annual calendar of activities.

Chairperson Prof. Zubair Meenai said the MoU marks a significant step forward. "Earlier, faculty members acted as counsellors within a small cell. With this collaboration, SPYM will provide trained counsellors and support gradually extended to teachers and staff," he said.

The MoU will remain valid for five years and may be extended after review, unless modified or terminated by either party.

13 E-Commerce Sites Fined Rs 10 Lakh Each For Illegal Walkie-Talkie Sales

New Delhi.(Agency)

The Central Consumer Protection Authority (CCPA) has initiated suo motu action against e-commerce platforms for listing and selling unauthorised walkie-talkies in violation of the Consumer Protection Act, 2019 and telecom laws, issuing final orders against eight entities and imposing penalties totalling Rs 44 lakh.

Notices were issued to 13 e-commerce entities -- Chimiya, JioMart, Talk Pro, Meesho, MaskMan Toys, TradeIndia, Antriksh Technologies, Vardaanmart, IndiaMart, Meta Platforms Inc. (Facebook Marketplace), Flipkart, Krishna Mart, and Amazon, following the identification of over 16,970 non-compliant product listings across platforms.

The CCPA found that platforms were facilitating the sale of Personal Mobile Radios (PMRs) operating outside the license-exempt frequency band, without Equipment Type Approval (ETA) certification or proper disclosure of licensing requirements.Penalties of Rs 10 lakh and Rs 1 lakh imposed. The authority imposed penalties of Rs 10 lakh each on Meesho, Meta Platforms Inc. (Facebook Marketplace), Flipkart, and Amazon, and Rs 1 lakh each on Chimiya, JioMart, Talk Pro, and MaskMan Toys for violations of consumer rights, misleading advertisements, and unfair trade practices, Consumer Affairs Secretary Nidhi Khare told PTI.

Meesho, Meta, Chimiya, JioMart, and Talk Pro have paid their penalties. Payment from the remaining platforms is awaited, she added.Under existing regulations, license exemption applies only to PMRs operating strictly in the 446.0-446.2 MHz band. Rule 5 of the Use of Low Power and Very Low Power Short Range Radio Frequency Devices Rules, 2018, mandates that manufacturers and sellers must obtain ETA before import, sale, or operation of such devices.

Major violations uncovered On Flipkart, 65,931 units were sold where the frequency range was either left blank or fell outside the exempted range. Another 42,275 units were sold with the correct frequency disclosed. Amazon saw 2,602 units sold between January 2023 and May 2025, with 467 product listings lacking proper frequency or certification details.

Meesho recorded sales of 2,209 units by a single seller alone, with numerous listings failing to disclose ETA certification or frequency specifications. JioMart sold 58 units over two years without clear licensing requirement disclosures, while Facebook Marketplace had 710 listings delisted following CCPA intervention.

In the case of Facebook Marketplace, the CCPA found walkie-talkies were listed without disclosure of licensing requirements, frequency specifications, or ETA/WPC certification.

NEWS BOX

Social media platforms removed 4.7 million accounts after Australia banned them for children

World. (Agency)

Social media companies have revoked access to about 4.7 million accounts identified as belonging to children in Australia since the country banned use of the platforms by those under 16, officials said.

"We stared down everybody who said it couldn't be done, some of the most powerful and rich companies in the world and their supporters," communications minister Anika Wells told reporters on Friday. "Now Australian parents can be confident that their kids can have their childhoods back."The figures, reported to Australia's government by 10 social media platforms, were the first to show the scale of the landmark ban since it was enacted in December over fears about the effects of harmful online environments on young people. The law provoked fraught debates in Australia about technology use, privacy, child safety and mental health and has prompted other countries to consider similar measures.

Officials said the figure was encouraging

Under Australian law, Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube and Twitch face fines of up to 49.5 million Australian dollars ($33.2 million) if they fail to take reasonable steps to remove the accounts of Australian children younger than 16. Messaging services such as WhatsApp and Facebook Messenger are exempt.

To verify age, platforms can either request copies of identification documents, use a third party to apply age estimation technology to an account holder's face, or make inferences from data already available such has how long an account has been held.About 2.5 million Australians are aged between 8 and 15, said the country's eSafety Commissioner Julie Inman Grant, and past estimates suggested 84% of 8- to 12-year-olds held social media accounts. It was not known how many accounts were held across the 10 platforms but Inman Grant said the figure of 4.7 million "deactivated or restricted" was encouraging.

UN Charter not à la carte menu, erosion of international law unfolding in 4K: Guterres

UNITED NATIONS. (Agency)

Asserting that the UN Charter is not "à la carte menu", UN chief denounced nations for brazenly violating international law, saying when leaders "pick and choose" which rules to follow, they undermine global order and set a "perilous" precedent.

As Guterres enters the final year of his tenure as UN Secretary General, he told the 193-member General Assembly on Thursday that he will make every day of 2026 count and remains fully committed and determined to keep working, fighting, and pushing for a better world.Against the backdrop of the recent US military action in Venezuela, the 2022 Russian invasion of Ukraine as well as other geo-political challenges, Guterres said the world is brimming with conflict, impunity, inequality and unpredictability.

"A world marked by self-defeating geopolitical divides...brazen violations of international law...and wholesale cuts in development and humanitarian aid. These forces and more are shaking the foundations of global cooperation and testing the resilience of multilateralism itself," he said.

"That is the paradox of our era: at a time when we need international cooperation the most, we seem to be the least inclined to use it and invest in it. Some seek to put international cooperation on deathwatch. I can assure you: we will not give up," the UN chief said.

Middle East allies in blitz of diplomacy urged Trump to hold off on Iran strikes

London. (Agency)

Several Middle Eastern allies of the United States have urged the Trump administration to hold off on strikes against Iran for the government's deadly crackdown on protesters, according to an Arab diplomat familiar with the matter.Top officials from Egypt, Oman, Saudi Arabia and Qatar have raised concerns in the last 48 hours that a U.S. military intervention would shake the global economy and destabilize an already volatile region, said the diplomat who spoke on condition of anonymity to describe the sensitive conversations.

Oil prices fell on Thursday as the markets appeared to take note of President Donald Trump's shifting tone as a sign that he's leaning away from attacking Iran after days of launching blistering threats at Tehran for its brutal crackdown.Nevertheless, White House press secretary Karoline Leavitt on Thursday maintained that "all options remain on the table" for Trump as he deals with Iran."The truth is only President Trump knows what he's going to do and a very, very small team of advisers are read into his thinking on that," Leavitt said. She added, "He continues to closely monitor the situation on the ground in Iran."The nationwide protests challenging Iran's theocracy appeared increasingly smothered Thursday, a week after authorities shut the country off from the world and escalated a bloody crackdown that activists say has killed at least 2,637 people.The delicate diplomacy from Arab officials comes during a period of rhetorical whiplash from Trump.

Trump, in a matter of a day, went from offering assurances to Iranian citizens that "help is on its way" and urging them to take over their country's institutions to abruptly declaring on Wednesday that he had received information from "very important sources on the other side" that Iran had stopped killing protesters and was not going forward with executions.The Arab officials also urged senior Iranian officials to quickly end the violent repression of protesters. They warned that any Iranian response to a U.S. action against the U.S. or other targets in the region would have significant repercussions for Iran, the diplomat said.

Trump took Machado's medal, but can Nobel Peace Prize be transferred

World. (Agency)

"Wonderful gesture," said US President Donald Trump with a cheek-to-cheek smile as he posed with a Nobel Peace Prize after Venezuela's Opposition leader Maria Corina Machado handed her medal to him at the White House. Trump's smile was telling. The honour has long been his heart's desire, and he has never shied away from openly pitching, almost begging, for it.Machado not only presented the medal to Trump, she left it at the White House, and Trump accepted it openly, calling it a "gesture of mutual respect."This marked the first time in history that a Nobel Peace Prize laureate voluntarily handed over the medal. But can such an award actually be transferred? The Norwegian Nobel Institute had already addressed the issue days before Machado's White House visit.On Sunday, the institute reiterated that the Nobel Peace Prize cannot be transferred, shared, or revoked, following remarks by the Venezuelan opposition leader suggesting she might give her 2025

award to Trump.In a statement, the institute said the decision to award a Nobel Prize is final and permanent, citing the statutes of the Nobel Foundation, which do not allow appeals. It also noted that Nobel Committees do not comment on the actions or statements of laureates after receiving the award, underscoring that "once a Nobel Prize is announced, it cannot be revoked, shared or transferred to others."Once a Nobel Prize is announced, it cannot be revoked, shared or transferred to others. The decision is final and stands for all time," the Norwegian Nobel Committee and the Norwegian Nobel Institute said.

WHY MACHADO GAVE HER PEACE PRIZE TO TRUMP?

Nobel Peace Prize, regarded as the most prestigious of all Nobel prizes, which are given to those who have "conferred the greatest benefit to mankind", was presented to Machado this year. However, she later announced that she would be presenting it to Trump after he captured the country's President Nicolas Maduro.

Machado later said the gift was in recognition of what she called his commitment to the freedom of the Venezuelan people.

"I presented the president of the United States the medal, the Nobel Peace Prize," Machado told reporters after leaving the White House. She said she had done so "as a recognition for his unique commitment with our freedom."In a social media post on Thursday evening, Trump wrote: "Maria presented me with her Nobel Peace Prize for the work I have done. Such a wonderful gesture of mutual respect. Thank you Maria!"

China's Xi Jinping and Canada's Mark Carney seek new chapter in relations

BEIJING. (Agency)

Faced with new global challenges, the leaders of China and Canada pledged Friday to improve relations between their two nations after years of acrimony.Xi Jinping told visiting Prime Minister Mark Carney that he is willing to continue working to improve ties, noting that talks have been underway on restoring and restarting cooperation since the two held an initial meeting in October on the sidelines of a regional economic conference in South Korea."It can be said that our meeting last year opened a new chapter in turning China–Canada relations toward improvement," China's top leader said.

Carney, the first Canadian prime minister to visit China in eight years, said better relations would help improve a global governance system that he described as "under great strain."He called for a new relationship "adapted to new global realities" and cooperation in agriculture, energy and finance.Those new realities reflect in large part the

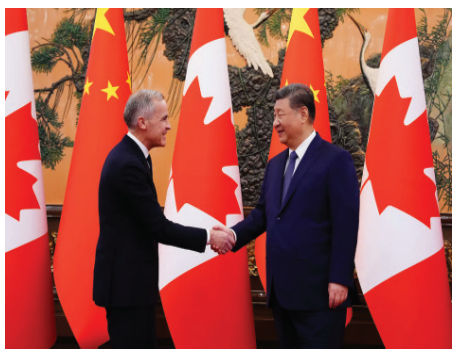

so-called America-first approach of US President Donald Trump. The tariffs he has imposed have hit both the Canadian and Chinese economies. Carney, who has met with several leading Chinese companies in Beijing, said ahead of his trip that his government is focused on building an economy less reliant on the US at what he called "a time of global trade disruption."No announcement was made on tariffs between China and Canada, which is a sticking point in the relationship.Canada followed the US in putting tariffs of 100% on EVs from China and 25% on steel and aluminum under former Prime Minister Justin Trudeau, Carney's predecessor.China responded by imposing duties of 100% on Canadian canola oil and meal and 25% on pork and seafood. It added a 75.8% tariff on canola seeds last August. Collectively, the import taxes effectively closed the Chinese market to Canadian canola, an industry group has said.China is hoping Trump's pressure tactics on allies such as Canada will drive them to pursue a foreign policy that is less aligned with the United States. The US president has suggested Canada could become America's 51st state.

US strikes deal with Taiwan to cut tariffs, boost chip investment

BANGKOK. (Agency)

Taiwan vowed Friday to remain the world's "most important" AI chipmaker, after reaching a trade deal with the United States that will reduce tariffs on the island's shipments and increase Taiwanese investment on US soil.Taiwan is a powerhouse in producing chips -- a critical component in the global economy -- but the United States wants more of the technology made there.The agreement "will drive a massive reshoring of America's semiconductor sector," the US Commerce Department said.Under the deal, Washington will lower tariffs on Taiwanese goods to 15 percent, down from a 20 percent "reciprocal" rate meant to address US trade deficits and practices it deems unfair.Taiwanese Premir Cho Jung-tai praised negotiators Friday for "delivering a well-executed home run" following months of talks."These results underscore that the progress achieved so far has been hard-won," Cho said.Taiwan's dominance of the chip industry has long been seen as a "silicon shield" protecting it from an invasion or blockade by China -- which claims the island is part of its sovereign territory -- and an incentive for the United States to defend it.But the threat of a Chinese attack has fuelled concerns about potential disruptions to global supply chains, increasing pressure for more chip production beyond Taiwan's shores."Based on current planning, Taiwan will still remain the world's most important producer of AI semiconductors, not only for Taiwanese companies, but globally," Taiwanese Economic Affairs Minister Kung Ming-hsin assured reporters on Friday.Production capacity for the advanced chips that power artificial intelligence systems will be split about 85-15 between Taiwan and the United States by 2030 and 80-20 by 2036, he projected.

New, direct investments'

The deal will need to be approved by Taiwan's opposition-controlled parliament where lawmakers have expressed concern about the potential for Taiwan to lose its chip dominance.

Sector-specific tariffs on Taiwanese auto parts, timber, lumber and wood products will also be capped at 15 percent, while generic pharmaceuticals and certain natural resources will face no "reciprocal" duties, the US Commerce Department said.Meanwhile, Taiwanese chip and tech businesses are set to make "new, direct investments totalling at least $250 billion" in the United States to build and expand capacity .

Pak security forces kill 13 terrorists in overnight raids in Khyber Pakhtunkhwa

World. (Agency)

Pakistan's security forces said they struck twice during the night in the country's restive northwest, killing 13 terrorists in separate intelligence-led operations as Islamabad presses. In a statement issued on Thursday, the military's media wing, the Inter-Services Public Relations, said the operations were carried out in Khyber Pakhtunkhwa during the intervening night of January 13 and 14, according to a news agency PTI.

"Thirteen khawarij belonging to Fitna Al Khawarij were killed in two separate engagements in Khyber Pakhtunkhwa province," the Inter-Services Public Relations (ISPR) said, using the term employed by Pakistani authorities for militants of the Tehreek-e-Taliban Pakistan.

SECOND OPERATION IN KURRAM DISTRICT

According to the statement, eight terrorists were killed in an intelligence-based operation in the Bannu district after security forces acted on reports of their presence. In a second operation in the Kurram district, five more terrorists were "neutralised."Sanitisation operations are being conducted to eliminate any other terrorist found in the area," the ISPR said.The latest actions follow another operation earlier this week in Balochistan's Kalat district, where four militants were

killed, underscoring the scale of Pakistan's ongoing counterterror campaign.

Despite sustained military pressure, terrorist violence has surged. A recent report by the Pak Institute for Peace Studies found that terrorist attacks in Pakistan rose 34 percent in 2025, while terrorism-related fatalities increased by 21 percent compared with the previous year.At a press conference last week, ISPR Director General Ahmed Sharif Chaudhry said

Replacing medicines, India giving Pak a bitter pill to swallow in Afghanistan

World. (Agency)

An Afghan blogger, who goes by the name Fazal Afghan on X, wrote about his experience of purchasing some medicines in Afghanistan. He wrote that while he was trying to buy Parol, a brand of paracetamol common in Pakistan and Turkey, he was informed by the pharmacist he could get similar tablets from an Indian pharmaceutical company that would be at least four times cheaper.

He asked for the Turkish-made paracetamol because he trusted its quality. "...It costs 40 Afghanis for a pack of 10 tablets. Then he (the shopkeeper) showed me another option, paracetamol made in India. It was the same quantity, but only 10 Afghanis. He also told me that Indian medicines give better results than the others they sell," Fazal wrote.Enticed by the price, he immediately purchased the Indian tablets, and wrote it cleared up his headache quickly. He then went on to say, "Indian medicines are gradually replacing Pakistani ones in Afghanistan."Pakistan's share is the Afghan pharmaceutical market has shrunk after a series of clashes between the two countries. While the market share was dropping since 2024, after the recent clashes in October-November 2025, Afghanistan's Deputy Prime Minister Abdul Ghani Baradar declared an immediate ban on Pakistani medicines citing their poor quality, and urged traders to look for alternatives from India, Iran and Central Asia.At the same time, Indian pharmaceutical exports to Afghanistan increased rapidly — New Delhi sent medicines worth $108 million to Kabul in FY 2024-25, with reports indicating exports worth $100 million in the rest of 2025.

WHY DID AFGHANISTAN DROP PAKISTANI PHARMACEUTICALS?

Given Afghanistan's geographic location as a landlocked country, and its fragile domestic healthcare industry, the nation has been historically dependent on Pakistan for even the most basic of medical supplies.Before November 2025, Pakistan was Afghanistan's dominant supplier of medicines, benefiting from geographic proximity and low-cost land routes via

Torkham and Chaman.It must be noted that Afghanistan has very little domestic production of pharmaceuticals, and imports 85–96% of its medicines.According to UN COMTRADE data via Trading Economics, Pakistan exported $186.69 million worth of pharmaceuticals to Afghanistan in 2024.Business Recorder estimated 2023 exports at $112.8 million. According to Noorullah Noori, the Taliban's director general for administrative affairs, over 70% of the medicines used in Afghanistan came from Pakistan prior to November 2025.This dependence, which dated back decades, intensified post-2001 due to Afghanistan's war-damaged infrastructure and lack of quality controls and labs, making Pakistani imports the most practical and cost-effective option.

Despite this heavy dependence, following repeated border clashes, the Torkham and Chaman border crossings were closed to Afghan traders last year while Afghanistan's Taliban leadership slapped an outright ban on Pakistani drugs.This led to severe shortages of medicines in the country, with a Deutsche Welle (DW) report noting shortages of antibiotics, insulin and heart medications, with pharmacists charging exorbitant prices or selling counterfeit counterparts.

NEWS BOX

Bangladesh cricketers to end boycott if ex-director issues public apology: Report

New Delhi. (Agency)

Bangladesh's professional cricketers have reportedly drawn a firm line in their ongoing boycott, insisting they will only return to competitive action if former chairman Nazmul Islam issues a public apology for comments he previously made about players.

According to a report by ESPNcricinfo, the players released a statement on Thursday, January 15, escalating tensions with the Bangladesh Cricket Board (BCB). The dispute has already begun to impact domestic cricket, with several matches in both the Bangladesh Premier League and the Dhaka Premier League being called off.While the BCB has removed Islam from his role as chairman, the cricketers are demanding further action, calling for him to be stripped of his position as a board director as well. The ESPNcricinfo report adds that Islam had been prepared to apologise only in a closed-door meeting, a stance that failed to satisfy the players and deepened the standoff.The boycott is being led by Mohammad Mithun, who heads the Cricketers' Welfare Association of Bangladesh (CWAB). The issue remains a key point of friction between the players' body and the board as talks continue behind the scenes.Following discussions with the BCB, CWAB issued a press release stating that the cricketers are prepared to resume participation in BPL matches scheduled for Friday, provided a

public apology is made. The association also said it was willing to allow the board time to follow due process regarding Islam's removal as a director.We welcome the decision to remove BCB director M Nazmul Islam from the board's finance committee," the CWAB said. "Since he has been given a showcause notice and since the BCB has asked for time due to procedural reasons regarding his directorship, we want to give him that time. However, we hope that the process will continue.

Roger Federer returns to Australian Open, beats World No. 12 in tie-breaker

NEW DELHI. (Agency)

Roger Federer delighted fans on Friday at the 2026 Australian Open with a spirited practice session against Casper Ruud on the famed Rod Laver Arena. The Swiss legend - making a highly anticipated return to Melbourne Park for the first time since his retirement in 2022 - took part in a practice tie-break scenario with the Norwegian three-time Grand Slam finalist, giving fans a rare opportunity to see one of the sport's greatest in action once again.Although the session was not part of the competitive tournament, its energy was unmistakable, with spectators filling the arena early and in large numbers to witness Federer's graceful footwork and immaculate shot-making. Those trademark one-handed backhand

returns must have brought memories flooding back for many in attendance.

Federer struck a sublime backhand down-the-line return, much to the delight of the packed Rod Laver Arena. The Swiss great acknowledged the crowd's affection after the shot, offering a wry smile and a wave in response.

Federer's presence in Melbourne this year comes as part of an exhibition event scheduled for Saturday, January 17, the night before the main draw gets under way. Organisers have built a special Opening Ceremony around his return, which will see Federer share the court with fellow legends - including Andre Agassi, Lleyton Hewitt and Pat Rafter - in a celebration match honouring his legacy and the sport's enduring appeal.At 44, Federer continues to captivate audiences, and his practice hit with Ruud reflected his enduring connection to tennis, even in a more relaxed setting.

One year on, Aryna Sabalenka seeks to heal old wounds at the Australian Open

Australian Open 2026: Aryna Sabalenka suffered a shock defeat to Madison Keys in last year's Australian Open final, and the world No. 1 will be eager to reassert her dominance when this year's hard-court showpiece unfolds in Melbourne.

New Delhi. (Agency)

Last year in Melbourne was nothing short of shocking for Aryna Sabalenka. The Australian Open final against Madison Keys left fans stunned and wondering what went wrong. Until that day, Sabalenka had been untouchable — she had won 17 consecutive sets at Melbourne Park and 28 of her last 29 hard-court Slam matches since the start of 2023. The numbers screamed dominance, a force seemingly unstoppable on the hard courts.Yet, on that fateful day, even the world's best was brought crashing down. The heartbreak lingered, a reminder that in tennis, nothing is guaranteed, no matter how commanding the form.Now, it's 2026, and the stage is set again at Melbourne Park. Sabalenka begins her campaign against France's Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, but this time the narrative is different. The mission is no longer just to compete — it's to reclaim her crown, to erase the ghosts of last year, and to remind the world who truly rules the hard courts. Melbourne is ready for her comeback, and so is she.

SABALENKA STARTS 2026 IN STYLE

Sabalenka couldn't have asked for a better start to 2026. After a disappointing end to 2025, where she fell to Elena Rybakina in the WTA Finals, the world No. 1 has roared back into form by claiming the Brisbane International in commanding fashion.

The Belarusian top seed defended her WTA 500 crown with authority, defeating Ukraine's Marta Kostyuk 6-4, 6-3 in the final at Pat Rafter Arena to complete a flawless week without dropping a single set.

The triumph marked her second consecutive Brisbane title and the 22nd singles trophy of her career, moving her past Victoria Azarenka into third place among active players — a clear reflection of her growing dominance on the tour.More than just the silverware, Sabalenka's run in Brisbane carried deeper significance. She produced a

statement straight-sets win over Madison Keys, the 2025 Australian Open champion, in a rematch of last year's Melbourne heartbreak, showing she has well and truly put those scars behind her.

SABALENKA FACES TOUGH CHALLENGE

Reclaiming her throne at Melbourne Park will not come easy, but Sabalenka appears ready for the challenge. The world No.1 has been handed a promising yet intriguing draw at the 2026 Australian Open as she sets out to regain a title she has already lifted twice on the sport's biggest hard-court stage.Sabalenka begins her campaign against French wildcard Rajaonah, a match she enters as the clear favourite but one that could set the tone for her title push. A likely third-round clash with 28th seed Emma Raducanu looms as an early examination, offering a stern test against another powerful hitter capable of unsettling rhythms.Beyond that, the Belarusian's quarter looks manageable on paper. Seventh seed Jasmine Paolini and 14th seed Clara Tauson present potential hurdles in the middle rounds, yet neither boasts Sabalenka's Slam pedigree or recent form. Forecast models back her to progress smoothly through the opening week, reflecting both her top-seed status and her dominant showing in Brisbane.

However, the real battles may await later. With stars like Coco Gauff and Iga witek positioned deeper in the draw, a blockbuster semifinal could be on the horizon. Armed with confidence, power, and belief, Sabalenka arrives in Melbourne ready to chase redemption and legacy.

Vaibhav Suryavanshi's U19 run could hurt him: Ex-India cricketer makes bold statement

NEW DELHI. (Agency)

A debate has emerged around the future pathway of teenage batting prodigy Vaibhav Suryavanshi, after former India cricketer WV Raman questioned whether playing Under-19 cricket would benefit the youngster at this stage of his career.

Raman shared his view on social media, suggesting that while Suryavanshi may dominate at the junior level, the experience could ultimately slow his long-term development given how far he has already progressed."This could be an unpopular opinion. #Suryavanshi has performed extremely well in the A series and the IPL. Making him play at the U-19 level is likely to be detrimental to his growth. He may win matches no doubt, but it should always be about the big picture!" Raman wrote.A rare case outside the conventional pathway

The comments come as the ICC Under-19 World Cup begins, with Australia entering the competition as defending champions. India, five-time winners of the tournament, are once again among the title contenders, with Suryavanshi expected to play a central role in their campaign.At just 14, Suryavanshi's rise has been anything but typical. He has already featured in India A matches and made a strong impression in

the Indian Premier League, achievements rarely seen at such a young age. Picked up by the Rajasthan Royals at 13, he went on to score 252 runs in his debut IPL season at a strike rate above 200, including a record-breaking century that highlighted his explosive potential.His dominance has extended to age-group cricket as well. During the Under-19 Asia Cup, Suryavanshi struck 171 against the UAE and followed it up with a century against South Africa Under-19. He also scored a rapid 96 in a warm-up match ahead of the World Cup, reinforcing his reputation as one of the most destructive young batters in the game.

Selectors have backed his inclusion at the Under-19 level, pointing to the value of structured competition, leadership responsibility, and exposure to high-pressure tournaments. However, Raman's comments have reopened a broader discussion about whether players with exceptional early success should follow customised development paths rather than traditional age-group progression.

As Australia defends their title and India begins another Under-19 World Cup campaign, Suryavanshi's performances will be closely monitored, not only for their impact on results, but for what they reveal about how Indian cricket balances immediate success with long-term vision.

India wants the Olympics, but is it truly ready to host the world

NEW DELHI. (Agency)

Delhi in January is not a new puzzle. Everyone who has lived through winter in the capital knows what comes with it: the dry throat, the scratchy cough, the morning haze that doesn't lift, the air that feels heavier than it should. That familiarity is precisely why the India Open's 2026 flashpoint landed like an accusation, not merely about badminton, but about the way Indian sport keeps mistaking inevitability for planning.On January 15, after a three-game win over HS Prannoy, Singapore's former world champion, Loh Kean Yew, walked into the media area at the Indira Gandhi Indoor Stadium and said what visiting athletes often think but don't always state so plainly. Asked if conditions were an issue, he didn't hedge.

"Yeah, of course. Anyone would. I am surprised you guys (reporters) are okay," he said, before adding a line that travelled far beyond the mixed zone: "I breathe less (laughs). No, I mean I just wear my mask when I can. Other than that, I try to stay indoors as much as possible. But, there's only that much that I can do."Even in a sport that trains players to keep emotion off their faces, Loh kept returning to the same point.How did the body feel at the

start of the season?"It was good in Malaysia until I came here The weather Is not so good."The subtext did not need decoding. You can train for endurance, manage recovery and fine-tune diet, but you cannot condition your lungs to treat hazardous air as a neutral variable.For medical experts, the concern is straightforward. Dr. Lancelot Pinto, consultant pulmonologist and epidemiologist at P. D. Hinduja Hospital & Medical Research Centre in Mumbai, says it is fundamentally unfair to ask athletes to compete in high-intensity sport under such conditions."Intense sports require one to breathe deeply and often cause athletes to hyperventilate," Dr. Pinto said"Both these acts are likely to result in a significant exposure to contaminants in the air, and can have both short- and long-term effects. Elite athletes spend a lot of effort in preserving their health, and it is unfair to expose them to unwarranted risks such as hazardous air quality."

Harleen Deol makes her bat do the talking, bounces back from batter's worst nightmare

New Delhi. (Agency)

Few moments in sport cut deeper than being publicly told you are not good enough in that instant. For a batter, it is the ultimate humiliation. Not being dismissed by the opposition, but by your own team's decision. Harleen Deol experienced that nightmare earlier this week when she was asked to retire herself out for a poor strike rate during a Women's Premier League 2026 clash between the UP Warriorz and the Delhi Capitals in Navi Mumbai.What made the decision sting even more was the context. Deol was just three runs short of a half-century. That milestone, however, mattered little to a management group led by Abhishek Nayar, who chose to pull the plug in search of quicker runs. The call backfired spectacularly. The Warriorz's gamble collapsed, leaving the franchise red-faced and Deol carrying the emotional weight of a decision that would have unsettled even the

strongest minds.When trust is questioned, confidence is testedThere is a clear difference between tactical substitution and public doubt. It is one thing when a lower-order batter is sacrificed for momentum. It is another when a specialist batter, whose role is to score runs and anchor chases, is asked to walk back. The feeling is comparable to a footballer being brought on as a substitute only to be withdrawn again. Rare, brutal, and unforgettable.What followed could have gone in two directions. Deol could have retreated into her shell, burdened by embarrassment and second-guessing every movement at the crease. Or she could respond with clarity, composure, and conviction. She chose the latter.

That response came swiftly and emphatically, against the Mumbai Indians. Harleen has long been known for her vibrant personality off the field, her energy and expressiveness often as visible as her strokeplay. This time, however, there was no outward show. No extra celebration. No statement beyond the scoreboard. She let the bat do the talking.Chasing a demanding target, Deol produced an innings that shifted the narrative entirely. She dismantled the bowling with a fluent and fearless knock of 64 off 39 balls, striking 12 boundaries and guiding the Warriorz home with authority. This time, there was no debate. No questioning of intent.

Royal Challengers Bengaluru look to stay perfect against in-form Gujarat Giants

NEW DELHI. (Agency)

Royal Challengers Bengaluru will look to extend their perfect start to the Women's Premier League 2026 when they take on Gujarat Giants in Navi Mumbai on Friday, January 16.RCB come into the contest with two wins from two matches and a chance to make it three on the bounce to open their league campaign. Gujarat, meanwhile, also have two victories but have played one extra game, with a recent defeat exposing a few areas they will be keen to address. With both sides sitting near the top of the table, the clash shapes up as a key early-season test.RCB's success so far has been built around strong starts and controlled execution. Their top order has done most of the heavy lifting, with Smriti Mandhana and Grace Harris setting the tone, while Nadine de Klerk has shown her ability to finish games under pressure. As a result, the middle order remains largely untested, something that could come into focus if Gujarat manage early breakthroughs.With the ball, RCB have been equally impressive. New recruit Lauren Bell

has stood out with her discipline in the powerplay, consistently building pressure through dot balls, while the supporting cast has given the captain plenty of options across phases.Gujarat Giants, on the other hand, possess a batting line-up capable of matching RCB stroke for stroke. The experience of Beth Mooney, Sophie Devine and captain Ashleigh Gardner provides solidity and firepower through the top and middle. The emergence of Kanika Ahuja at No.3 and Bharti Fulmali as a finisher has further strengthened their batting depth.The concern for Gujarat lies in their bowling, where early wickets have been hard to come by. Renuka Singh Thakur and Kashvee Gautam will need to find a way to contain RCB's aggressive top order if the Giants are to halt their momentum.With both teams boasting match-winners and points at a premium, an absorbing contest is on the cards at DY Patil Stadium.WPL 2026, GG-W vs RCB-W: Head-to-headIt's an even split between the two teams, as they have each won three matches in the six encounters they have had in the WPL so far.WPL 2026, GG-W vs RCB-W: Weather and pitch conditionsClear skies are forecast for the evening, with temperatures around 27 degrees Celsius at the start and expected to dip as the night progresses. Humidity is likely to sit near the 60 per cent mark and rise later, bringing dew into play during the second half. The pitches have begun to wear, offering bowlers some assistance, but the presence of dew is set to heavily influence the toss, with teams expected to prefer bowling first.

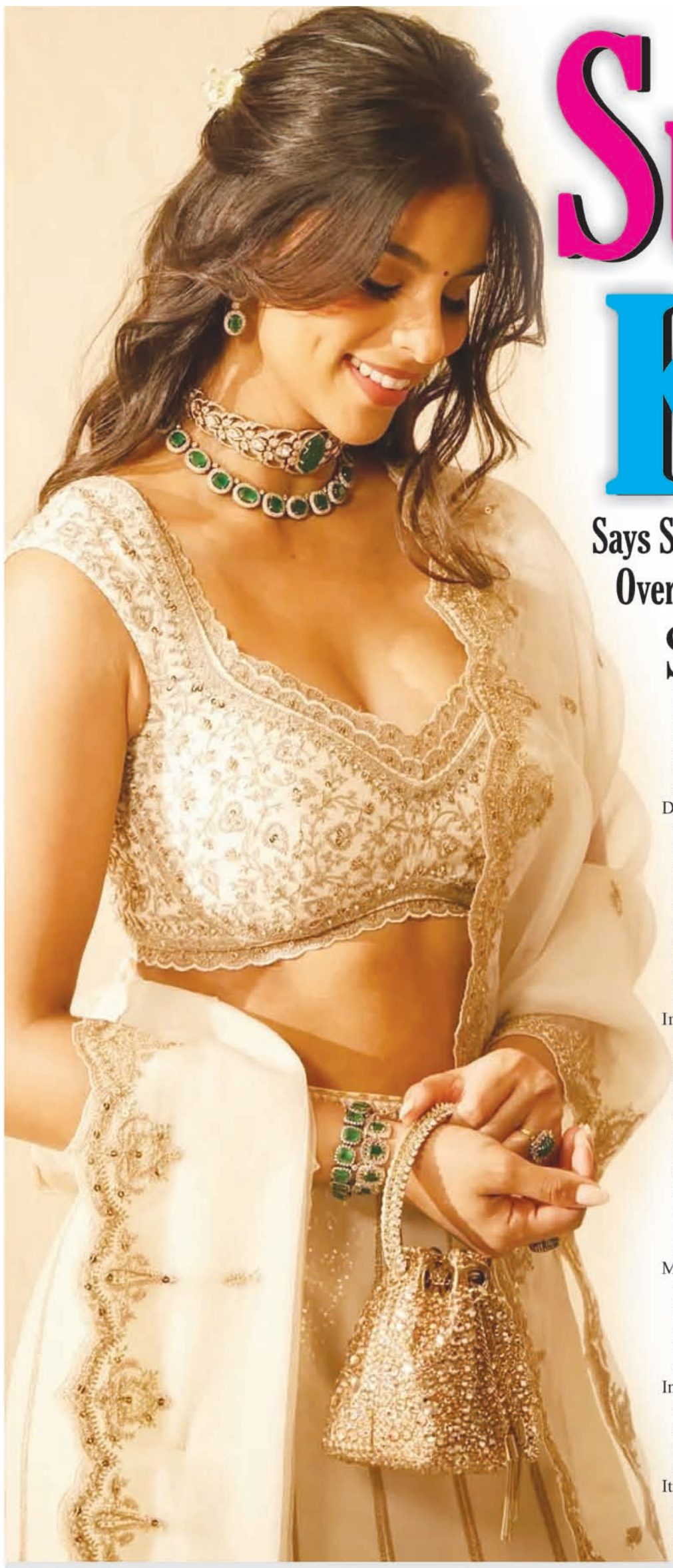

Suhana Khan

Says She'd Rather Be Interesting Than Obsess Over Looks: 'Why Are We Focusing On...'

Shah Rukh Khan's daughter, Suhana Khan, is gearing up for her big screen debut in King. Recently, she indulged in an interesting conversation where she got candid about who she is as a person and how she discovered her passion for acting.When asked to describe herself, Suhana Khan told Harper's Bazaar India, "A homebody who loves being busy." She said that she is both an introvert and an extrovert. Suhana added, "Why are we all focusing on what we look like? There are other important things. Like I'd rather be compassionate, kind, interesting, and fun, and make someone else feel good in my presence than obsess over looks."

Despite being a star kid, Suhana prefers to stay private. She described herself as a deeply sensitive person, and she is proud of her vulnerability. Suhana Khan said, "I try to be a better person every day. I think I'm a kind person and I really take pride in that." Interestingly, many Bollywood stars have spoken highly of Shah Rukh Khan's kindness.

In the same chat, Suhana Khan recalled how she discovered her passion for acting in boarding school. While she grew up with an interest in cinema, boarding school stands out as a distinct memory. She revealed that she once auditioned for a play but got cast in the chorus instead. "I was so upset and disappointed. And I think that's when I knew that I really wanted to play those parts and enjoy the thrill of being on stage," Suhana recalled.

Meanwhile, Suhana Khan is currently gearing up for her next film with her father, Shah Rukh Khan, in King. The action drama, whose teaser was released in 2025, is one of the most-highly awaited films. According to a report by Bollywood Hungama, King is being mounted on an unprecedented budget of ₹350 crore, positioning it among the costliest action films ever produced in India.

Initial reports suggest that when the project was first conceptualised with Suhana Khan in the lead and Sujoy Ghosh as director, the budget was set at around ₹150 crore. However, as the story evolved and Shah Rukh Khan decided to take centre stage, the team realised the potential to mount the film on a much larger canvas.

It was then that Siddharth Anand came on board as director, bringing his flair for scale and adrenaline-fueled storytelling. With his involvement, King transformed into one of the most ambitious ventures ever undertaken by Red Chillies Entertainment and Marflix Pictures.

Faisal Shaikh AKA Faisu Confirmed As Contestant On Reality Show The 50: 'Always Enjoyed Competition'

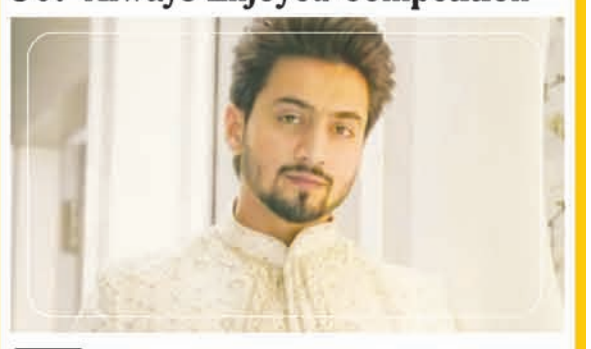

The upcoming reality show The 50 is steadily adding to its lineup, and the latest name to join is digital creator and reality show regular Faisal Shaikh, popularly known as Faisu. The show marks the Indian adaptation of a globally successful format owned by Banijay and is set to stream on JioHotstar while also airing on Colors.

Faisu has built a strong following over the years through social media and multiple reality shows. Known for his calm approach and ability to handle competitive formats, his inclusion adds another familiar face to the mix as the show prepares for its debut. The 50 brings together celebrities and creators in a game focused on strategy, alliances, and staying in the competition.

They welcomed their daughter, Raha Kapoor, on November 6, 2022. While the couple initially chose to keep her away from the public eye, they later introduced her to the paparazzi during the Kapoor family's annual Christmas lunch. Since then, Raha has often been spotted charming photographers with her playful interactions.

Speaking about joining the show, Faisu said, "Having been part of multiple reality shows, I've always enjoyed the thrill of competition and the chance to connect with audiences. The 50 on JioHotstar takes that experience to another level, allowing me to be completely real — my mindset, emotions, and strategies. It's exciting to compete alongside such a diverse mix of celebrities and creators, form genuine bonds, do tasks, and give audiences an entertaining, unfiltered side of me."

Meanwhile, a prominent name in Indian television, Karan Patel, has been confirmed as a contestant as well. He is best known for his impactful performances and outspoken personality. Over the years, he has built a reputation for being candid, competitive, and unafraid to voice his opinions, traits that have consistently kept him in the spotlight, both in fiction and reality formats.With further contestants still being revealed, the show is shaping up as a mix of familiar personalities from different spaces. The format is expected to test not just physical and mental strength, but also decision-making and teamwork. The 50 is scheduled to premiere on 1 February, streaming on JioHotstar and airing on Colors.

Shahid Kapoor Stops To Click Selfie With Fan At Mumbai Airport, Internet Calls Him 'Real Hero'

Fans and celebrities share a delicate bond. One sweet interaction can make a fan's day, while a cold response can turn admiration into absolute disappointment. Shahid Kapoor, however, seems to have mastered this connection.

Spotted at the airport recently as he returned to the city, Shahid patiently interacted with his fan, showing the same humility and warmth that fans love him for.

Shahid's Sweet Gesture Will Melt Your Heart

O'Romeo star Shahid Kapoor was recently spotted returning to Mumbai at the airport. Dressed in a white jacket, blue trousers and beige sneakers, Shahid looked stylish with his new beard look and black glasses. In the paparazzi video, a fan can be seen standing behind Shahid, patiently waiting for a selfie. Noticing him, Shahid called the fan forward, paused to click a selfie and then moved ahead. The sweet gesture showed how much he cares for the people who love and support him.

The internet loved Shahid's gesture and filled the comments section of the video with love. A user said, "This is the reason why he's my favourite." Another one added, "Real hero Shahid Kapoor." A fan remarked, 'Very nice of you, Shahid!" Someone wrote, "Back to his old hairstyle. Jab We Met wale Shahid Kapoor ban jao please!" "Shahid is a good man, he won't object to giving selfies, but try to avoid asking selfies when his family is with him, especially kids."

What's Next For Shahid?

Shahid Kapoor is reuniting with his longtime director, Vishal Bhardwaj, the genius behind hits like Haider and Kaminey. Together, they are bringing an intense and thrilling love story to the big screen with their new film, O Romeo. Perfectly timed for Valentine's Day, the movie is set to release in theatres on February 13 and is backed by producer Sajid Nadiadwala.The film boasts a stellar ensemble cast, including Triptii Dimri, Nana Patekar, Avinash Tiwary, Tamannaah Bhatia, Vikrant Massey, Disha Patani, Farida Jalal and Aruna Irani. With such a powerhouse combination of talent and direction, the film is already generating buzz. The teaser, released a few days ago, has been met with widespread praise.

Katrina Kaif

Calls Rani Mukerji's 'Irreplaceable And Unstoppable', Praises Mardaani 3 Trailer

Katrina Kaif is the recent one to shower praise on Rani Mukerji after the trailer of Mardaani 3 was released. She called the actor "irreplaceable and unstoppable." The actress lauded the intense trailer, which has been receiving an overwhelmingly positive response from other celebrities too.

Taking to her Instagram stories, Katrina Kaif shared the trailer and wrote, "#30Yearsof Queen #RaniMukerji irreplaceable, unstoppable undefinable." Kiara Advani wrote, "30 years. One Rani, Endless power. From timeless grace to fearless Mardaani. She still rules the screen. Can't wait to watch #Mardaani3." Earlier, Kareena Kapoor also shared the trailer, "Dynamite..Rani meri jaan love you always..killing it." Alia Bhatt also wrote, "30 years of unforgettable performances and now one more. Cannot wait to watch Mardaani 3." And guess what? Filmmaker Siddharth Anand has also turned to social media to praise the 'FANTASTIC' trailer. Impressed by the powerful clip, the filmmaker shared the link on X (formerly Twitter) and called it a must-watch. He wrote, "#Mardaani3Trailer is FANTASTIC! Hits you like a bolt of lightning! Rani is GOLD! And Mallika Prasad playing Amma is terrifying! Abhiraj, you've nailed this one! Mohit, what a trailer you've cut, again!! Guys, watch it now!"

Mardaani 3 Trailer

The makers of Rani Mukerji's hard-hitting cop franchise Mardaani have unveiled the trailer of its third instalment, bringing back the actor as the relentless and fearless IPS officer Shivani Shivaji Roy. Staying true to the franchise's uncompromising tone, Mardaani 3 promises another disturbing, socially rooted narrative that places Shivani in the middle of a race against time. This time around, Shivani is seen joining the National Investigation Agency (NIA) and taking charge of a chilling case involving the kidnapping of two young girls. As Shivani digs deeper into the investigation, the case spirals into something far more sinister. The trailer reveals a nationwide human trafficking network run by an elderly woman named Amma, played by Mallika Prasad. Amma is shown buying girls from different parts of the country for ₹10 lakh each, drugging them into unconsciousness, and exploiting them systematically. What initially appears to be a trafficking case soon exposes links to a larger beggar mafia, indicating organised crime operating under the guise of helplessness. One of the most unsettling moments in the trailer shows a rescued girl coughing up blood in a hospital, driving home the physical and emotional brutality inflicted on the victims.